R.N.I. No.HIN/2002/8718 www.aksnews.com M.P./BHOPAL/642/2021-23

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

वर्ष : 20 । अंक : 20
16 से 31 जुलाई 2022
पृष्ठ : 48
मूल्य : 25 रु.

राष्ट्रपति चुनाव
राजनीति का शक्ति परीक्षण

भाजपा की आदिवासी रणनीति से
विपक्ष की एकता टूटी

वोटिंग से पहले ही 2024 की पहली
लड़ाई हार गया विपक्ष

ANU SALES CORPORATION

We Deal in Pathology & Medical Equipment

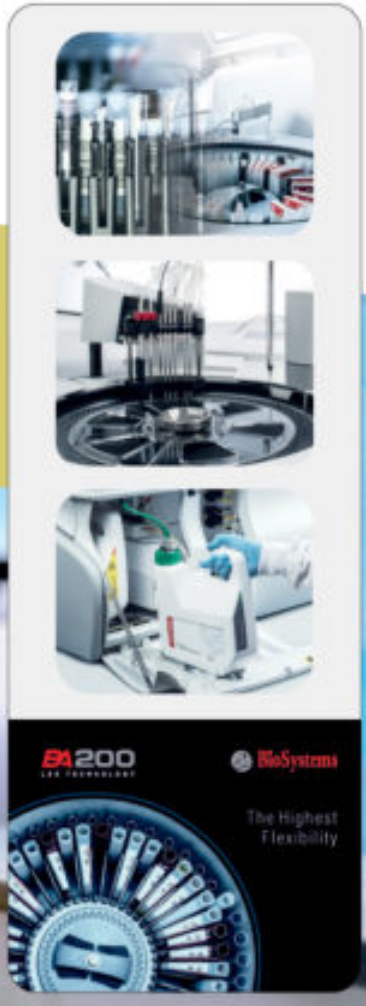

Address : M-179, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023

9329556524, 9329556530 Email : ascbhopal@gmail.com

इस अंक में

राजकाज

8 | माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ाने की...

दिल्ली में विधायकों, मंत्रियों, चीफ व्हिप, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब मप्र के माननीयों के वेतन-भत्ते में बढ़ोतरी की आस जग गई है। इसकी एक वजह यह भी है...

राजपथ

10-11 | 2023 की तस्वीर साफ

मप्र में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं। ऐसे में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने जमकर मेहनत किया है। दोनों पार्टियों...

समस्या

15 | पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारने की कवायद

करीब 12 साल पहले राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, उसके बाद भी आधी राजधानी अब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा से दूर है। करीब 10 लाख लोगों को अपने घर के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दरकार है।

घपला

18 | नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा

मप्र में नर्सिंग कॉलेज संचालन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में लॉ स्टूडेंट्स की याचिका पर आरोप लगाया कि प्रदेश के 453 कॉलेजों की फाइलों में से 37 हजार पेज गायब हैं। याचिकाकर्ता ने निरीक्षण में यह जानकारी कोर्ट को दी। जिस पर हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से...

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि और प्रथम नागरिक होता है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव को सत्तापक्ष और विपक्ष की राजनीति का शक्ति परीक्षण माना जा रहा है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने जहां द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है तो विपक्षी खेमे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उतारा है। प्रत्याशी चयन में ही एनडीए ने जो आदिवासी कार्ड खेला है, उससे विपक्ष दो खेमों में बंट गया है।

राजनीति

30-31 | अब असंसदीय शब्दों पर बैन

संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इस बार संसद में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रंग में नेता दिखेंगे। यानी वे अपशब्द बोलने से कतराएंगे। ऐसा इसलिए कि अब संसद की कार्यवाही से असंसदीय शब्दों को हटा दिया गया है। सबसे बड़ी परेशानी की बात ये है कि...

महाराष्ट्र

34 | विवादों वाली उद्धव सरकार!

महाराष्ट्र में महाविकास अघाडी सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे को जिस सबसे बड़े विवाद का सामना करना पड़ा, वो सुशांत सिंह राजपूत केस था। 14 जून 2020 को सुशांत की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनसे पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की भी संदिग्ध...

बिहार

37 | नीतीश का डोलता मन

राजनीति में समय से ज्यादा संख्याबल बलवान होता है, और कुछ मामलों में परिस्थितियां भी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदर्भ में कुछ ऐसा ही लगता है। अमूमन किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर आई पार्टी को सत्ता...

6 -7 अंदर की बात
40 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

कितनी बार कृष्ण गोवर्धन उठाएं...

किसी कवि ने लिखा है...

कितनी बार कृष्ण गोवर्धन उठाएं।
आखिर इंसान अपनी गलती क्यों दोहराए।।
कहीं सूखा कहीं बाढ़, बन ना सका अबतक एक ढ़ार।।
मौजूद है आज सब साधन, फिर भी विपदा है जलप्लावन।

ये पंक्तियां प्रकृति के कहर की ओर इंगित करती हैं। आज हम अपनी गलतियों के कारण प्रकृति का कोप भुगत रहे हैं। मानसून के इस दौर में जहां मप्र, महाराष्ट्र और गुजरात में बारिश और बाढ़ से लोग तबाह हो रहे हैं, वहीं उप्र, बिहार, झारखंड जैसे राज्यों में सूखा पड़ा हुआ है। बरसात, कुदरत की नियामत है। कहीं कम तो कहीं अधिक। बारिश और बाढ़ ने देश के कई हिस्सों में हाहाकार मचा रखा है। मानसून की शुरुआत से ही देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश, बाढ़, बादल फटने, बिजली गिरने और भू-स्खलन से तबाही का सिलसिला जारी है। पहाड़ों पर आसमानी आफत टूट रही है तो देश के कई इलाके बाढ़ के कहर से त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। असम के बाद गुजरात तथा महाराष्ट्र बाढ़ के प्रकोप से त्रस्त हैं, जहां अब तक काफी संख्या में लोगों को जान गंवानी पड़ी। हालांकि उत्तर भारत के कई इलाके मानसून की बारिश के लिए अब तक तरस रहे हैं। निःसंदेह यह सब पर्यावरण असंतुलन का ही दुष्परिणाम है, जिसके कारण मानसून से होती तबाही की तीव्रता साल दर साल बढ़ रही है। मानसून का मिजाज इस कदर बदल रहा है कि जहां मानसून के दौरान महीने के अधिकांश दिन सूखे निकल जाते हैं, वहीं कुछेक दिनों में ही इतनी बारिश हो जाती है कि लोगों की मुसीबतें कई गुना बढ़ जाती हैं। एक समय था, जब हर कहीं बड़े-बड़े तालाब और गहरे-गहरे कुएं होते थे और पानी अपने आप धीरे-धीरे उनमें समा जाता था, जिससे भूजल स्तर भी बढ़ता था लेकिन अब विकास की अंधी दौड़ में तालाबों की जगह ऊंची-ऊंची इमारतों ने ले ली है। शहर कांक्रीट के जंगल बन गए हैं, अधिकांश जगहों पर कुओं को मिट्टी डालकर भर दिया गया है। दरअसल हमारी फितरत कुछ ऐसी हो गई है कि हम मानसून का भरपूर आनंद तो लेना चाहते हैं किंतु इस मौसम में किसी भी छोटी-बड़ी आपदा के उत्पन्न होने की प्रबल आशंकाओं के बावजूद उससे निपटने की तैयारियां नहीं करते। दरअसल हमारी व्यवस्था का काला सच यही है कि न कहीं कोई जवाबदेह नजर आता है और न ही कहीं कोई जवाबदेही तय करने वाला तंत्र दिखता है। हर प्राकृतिक आपदा के समक्ष उससे बचाव की हमारी समस्त व्यवस्था ताश के पत्तों की भांति ढह जाती है। ऐसी आपदाओं से बचाव तो दूर की कौड़ी है, हम तो मानसून में सामान्य वर्षा होने पर भी बारिश के पानी की निकासी के मामले में साल दर साल फेल साबित हो रहे हैं। देशभर के लगभग तमाम राज्यों में प्रशासन के पास पर्याप्त बजट के बावजूद प्रतिवर्ष छोटे-बड़े नालों की सफाई का काम मानसून से पहले अधूरा रह जाता है, जिसके चलते ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं। अनेक बार ऐसे तथ्य सामने आ चुके हैं, जिनसे पता चलता रहा है कि मानूसन की शुरूआत से पहले ही करोड़ों रुपए का घपला करते हुए केवल कागजों में ही नालों की सफाई का काम पूरा कर दिया जाता है। ऐसे में हम इसकी कल्पना भी कैसे कर सकते हैं कि प्रकृति हमारा साथ दे। दरअसल, हम प्रकृति को तहस-नहस कर रहे हैं और बाकी सब भगवान भरोसे छोड़ रहे हैं। आखिरकार भगवान भी हमें कब तक सहारा देंगे।

- राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 20, अंक 20, पृष्ठ-48, 16 से 31 जुलाई, 2022

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2021-23

ब्यूरो
कोलकाता:- इंद्रकुमार, **छत्तीसगढ़:**- संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, **जयपुर:**- आर.के. बिन्नानी, **लखनऊ :**- मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
098934 77156, (गंजबासौदा) ज्योत्सना अनूप यादव
089823 27267, (रतलाम) सुभाष सोमानी
075666 71111, (विदिशा) मोहित बंसल

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी फोन : 9811017939
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान) मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई, मोबाइल 094241 08015
इंदौर : नवीन रघुवंशी, रघुवंशी कॉलोनी, इंदौर, मो.-9827227000
देवास : जय सिंह, देवास मो.-7000526104, 9907353976

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

aksnews.com

देश में शांति कैसे होगी?

तमाम चीजों से जूझ रहे देश को शांति की ज्यादा जरूरत है वह भी उस स्थिति में जब कई नेता, खासकर कट्टरपंथी धार्मिक गुरु और उलेमा गृह युद्ध की आशंका तक जता रहे हैं। कुछ तालिबानी तत्व भारत में जिस तरह से बढ़ रहे हैं वह बेहद चिंताजनक है।

● **नरेंद्र शर्मा,** सीहोर (म.प्र.)

मेट्रो से होगा फायदा

भोपाल और इंदौर में मेट्रो रेल के साथ हर साल 20 लाख लीटर बरसात के पानी की बचत होगी। इसके लिए एलीवेटेड ट्रैक के नीचे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जा रहे हैं। गर्डर पर बारिश का जितना पानी आएगा वह पाइप के जरिए भूगर्भ में जाएगा।

● **मुजम्मिल हुसैन,** भोपाल (म.प्र.)

महिलाओं की भागीदारी बढ़े

मप्र और तेलंगाना देश के उन राज्यों में शामिल हैं जहां पुलिस में महिलाओं की भागीदारी सबसे कम है। मप्र में 100 में मात्र 6 पुलिसकर्मी महिलाएं हैं, तेलंगाना में 100 में मात्र 5 पुलिसकर्मी महिलाएं हैं। प्रदेश सरकार को महिलाओं की अधिक भर्ती के लिए योजनाएं लानी चाहिए।

● **प्रिया सिंह,** इंदौर (म.प्र.)

क्या लोकतंत्र वाकई खतरे में है?

मप्र और कर्नाटक के बाद अब महाराष्ट्र में जिस तरह सरकार को गिराया गया, इससे लोकतंत्र पर से लोगों का विश्वास उठने लगा है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ उन्हीं के शिवसैनिकों की बगावत और उनको भाजपा का सहयोग मिलना ऑपरेशन लोटस माना जा रहा है। भाजपा भले ही कुछ न कहे, लेकिन विपक्ष खुले तौर पर यह आरोप लगा रहा है कि मप्र, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र में जिस तरह सरकार गिराई गई, वह ऑपरेशन लोटस का ही परिणाम है। महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ उससे बगावत को प्रोत्साहन मिलेगा। चुनाव में जीत आज किसी स्टार्ट-अप को दिए जाने वाले कर्ज के जैसा राजनीतिक कर्ज बन गया है।

● **राजू मकोडिया,** सीहोर (म.प्र.)

नक्सलियों से राहत कब?

मप्र, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ यानि एमएमसी जोन के हॉर्ड कोर नक्सली ही मप्र में सक्रिय होकर अपना नेटवर्क तेजी से फैला रहे हैं। मप्र में इस समय करीब 100 नक्सली सक्रिय हैं। मप्र में बालाघाट नक्सल आंदोलन का अहम केंद्र है, इसलिए यहां नक्सलियों की एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। पहले यहां टांडा और मलाजखंड दलम ही थे, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 6 हो गई है। इनकी मॉनीटरिंग के लिए दो डिविजनल कमेटी बालाघाट में काम कर रही हैं। सरकार को नक्सलियों को पकड़ने तैनाती बढ़ाने की जरूरत है।

● **प्रवीण चौरसिया,** ग्वालियर (म.प्र.)

गांव में सड़कें कहां?

मप्र में सरकारी दावों के अनुसार सड़कों का जाल गांव से लेकर शहर तक बिछा हुआ है। लेकिन हकीकत यह है कि अभी भी लगभग 2,200 गांव में सड़क नहीं पहुंच सकी है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 90,577 किलोमीटर लंबी सड़कें बननी थी। अभी 5 हजार किमी सड़कें बाकी हैं। हालांकि योजना में लगभग 17 हजार करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। राज्य सरकार ने इस साल बजट में 1,250 किमी सड़कों के नवीनीकरण का प्रावधान किया है।

● **राजू मकोडिया,** सीहोर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

राह-ए-नौकरशाह

रामचंद्र प्रसाद सिंह नौकरशाह के नाते भले चतुर सुजान रहे हों पर सियासत में गलत आंकलन कर बैठे। आरसीपी सिंह है उनका चर्चित नाम। इसी हफ्ते केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को मजबूर हो गए। मजबूर किया उनके आका नीतीश कुमार ने। राज्यसभा का कार्यकाल ही खत्म हो गया तो फिर मंत्रिपद कैसे बचता? उप्र कैडर के 1984 बैच के आईएएस आरसीपी सिंह मूल रूप से बिहार के हैं। नीतीश कुमार के जिले नालंदा के तो हैं ही, नीतीश की जाति के हैं। नीतीश कुमार जब केंद्र में रेल मंत्री बने तो कुर्मी होने के नाते बेनी प्रसाद वर्मा ने सिफारिश कर आरसीपी को उनका निजी सचिव बनवा दिया। नीतीश मुख्यमंत्री बने तो आरसीपी उनके प्रधान सचिव बनकर बिहार सरकार में डेपुटेशन पर चले गए। फिर तो नीतीश बाबू के आंख-कान वे ही कहे जाने लगे। नीतीश ने 2010 में राज्यसभा भेज दिया। जल्द आरसीपी सिंह नीतीश के लिए उनके सबसे खास सखा राजीव रंजन सिंह से भी ज्यादा अहम बन गए। पार्टी का अध्यक्ष बनाया तो निहितार्थ निकाले गए कि वही होंगे नीतीश के सियासी वारिस। लेकिन केंद्र में मंत्री बनने के बाद नीतीश के साथ उनके रिश्तों में खटास शुरू हो गई। नीतीश ने पिछले महीने उन्हें जब राज्यसभा का तीसरी बार उम्मीदवार नहीं बनाया तो आरसीपी ने नीतीश पर कटाक्ष करने से भी गुरेज नहीं किया।

सावन में होगा पायलट का अभिषेक

राजस्थान में एक बार फिर नेतृत्व परिवर्तन के कयास लगने शुरू हो गए हैं। इस कयासबाजी को पायलट समर्थक और कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद के ट्वीट से हवा मिलती दिख रही है। दरअसल, इन दिनों सचिन पायलट के समर्थक माने जाने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम का एक ट्वीट भी राज्य की सियासत में चर्चा का विषय बना हुआ है। आचार्य प्रमोद ने ट्वीट कर लिखा- 'विषपान करने वाले नीलकंठ का अभिषेक श्रावण मास में किया जाता है। आचार्य ने ट्वीट कर सचिन पायलट को जहर की तुलना घूंट पीने वाले नीलकंठ से ही नहीं की है बल्कि श्रावण मास में अभिषेक के तौर पर उन्होंने इशारे ही इशारे में कहा है कि अगले कुछ महीनों में राजस्थान में सत्ता की कुर्सी में बदलाव होगा। गौरतलब है कि आचार्य समय-समय पर सचिन पायलट के पक्ष में ट्वीट कर सुर्खियों में आते रहे हैं। इससे पहले भी उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के दौरान मीडिया से बात करते हुए आचार्य प्रमोद ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाने पर खुलकर नाराजगी जताई थी। हालांकि आचार्य प्रमोद कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं हैं। लेकिन उनके ट्वीट से प्रदेश की राजनीति में फिर से सियासी चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है।

काम और इल्जाम

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। चुनाव के पहले जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसी परंपरा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर इन दिनों तरह-तरह की योजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास में व्यस्त हैं। उनकी ओर से की जा रही घोषणाओं को देखकर कांग्रेसी भी रंज खा रहे हैं कि अगर घोषणाओं की रफ्तार यूं ही बढ़ती रही तो पिछली सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की और आचार संहिता लगने से पहले आखिर के छह महीनों में की गई घोषणाओं का भी जयराम रिकार्ड तोड़ देंगे। जबकि उपचुनावों के दौरान की गई घोषणाओं पर कुछ को छोड़कर अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका है। मुख्यमंत्री इन दिनों कहीं भी जाते हैं तो कहीं तहसील, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं बीडीओ ऑफिस तो कहीं उप-तहसील खोलने की घोषणाएं करते जा रहे हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों में भी इसी तरह का चलन है। बड़ा सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि घोषणाएं तो जितनी मर्जी कर लो लेकिन बजट तो कहीं है ही नहीं। पिछली वीरभद्र सिंह सरकार में भी ऐसा ही इल्जाम भाजपा सरकार पर लगाती थी। अब कांग्रेस वही इल्जाम जयराम सरकार के खिलाफ दोहराने पर आ गई है।

संकट में सपा

उप्र में समाजवादी पार्टी संकट में दिख रही है। उसका गठबंधन बिखर रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद महान दल के केशव देव मौर्य ने नाराज होकर सपा से नाता तोड़ा था। चाचा शिवपाल यादव के साथ तो खैर कभी उनका मन ठीक से मिला ही नहीं था। लिहाजा प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को टिकट भी कोई नहीं दिया सपा ने। खुद शिवपाल यादव भी समाजवादी पार्टी के चुनाव निशान से ही लड़े थे विधानसभा चुनाव। चुनाव बाद से खासे मुखर रहे हैं अपने भतीजे के प्रति। अब ओमप्रकाश राजभर रूठ गए हैं। वजह बेटे के लिए एमएलसी की सीट नहीं मिलना है। केशव देव मौर्य की तरह ही राजभर ने भी यही फरमाया है कि सपा ने जयंत चौधरी के रालोद को ज्यादा अहमियत दी है। जबकि रालोद ने 34 सीटें लेकर भी केवल आठ ही जीतीं। सुभासपा ने तो 14 सीटों में 6 जीतकर रालोद से कहीं बेहतर प्रदर्शन किया। तो भी रालोद को राज्यसभा मिल गई, हमें विधानपरिषद सीट भी नहीं दी।

सवालों के घेरे में कांग्रेस

महाराष्ट्र से पहले सरकार पलटने के प्रयोग 2013 में कर्नाटक और 2015 में बिहार में हुए थे। बिहार में महागठबंधन और कर्नाटक में जेडी (एस) के साथ मिलकर कांग्रेस ने भाजपा का रास्ता रोका था। हालांकि 2019 के बाद विपक्षी दलों में संशय की स्थिति बनने लगी। विपक्ष इसके पीछे केंद्रीय जांच एजेंसियों के बेवजह इस्तेमाल का भी दोष लगाता है। लेकिन महाराष्ट्र की असफलता ने कांग्रेस को फिर सवालों के घेरे में खड़ा करने का काम किया है। गौरतलब है कि झारखंड में झामुमो-कांग्रेस गठबंधन को लेकर भी कयासबाजियों के दौर चल रहे हैं। असल में विपक्ष के पास मुद्दों की कमी भी साफ नजर आ रही है। पूर्व में जिन मुद्दों को लेकर विपक्षी दल चुनाव में उतरे थे वह उतने असरदार नहीं रहे। चाहे वह कमजोर अर्थव्यवस्था हो, बदहाल बेरोजगारी या फिर चीन का बढ़ता अतिक्रमण। सिर्फ इतना ही नहीं, कोरोना के समय हुई मुश्किलें, डिमोनेटाइजेशन और कृषि सुधार कानून को लेकर हुए प्रदर्शन का भी चुनाव में बिल्कुल असर देखने को नहीं मिला।

आधे पर अटक गया टारगेट

मप्र में निकाय चुनाव की आचार संहिता हटते ही तबादलों का दौर शुरू होगा। ऐसे में हर अधिकारी इस कोशिश में लगा हुआ है कि उसे मनचाही पदस्थापना मिले। सूत्रों का कहना है कि अफसरों की मंशा को भांपते हुए सरकार ने भी खेल-खेला और नगरीय निकाय चुनाव के दौरान मनचाही पोस्टिंग चाहने वाले अफसरों को महापौर प्रत्याशी के प्रचार-प्रसार के लिए चंदा जुटाने का टारगेट थमा दिया। जितना बड़ा जिला, उतना बड़ा टारगेट अफसरों को थमा दिया। सूत्र बताते हैं कि राजधानी में एक बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाले साहब ने अपनी मनपसंद जिले की कलेक्टरी के लिए 5 करोड़ रुपए जुटाने की बोली लगा दी। बताया जाता है कि साहब ने इसके लिए अपने पदस्थापना वाले विभाग में मातहतों को काम पर लगा दिया और जल्द से जल्द टारगेट पूरा करने को कहा। साहब के आदेश के बाद उनके मातहतों ने शहरवासियों को तरह-तरह की नोटिस भेजकर वसूली का अभियान तेज कर दिया। लेकिन साहब की सारी कोशिश पर उस समय पानी फिर गया, जब महीनों की मेहनत के बाद भी आधा टारगेट ही पूरा हो पाया। अब देखना यह है कि आधा टारगेट पूरा करने वाले साहब को उनकी मंशानुसार जिले की कलेक्टरी मिल पाती है या नहीं। गौरतलब है कि 10-12 वर्ष पुराने ये आईएएस अधिकारी किसी बड़े जिले का कलेक्टर बनने के लिए लंबे समय से जुगाड़ लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक वे उसमें सफल नहीं हो पाए हैं।

अब शुरू होगी राजनीतिक पारी

देश के नौकरशाहों में राजनीति प्रेम दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मप्र में यह खुमारी पहले कम थी, लेकिन अब कई नौकरशाह नौकरी के समय से ही राजनीति की राह बनाने लगते हैं। सूत्र बताते हैं कि राजनीति के चस्के में पड़कर डेढ़ महीने के अंदर दो आईएएस अधिकारियों ने नौकरी का त्याग कर दिया है। इनमें 2014 बैच के प्रमोटी आईएएस रहे एक साहब ने तो नौकरी के दौरान ही अपनी राजनीति की राह आसान कर ली थी और पार्टी के आका से संकेत मिलने के बाद वीआरएस ले लिया। सूत्र बताते हैं कि नौकरी के दौरान ही साहब का झाड़ू से लगाव हो गया था। अब साहब जल्द ही झाड़ू थाम लेंगे। बताया जाता है कि साहब को पार्टी का एडवाइजर बनाने की तैयारी कर ली गई है। साहब पार्टी के एडवाइजर रहने के साथ ही चुनाव भी लड़ेंगे। साहब कहां से चुनाव लड़ेंगे यह तो पता नहीं लेकिन यहां बता दें कि साहब ने नौकरी के दौरान जमकर कमाई की है। इनकी कमाई का आंकलन एक आदिवासी जिले में स्थित इनके रिसोर्ट को देखकर लगाया जा सकता है।

अपने तो अपने होते हैं...

आपने फिल्म अपने का यह गीत तो सुना ही होगा कि 'बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं...' इस बात को प्रदेश की राजनीति के एक कद्दावर नेता और भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी चरितार्थ कर रहे हैं। नेताजी भले ही इन दिनों मप्र की राजनीति में बड़े पद को संभाल रहे हैं, लेकिन वे रहने वाले दक्षिण भारत के एक राज्य के हैं। वहीं भारतीय प्रशासनिक सेवा के उक्त अधिकारी भी दक्षिण भारत के ही हैं। दोनों के राज्य भले ही अलग-अलग हैं, लेकिन पहले ये दोनों राज्य एक ही थे। इस कारण नेताजी और 2009 बैच के आईएएस अधिकारी में घनिष्ठता इस कदर बढ़ गई है कि माननीय का भोजन इन दिनों साहब के घर से ही बनकर आता है। सूत्रों का कहना है कि माननीय जब भी राजधानी में रहते हैं, उन्हें साहब के घर का खाना बराबर मिलता है। बताया जाता है कि जबसे माननीय को प्रदेश की राजनीति में बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, तबसे दक्षिण भारतीय अफसरों की चांदी कटने लगी है। सूत्र बताते हैं कि कई अफसर रात के अंधेरे में माननीय के यहां बैठकें करके अच्छी जगह अपनी पदस्थापना के लिए जुगाड़ लगाते हैं। बताया जाता है कि आने वाले दिनों में कई दक्षिण भारतीय आईएएस और आईपीएस अफसरों के दिन फिरने वाले हैं। माननीय ने भरोसा दिलाया है कि सबकी मनचाही मुराद पूरी होगी। ऐसे में 2009 बैच के आईएएस अधिकारी को भी उम्मीद है कि माननीय नमक का कर्ज अदा करेंगे। यहां यह बता दें कि उनकी पत्नी आईपीएस अफसर हैं।

फर्जी मुकदमों की भरमार

प्रदेश के जिन दो शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की गई है, वहां के अफसरों पर कई तरह के दबाव भी बढ़ गए हैं। एक जिले के अफसर तो राजनीतिक हस्तक्षेप से इस कदर परेशान हो गए हैं कि उनका काम प्रभावित हो रहा है। दरअसल, उक्त जिले के एक माननीय ने तथाकथित तौर पर पूरी पुलिस प्रणाली को हाईजैक कर लिया है। यानी वे जो चाहते हैं, वही करवाते हैं। इसका परिणाम यह हो रहा है कि जिले में फर्जी मुकदमों की बाढ़ आ गई है। माननीय अपना राजनीतिक रसूख दिखाने और विरोधियों पर दबाव बनाने के लिए फर्जी मुकदमे करा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि उक्त जिले के पुलिस कमिश्नर भी माननीय की मनमानी से परेशान हैं। कई बार तो वे दबाव के कारण इतने परेशान हो जाते हैं कि उनके मुंह से निकल जाता है कि जब शहर में एक ही आदमी की चलेगी तो व्यवस्था कैसे सुधरेगी। यहां बता दें कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रधानमंत्री की मंशानुसार दो जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की गई है, ताकि इसकी सफलता का आंकलन कर अन्य जिलों में इसे लागू किया जाए।

क्रीम पोस्ट बचेगी या जाएगी

गांवों की आचार संहिता हटने के बाद अब 20 जुलाई के बाद शहरों की आचार संहिता भी हट जाएगी। इसके साथ ही प्रदेश में तबादलों का दौर शुरू होगा। अपनी मनपसंद जगह पाने के लिए अफसर अभी से जुगाड़ लगाने लगे हैं। ऐसे में सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या पहले से क्रीम पोस्ट पर तैनात मंत्रियों और नेताओं के नाते-रिश्तेदारों की विदाई होगी या उन्हें बदले में कोई और बड़ी जगह दी जाएगी। दरअसल, प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में यह चर्चा इन दिनों जोरों पर है कि तबादले शुरू होते ही मंत्री और नेता अपने-अपने नाते-रिश्तेदारों के लिए अभी से क्रीम पोस्ट की जुगाड़ कर चुके हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के अधिकांश बड़े विभागों और बड़े जिलों में माननीयों के करीबी काबिज हैं। ऐसे में आगामी दिनों में होने वाले प्रशासनिक तबादले देखने लायक होंगे। अब देखना यह है कि कौन मंत्री और कौन नेता अपने नाते-रिश्तेदार को मालदार विभाग या मालदार जिला पुन: दिलाने में कामयाब होता है। वहीं अन्य अधिकारी भी क्रीम पोस्ट के लिए हाथ-पांव मार रहे हैं। किसकी दाल गलेगी समय बताएगा।

माननीयों के वेतन भत्ते बढ़ाने की तैयारी

दिल्ली में विधायकों, मंत्रियों, चीफ व्हिप, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और लीडर ऑफ अपोजिशन के वेतन भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब मप्र के माननीयों के वेतन-भत्ते में बढ़ोतरी की आस जग गई है। इसकी एक वजह यह भी है कि सरकार ने प्रदेश के विधायकों की स्वेच्छानुदान निधि 15 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए कर दी गई है। इसी के तहत उनकी विधायक निधि भी 1.85 करोड़ से बढ़कर 2.50 करोड़ हुई है। इस बढ़ोत्तरी के बाद विधायक वेतन-भत्तों में भी इजाफा चाहते हैं। इसके लिए विधानसभा समिति भी सक्रिय हुई है। हाल ही में इसे लेकर एक बैठक भी हो चुकी है। वेतन-भत्तों को बढ़ाने की अनुशंसा करने से पहले समिति अन्य राज्यों के वेतन भत्तों का अध्ययन करना चाहती है।

1.10 लाख रुपए प्रतिमाह से अधिक वेतन-भत्ता पाने वाले विधायकों को यह राशि कम लग रही है। वे समय-समय पर इसे बढ़ाने की मांग करते रहे हैं। विधानसभा के पिछले सत्रों में भी मांग उठी। हालांकि कमलनाथ सरकार में विधायकों के वेतन-भत्ते को लेकर तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष ने समिति का गठन कर दिया था। यह समिति अपनी अनुशंसाएं विधानसभा अध्यक्ष को सौंप पाती, इसके पहले ही कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई।

सत्ता परिवर्तन के बाद यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। कोरोनाकाल में खजाने की माली हालत खराब होने से यह फाइल बंद रही। अब इस पर सक्रियता बढ़ी है। पिछले दिनों इसे लेकर विधानसभा सचिवालय में बैठक हुई। हालांकि इसे अनौपचारिक बताया गया।

गौरतलब है कि अभी विधायकों को जो वेतनभत्ता मिलता है, उसमें 30 हजार प्रतिमाह वेतन, 35 हजार हर माह निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 10 हजार लेखन सामग्री, डाक भत्ता, 15 हजार प्रतिमाह कम्प्यूटर ऑपरेटर या अर्दली भत्ता, 10 हजार टेलीफोन भत्ता, 10 हजार मेडिकल, नि:शुल्क रेल, हवाई सुविधा आदि शामिल हैं। विधानसभा का मानसून सत्र 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। इस सत्र से विधायकों को उमीद है। दबाव है सत्र के पहले विधानसभा को वेतन भत्ते बढ़ाने संबंधी अनुशंसाएं सौंपें। सदन में किसी विधेयक या अन्य मामलों पर अमूमन सत्ता व विपक्ष में एक राय कम ही बनती है। लेकिन वेतन भत्तों के मामले में सभी एकमत रहते हैं। कर्मियों या अन्य वर्ग को सुविधाएं देने की बात पर खजाने की हालत आड़े आ जाती है।

मप्र सरकार हजारों करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी है। बैठकों और भाषणों में सरकारी खर्चों में कटौती की बात की जाती है, लेकिन फिजूलखर्ची के मामले में सरकार अभी भी पुराने ढर्रे पर ही चल रही है। विधायकों को हर महीने टेलीफोन भत्ते के नाम पर 10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं। यह हास्यास्पद है कि मोबाइल कंपनियां इसके लिए महज 2399 रुपए चार्ज करती हैं, जबकि इसमें इंटरनेट का फ्री अनलिमिटेड डाटा भी मिलता है। बता दें, पहले विधायक बसों से यात्रा करते थे तो उन्हें इसका भी भत्ता मिलता था। लेकिन, बस यात्रा भत्ते को अप्रैल 2016 में खत्म कर दिया। क्योंकि विधायकों ने बस को छोड़कर निजी वाहनों से घूमना शुरू कर दिया था। इसके लिए उन्हें राज्य के अंदर हर 15 किमी पर 1500 रुपए दिए जाने लगे। इसे बाद में बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया।

जानकारी के मुताबिक, 2016 में विधायकों की लॉटरी लग गई। इस साल में विधायकों का वेतन तीन गुना बढ़ाया (10 से 30 हजार रुपए) कर दिया गया। निर्वाचन क्षेत्र का भत्ता भी 25 हजार से बढ़ाकर 35 हजार रुपए किया गया। ये भी गौर करने वाली बात है कि राज्य में विधायकों का वाहन लोन और हाउस लोन बढ़ाए जाने की फाइल दो साल से रुकी पड़ी है।

जानकार बताते हैं कि वर्तमान में कुछ भत्तों की विधायकों को बिलकुल जरूरत नहीं है। जैसे, 2012 में कम्प्यूटर भत्ता 10 हजार था, उसे 2016 में बढ़ाकर 15 हजार करना। विधायक को एक कार्यकाल में पचास हजार रुपए लैपटॉप के लिए मिलना। विधायक को यात्रा भत्ता 15 किमी तक 1500 रुपए राज्य के भीतर और 2500 रुपए राज्य के बाहर मिलना। हर महीने स्टेशनरी एलाउंस 10 हजार रुपए मिलना। इनके अलावा विधायकों को जो अतिरिक्त सुविधाएं मिलती हैं उनमें अनलिमिटेड रेल कूपन, हर महीने राज्य के बाहर अधिकतम 30 हजार रुपए प्रतिमाह मिलना और राज्य के बाहर 15 रुपए प्रति किमी की दर से वाहन भत्ता मिलना शामिल हैं।

विधानसभा के पूर्व अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले पर रिव्यू की जरूरत है। सरकार चाहे तो ये पैसा बचा सकती है। ये भत्ते तब दिए जाते थे जब मंत्रियों और विधायकों का वेतन बहुत कम था। अब सरकार को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए यहां से पैसा बचेगा तो राज्य सरकार बाकी जगह बढ़ रहे टैक्स को कम कर सकती है। सिर्फ टेलीफोन भत्ता ही नहीं, बिजली मद और कैंटीन में मिल रहा सब्सिडाइज भोजन भी खत्म होना चाहिए।

● **कुमार विनोद**

किस राज्य में कितनी सैलरी

देश के सभी राज्यों में विधायकों को अलग-अलग सैलरी मिलती है। इतना ही नहीं हर राज्य में अलग-अलग भत्ते भी दिए जाते हैं। भारत में इस समय सबसे ज्यादा सैलरी तेलंगाना में मिलती है। यहां विधायकों को भत्तों को मिलाकर हर महीने 2.50 लाख रुपए सैलरी मिलती है। हालांकि, तेलंगाना में विधायकों की सैलरी बस 20 हजार है, लेकिन भत्तों के तौर पर हर महीने 2,30,000 रुपए मिलते हैं। वहीं, सबसे कम सैलरी त्रिपुरा में विधायकों को मिलती है। यहां हर महीने 48 हजार रुपए सैलरी मिलती है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी डेटा के मुताबिक, सबसे ज्यादा सैलरी तेलंगाना में मिलती है। इसके अलावा उत्तराखंड में विधायकों को हर महीने 1.98 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा हिमाचल में 1.90 लाख , हरियाणा में 1.55 लाख, बिहार में 1.30 हजार, राजस्थान में 1.42 लाख रुपए, आंध्र में 1,25,000 रुपए, गुजरात में 1,05,000 और उप्र में 95,000 रुपए प्रति महीने सैलरी मिलती है।

बार कोड से नकली शराब पर लगा अंकुश

वित्त वर्ष 2022-23 में आबकारी विभाग ने जो नई आबकारी नीति लागू की है उससे प्रदेश सरकार के राजस्व में बढ़ोत्तरी की संभावना तो बढ़ी ही है, साथ की नकली और अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगा है। दरअसल, आबकारी विभाग ने इस बार सुनियोजित तरीके से तकनीकी का सहारा लेकर माफिया पर तो नकेल कसी ही है, उपभोक्ताओं को भी राहत पहुंचाई है। शराब की खरीदी से लेकर बिक्री तक की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सिक्योरिटी बार कोड का सहारा लिया जा रहा है। इस कोड को स्कैन करते ही यह पता लग जाता है कि शराब कब बनी थी और कब खरीदी गई थी।

शराब के काराबोर को पारदर्शी कर विवादों से मुक्त रखने की यह परिकल्पना आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे की है। वैसे जबसे प्रदेश के आबकारी विभाग की कमान 2002 बैच के आईएएस अधिकारी राजीव चंद्र दुबे के हाथ में आई है, उन्होंने नए-नए नवाचारों से ऐसी प्रणाली शुरू कर दी है, जिससे अवैध और जहरीली शराब पर अंकुश तो लगा ही है, साथ ही व्यवसायियों की समस्याएं भी दूर हो गई हैं। साथ ही शराब निर्माताओं और व्यापारियों की मोनोपॉली भी खत्म हो गई है। गौरतलब है कि प्रदेश में शराब के व्यवसाय को पारदर्शी बनाने के लिए आबकारी विभाग ने ई-आबकारी पोर्टल शुरू किया है। अब इसी पोर्टल के माध्यम से सारा काम होगा। आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने राष्ट्रीय पाक्षिक अक्स से चर्चा में बताया कि पहले शराब का लाइसेंस लेने के लिए शराब व्यवसायियों को आवेदन लेकर घूमना पड़ता था, अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब उन्हें ई-आबकारी पोर्टल पर आवेदन करना पड़ता है। इस प्रक्रिया से भले ही आबकारी विभाग के अफसरों पर बोझ बढ़ा है, लेकिन व्यवसायी खुश हैं। अब उन्हें लाइसेंस के लिए चक्कर लगाने से मुक्ति मिल गई है। यही नहीं विभाग अब शराब कारोबारियों को और सहूलियत देते हुए 1 जून से विदेशी शराब की ऑनलाइन डिमांड की शुरुआत करने जा रहा है। यानी व्यवसायी अपने संस्थान में बैठे-बैठे ही शराब की मांग और आपूर्ति की व्यवस्था कर सकता है। गौरतलब है कि अभी तक देशी शराब के लिए यह व्यवस्था थी।

प्रदेश में शराब के कारोबार को पारदर्शी बनाने के लिए आबकारी विभाग ने ई-आबकारी पोर्टल शुरू किया है, वह शराब कारोबारियों के लिए फायदेमंद होगा। अभी तक शराब कारोबारियों को शराब के लिए वेयरहाउस पर डिपेंड रहना पड़ता था। चौंकाने वाली बात ये है कि सरकारी वेयरहाउस पर ठेकेदारों के कर्मचारियों की लंबी-लंबी लाइन लगी रहती है। माल ट्रक में लोड होता है और सेटिंग से बड़े ठेकेदार लेकर उड़ जाते हैं। छोटे ठेकेदार परेशान होते हैं। डिस्टलरी कंपनी ऑर्डर के बावजूद सप्लाय नहीं कर पा रही है। इसको देखते हुए आबकारी विभाग ने नई व्यवस्था की है। जिसके तहत अब 1 जून से विदेशी शराब ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से कारोबारी ऑर्डर कर सकेंगे। पोर्टल पर अब सभी ब्रांड और उनका स्टॉक नजर आएगा। इससे व्यवसायियों को अपनी मनचाही ब्रांड मिल सकेगी। अभी तक होता यह था कि जब भी शराब कारोबारी वेयरहाउस पहुंचकर अपनी डिमांड रखता था, तो वहां तैनात अधिकारी उसे अपनी पसंद का ब्रांड थमा देते थे। मरता क्या न करता की तर्ज पर कारोबारी को माल लेकर आना पड़ता था।

गौरतलब है कि आबकारी विभाग के अधिकारियों पर ठेकेदारों से साठ-गांठ के आरोप लगते रहे हैं। यह भी आरोप हैं कि वे अवैध शराब की बिक्री को अनदेखा करते हैं। व्यवस्था में सुधार के लिए ई-आबकारी पोर्टल कुछ दिनों में लांच होने वाला है। इस पोर्टल में जिलेवार हर ठेकेदार का अकाउंट व ई-वॉलेट रहेगा। ई-वॉलेट से सारे शुल्क ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। स्थानीय अफसरों के साथ भोपाल व ग्वालियर मुख्यालय के अफसर भी सीधे जानकारी लेते रहेंगे। आबकारी विभाग के अनुसार ई-आबकारी पोर्टल लांच होने वाला है। इससे विभाग की सारी सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी।

सरकार की नई व्यवस्था से अधिकारियों और वेयरहाउस में बैठने वाले लोगों की दादागिरी खत्म हो जाएगी। गौरतलब है कि अभी तक महंगी-महंगी दुकानों का ठेका लेकर शराब कारोबारी खुद को ठगा सा महसूस करते थे। इसकी सबसे बड़ी वजह दुकानों पर शराब की कमी होना है। डिमांड अनुसार वेयरहाउस और डिस्टलरीज से माल सप्लाय नहीं होता था, इस कारण वे परेशान थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। ई-आबकारी पोर्टल पर यह साफ-साफ दिख जाएगा कि वेयरहाउस में शराब है या नहीं।

● **सिद्धार्थ पांडे**

प्रिंट रेट से अधिक पर नहीं बिक रही शराब

प्रदेश में आबकारी विभाग ने ग्राहकों के हितों का ध्यान रखते हुए प्रावधान किया है कि अब एमएसपी से कम और एमआरपी से ज्यादा में शराब की बिक्री नहीं होगी। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद से प्रिंट रेट से अधिक दाम पर शराब बिकने की कोई खबर नहीं है। आबकारी विभाग द्वारा ग्राहकों को जागरूक किया जा रहा है कि वह क्यूआर स्कैन के बाद ही पेमेंट करें। ऐसे में ओवररेटिंग से बचा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश मे अवैध, जहरीली या किसी अन्य प्रदेश से चोरी-छुपे आई शराब की बिक्री पर नकेल कसने के लिए आबकारी विभाग ने शराब की हर बोतल पर बार कोड लागू कर दिया है। इससे कोड स्कैन करते ही पता चल जाएगा कि यह शराब कहां से आई है और कहां के लिए, किस कंपनी से बनी है। अभी बोतल पर सिर्फ होलोग्राम होता है। विभाग का दावा है कि इससे पता चल जाएगा कि शराब असली है या नकली। गौरतलब है कि कई बार ऐसी जानकारी भी मिलती है कि कंपनियां ड्यूटी फ्री शराब बेच रही हैं। कुछ लोग भी इस तरह का धंधा करते हैं। लेकिन अब एक्साइज ड्यूटी के बिना एक बोतल शराब भी नहीं बिक पाएगी।

पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सेमीफाइनल में पास होने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने भरपूर जोर लगाया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नगरीय निकाय चुनावों में जमकर प्रचार किया है। लेकिन निकाय चुनाव के पहले चरण के मतदान ने सभी को निराश किया है। हालांकि पंचायत चुनाव में बंपर वोटिंग कर गांव वालों ने कमाल कर दिखाया है, जबकि शहरों में मलाल सामने आया है।

2023 की तस्वीर साफ

मप्र में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं। ऐसे में अपना जनाधार मजबूत करने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने जमकर मेहनत किया है। दोनों पार्टियों की कोशिश है कि मिशन 2023 से पहले अपने जनाधार का आंकलन किया जाए। पंचायत चुनाव के तीनों चरण में रिकॉर्ड मतदान हुए हैं। इससे ग्रामीण वोटरों के बीच पार्टियों की स्थिति का आंकलन तो हो जाएगा, लेकिन निकाय चुनाव में कम वोटिंग ने पार्टियों का गणित बिगाड़ दिया है। गौरतलब है कि नगरीय निकाय चुनाव में पहले चरण का मतदान काफी फीका रहा। प्रदेश के 44 जिलों के 133 नगरीय निकायों में मतदान 61 फीसदी ही हो पाया। निकाय चुनाव में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं मतदान के मामले में पीछे ही रहीं। राजधानी भोपाल में प्रदेशभर में सबसे कम मतदान हुआ। साल 2014-15 के मुकाबले यहां 16 फीसदी कम वोट पड़े। इससे पार्टियों की चिंताएं बढ़ गई हैं।

गौरतलब है कि लगभग 8 साल बाद पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। भाजपा एवं कांग्रेस जहां आमने-सामने की लड़ाई में हैं, वहीं अनेक सीटों पर बसपा, आप, एआईएमआईएम सहित कई राजनीतिक दल त्रिकोण बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य की मुख्यधारा की राजनीतिक पार्टियां भाजपा एवं कांग्रेस ने पूरा जोर लगाया है। वे इसे 2023 के विधानसभा चुनाव का पूर्वाभ्यास मानकर लड़ रही हैं। चुनावी माहौल में विधानसभा चुनाव के पूर्व के शक्ति प्रदर्शन की ध्वनि गूंज साफ सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां भाजपा प्रत्याशियों के लिए जमकर सभाएं, रैलियां कर रहे हैं वहीं कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन मतदाताओं ने उनकी मंशा पर पानी फेर दिया है। निकाय एवं पंचायत चुनाव भले ही स्थानीय हों पर इनका महत्व कितना है इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है दोनों दलों के वरिष्ठ नेता जी जान से जुटे हैं। वे किनारे रहकर कोई जोखिम लेना नहीं चाहते। कमलनाथ ने तो विधायकों और विधानसभा चुनाव का टिकट चाहने वालों से साफ कह दिया है कि निकाय चुनाव के परिणाम के आधार पर उनका रिपोर्ट कार्ड बनेगा। इसके आधार ही तय होगा कि विधायकों का टिकट बरकरार रहेगा या नहीं। यही कारण है कि विधायक अपने-अपने क्षेत्र में पूरी ताकत से प्रत्याशी के साथ खड़े हैं। हालांकि कई जगह बागी प्रत्याशी दोनों दलों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। इस परेशानी को पहले चरण में पड़े कम वोट ने और बढ़ा दिया है।

नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण में मात्र 61 फीसदी मतदान ने भाजपा की नींद उड़ा दी है। पार्टी ने अधिक से अधिक मतदान के लिए जो फॉर्मूला अपनाया था वह फेल हो गया। यानी 'त्रिदेव' और 'पन्ना प्रमुख' काम नहीं आए। इस कारण 11 नगर निगमों सहित 133 नगरीय निकायों में पिछली बार की अपेक्षा कम मतदान हुआ है। इससे आशंका जताई जा रही है कि भाजपा को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि भाजपा ने अपने 'त्रिदेव' अभियान को लेकर खूब ढिंढोरा पीटा था और प्रत्येक बूथ पर बूथ अध्यक्ष, महामंत्री तथा बीएलए बनाकर उन्हें मतदाता सूची की जांच करने का काम सौंपा था। इसके साथ ही हर मतदाता सूची के 'पन्ना प्रमुख' बनाए गए थे और उनसे कहा था कि मतदाता सूची को ठीक तरह से जांच लें, ताकि मतदान के दौरान किसी

सियासी दलों के समीकरण बिगड़े

मप्र में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में कम मतदान ने सियासी दलों सहित राजनीतिक पंडितों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। हार-जीत का आंकलन और भविष्यवाणी भी गड़बड़ा गई है। कम मतदान में कांग्रेस को अपनी जीत और भाजपा को हार नजर आ रही है। राजनीतिक पंडित अपना गुणा-भाग कर रहे हैं और भाजपा दूसरे चरण में ज्यादा मतदान का भरसक प्रयास करा रही है। 11 नगर निगम सहित 133 नगरीय निकाय चुनाव में कम वोटिंग के बाद अब हार-जीत का आंकलन भी नए सिरे से हो रहा है। कांग्रेस कम मतदान में अपनी जीत की संभावना तलाश रही है। भाजपा भी कम मतदान से घबरा गई है। वो इसके लिए मतदाता सूची और मतदाता पर्ची में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहरा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने मतदान प्रतिशत कम होने पर भी मतदाताओं का आभार जताया है। कमलनाथ ने ट्वीट कर नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण में मतदाताओं के मतदान और कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने की बात कहकर सभी मतदाताओं का आभार व्यक्त किया।

प्रकार की कोई परेशानी न हो। इस अभियान के प्रचार की आड़ में कई नेताओं ने अपने-अपने क्षेत्र की मतदाता सूचियों को लेकर भाजपा संगठन को आश्वस्त किया था कि उनके यहां मतदाता सूची ठीक है, लेकिन 6 जुलाई को जब मतदान हुआ तो उसने त्रिदेव अभियान की पोल खोलकर रख दी। कई मतदाताओं के नाम सूची में नहीं मिले, जो त्रिदेव मतदाताओं की मदद के लिए मतदान केंद्र के बाहर मौजूद थे, वे ही मतदाता सूची से उनके नाम नहीं निकाल पाए। अब भाजपा के बड़े नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि कई नाम बिना बताए ही मतदाता सूची से डिलीट कर दिए गए।

नगरीय निकायों के प्रथम चरण के मतदान में पार्टी का बूथ मैनेजमेंट फॉर्मूला भी बेअसर साबित हुआ। मतदान के एक दिन पहले तक बूथ त्रिदेवों के भरोसे बनाई गई रणनीति भी सफल नहीं हो पाई। मतदान के दौरान त्रिदेव और पन्ना प्रमुख खुद ही चुनाव में व्यस्त होकर बिखरे-बिखरे रहे। इस वजह से पार्टी का मेरा बूथ सबसे मजबूत जैसा नारा महज जुमला ही साबित हुआ। भाजपा संगठन ने वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर जिले में विधायकों को भी तैनात किया था। सभी जिलों में हर बूथ पर पार्टी के पक्ष में 10 फीसदी वोट बढ़ाने का टारगेट रखा था। बड़े शहरों में चुनाव के दौरान सांसद-विधायक इसके लिए डटे भी रहे। इसके बावजूद प्रदेश के सभी जिलों में औसत मतदान प्रतिशत कम ही रहा। बड़े शहरों में तमाम प्रयासों के बावजूद पोलिंग प्रतिशत नहीं बढ़ पाया। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा, हुजूर, उत्तर और मध्य विधानसभा क्षेत्र के मतदान से पार्टी चिंतित है। संगठन इसके लिए अब पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों से पूछताछ भी कर रहा है। भाजपा सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिलों में कई बूथों के त्रिदेव स्वयं अथवा उनके परिजन भी पंचायत अथवा निकाय चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए वे अपने वोटरों को मनाने में व्यस्त रहे। पन्ना प्रमुख भी बिखरे-बिखरे रहे। इसके अलावा बारिश का मौसम, मतदान पर्चियां वितरित न होने और मतदान केंद्र बदल जाने से भी लोगों ने वोट डालने में रूचि नहीं दिखाई। भाजपा के

प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने स्वयं इस मुद्दे पर जिलाध्यक्ष, जिला प्रभारियों और बूथ त्रिदेवों के साथ रूबरू चर्चा कर पूरी रणनीति समझाई थी। लेकिन निकाय पंचायत चुनाव में पार्टी का यह फॉर्मूला विफल साबित हुआ। बूथ अध्यक्ष, महामंत्री और पोलिंग एजेंट्स (त्रिदेव) ने गंभीरता से काम नहीं किया। भाजपा संगठन ने दूसरे चरण के जिलों और 5 नगर निगमों के लिए अभी से विशेष इंतजाम करने को कहा है। नगर निगमों में ग्वालियर, खंडवा, सिंगरौली, बुरहानपुर और छिंदवाड़ा के मतदाताओं ने इस बार चुनाव में ज्यादा रूचि नहीं दिखाई। कहीं-कहीं तो मतदान प्रतिशत 10 फीसदी तक गिर गया है।

भाजपा का प्रदेश में बूथ विस्तारक और त्रिदेव के नाम से शुरू किया गया प्रयोग पहले ही चुनाव में फेल नजर आया। इस प्रयोग का बड़े स्तर पर प्रचार-प्रसार किया गया था और बूथ लेवल तक ट्रेनिंग प्रोग्राम रखे गए थे, लेकिन जिस तरह से मतदाता सूची में गड़बड़ियां सामने आईं, उसने इस अभियान की पोल खोलकर रख दी। भाजपा ने इस साल की शुरुआत में समर्पण निधि अभियान के साथ-साथ बूथ विस्तारक अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत एक-एक वरिष्ठ नेता को बूथ विस्तारक बनाकर बूथ पर भेजा गया था, जहां उसे बूथ की समितियां बनाना थीं और उसे ऑनलाइन पोर्टल पर लोड करना था। बूथ समिति का उद्देश्य उस बूथ के अंतर्गत रहने वाले मतदाताओं की जानकारी रखना था और उनसे लगातार संपर्क में रहना था। उस समय दावे तो खूब किए गए कि अभियान सफल हो गया है। इसके लिए नेताओं ने अपनी पीठ भी थपथपाई। इसके बाद हर बूथ पर त्रिदेव के रूप में अध्यक्ष, महामंत्री और भाजपा की ओर से बीएलए बनाया गया। बूथ पर 20 लोगों की समिति भी तैयार हो गई, जिनका काम ही मतदाता सूची की जांच करना था और मतदाताओं को भाजपा से जोड़ना था, लेकिन इसका परिणाम उलटा हुआ और कई लोगों के नाम सूची से कट गए, जिसकी भनक भाजपा तक को लग नहीं पाई। अब भाजपा इसकी समीक्षा करने की बात कह रही है। समीक्षा के दौरान पदाधिकारियों से सवाल भी किए जाएंगे कि गड़बड़ी आखिर कहां हुई? हालांकि दूसरे चरण में 72 फीसदी मतदान कराकर राज्य निर्वाचन आयोग ने बधाई का काम किया है। लेकिन राजनीतिक पार्टियों के लिए कम मतदान किसी सबक से कम नहीं है। 2023 में अगर इसी प्रकार का मतदान हुआ तो हार-जीत का गणित बिगड़ सकता है। इसलिए पार्टियों को अभी से तैयारी करनी होगी।

● **कुमार राजेन्द्र**

मतदाता-सूची पर अब दोनों दल नाखुश

तमाम मुद्दों पर एक-दूसरे के विरोधी रहने वाले दोनों प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस मतदाता सूची के मुद्दे पर एक होते नजर आ रहे हैं। नगर निगम निर्वाचन की मतदाता सूची में सरकार और भाजपा ने पहले उसकी शिकायतों को राजनीतिक स्वार्थ के चलते खारिज किया। नतीजा सामने है। कांग्रेस ने मतदाता सूची में धांधली का आरोप लगते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने की मांग रख दी है। कांग्रेस के प्रवक्ता और एडवोकेट रवि गुरनानी ने कहा कि मप्र निर्वाचन आयोग ने भी मतदान दिवस से तीन दिन पूर्व मतदाता सूची दुरुस्त करने के आदेश दिए थे जिसका भी पालन रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने नहीं किया। ऐसे दोषी अधिकारियों पर तुरंत आपराधिक प्रकरण दर्ज होना चाहिए। मप्र के निकाय चुनाव के पहले चरण में कम मतदान पर भाजपा के केंद्रीय कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी है। उसके बाद पार्टी के अंदर इसके जवाब तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि आलाकमान ने मप्र को 10 फीसदी वोट शेयर बढ़ाने का टारगेट दिया था। उलटा मतदान घट गया। वहीं मप्र के निकाय चुनाव में भाजपा कम वोटिंग की बड़ी वजह प्रशासनिक स्तर पर जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, सागर और सिंगरौली की प्रशासनिक मशीनरी की विफलता को मान रही है।

नौकरशाहों को देना होगा 11 साल का ब्यौरा

विजिलेंस क्लीयरेंस के लिए जरुरी है आईपीआर भरना

केंद्र सरकार ने आईएएस अधिकारियों के लिए (ए) प्रस्ताव सूची में शामिल करने के उद्देश्य से सतर्कता मंजूरी लेना अनिवार्य किया है। (बी) पैनल में या (सी) में कोई भी प्रतिनियुक्ति, जिसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी आवश्यक है, उस वक्त संबंधित अधिकारी की विजिलेंस क्लीयरेंस देखी जाती है। यदि कोई अधिकारी पिछले वर्ष की अपनी वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न अगले वर्ष की 31 जनवरी तक जमा करने में विफल रहता है, तो उसे सतर्कता मंजूरी से वंचित कर दिया जाएगा। वर्ष 2020 के लिए आईपीआर दाखिल नहीं करने वाले त्रुटिपूर्ण आईएएस अधिकारियों पर कार्रवाई के संबंध में, एआईएस (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 (2) के तहत कार्रवाई करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों को दोषी अधिकारियों की सूची अग्रेषित की गई थी। संबंधित वेतन नियमों में संशोधन के माध्यम से संबंधित एआईएस के अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति प्रदान करने के लिए भी आईपीआर समय पर जमा करना एक अनिवार्य शर्त है।

देश में आईएएस अफसरों के पास कितनी अचल संपत्ति है और वह कहां से मिली है, ये जानकारी उन्हें हर हाल में देनी होगी। अगर किसी आईएएस ने नियमित तौर से अपनी अचल संपत्ति का खुलासा नहीं किया है, तो उसे अब 11 साल का ब्यौरा देना पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने समय सीमा भी निर्धारित की है। दूसरे शब्दों में इसे एकबारगी छूट कहा जा सकता है। जिस विंडो पर आईपीआर भरी जाती है, वह 15 जुलाई से 14 सितंबर तक खुली रहेगी। डीओपीटी ने इस बाबत् सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आग्रह किया है कि वे संबंधित अधिकारियों से तय समय सीमा में आईपीआर भरवाना सुनिश्चित करें।

आईपीआर को लेकर केंद्र सरकार समय-समय पर सख्त आदेश जारी करती रही है। गत वर्ष केंद्र एवं राज्यों में कार्यरत सभी आईएएस अधिकारियों को वह स्रोत भी बताने के लिए कहा गया था, जिसके माध्यम से उसके परिवार के किसी सदस्य ने कोई प्रॉपर्टी ली है। अगर किसी अधिकारी ने परिवार से बाहर के किसी व्यक्ति के नाम पर कोई अचल संपत्ति ली है, तो उसका ब्यौरा भी देना अनिवार्य है। डीओपीटी की एस्टेब्लिशमेंट अफसर एवं अतिरिक्त सचिव दीप्ति उमाशंकर ने दिसंबर 2021 में केंद्र सरकार के सभी सचिवों और सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजकर उक्त जानकारी लेने के लिए कहा था।

इसके बाद भी अनेक आईएएस अफसर ऐसे रहे हैं, जिन्होंने दिसंबर 21 तक अपनी आईपीआर नहीं भरी। देश में 567 आईएएस अधिकारी ऐसे थे, जो अपनी अचल संपत्ति छिपाना चाह रहे थे। इन अधिकारियों ने अचल संपत्ति रिटर्न आईपीआर भरने से गुरेज किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों से आईपीआर दाखिल करने की अपील की थी। इसका भी लोक सेवकों पर कोई असर नहीं हुआ। उसके बाद विजिलेंस कार्रवाई का भय दिखाया गया। यह तरीका भी बेअसर रहा। उस दौरान 32 आईएएस अफसर तो ऐसे रहे हैं, जिन्होंने तीन साल से अधिक समय तक आईपीआर दाखिल नहीं की थी। विभाग से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया था। रिपोर्ट में कहा गया कि बड़ी संख्या में आईएएस अधिकारी हर साल अचल संपत्ति रिटर्न दाखिल नहीं कर रहे हैं। यह बात, प्रणाली में गहरी खराबी की ओर इशारा करती है। इसका यह भी अर्थ है कि लोक सेवकों के लिए विजिलेंस क्लीयरेंस से मना करना अब एक प्रभावी निवारक के रूप में काम नहीं कर रहा है।

विभाग से संबंधित कार्मिक, लोक शिकायत, कानून और न्याय पर संसदीय स्थायी समिति के चेयरमैन सुशील कुमार मोदी द्वारा वह रिपोर्ट संसद के पिछले सत्र में पेश की गई थी। इस कमेटी में लोकसभा व राज्यसभा के 31 सदस्य शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि 567 आईएएस अधिकारियों ने 2018 से 2021 के दौरान आईपीआर जमा नहीं कराई। इस रिपोर्ट को हर साल 31 जनवरी तक जमा कराना जरूरी है। केंद्र सरकार ने कई वर्ष पहले आईपीआर दाखिल करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफार्म तैयार कर दिया था। रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में 135 आईएएस ने आईपीआर जमा नहीं कराई। 2019 में ऐसे अधिकारियों की संख्या 128, 2020 में 146 आईएएस और 2021 में 158 आईएएस ने आईपीआर फाइल करने से पूरी तरह गुरेज किया। खास बात ये है कि सीधी भर्ती से आईएएस में आए अधिकारी भी आईपीआर भरने से बच रहे हैं। दो साल से अधिक समय तक आईपीआर नहीं दाखिल करने वाले अफसरों की संख्या 64 रही है। तीन साल से जिन आईएएस ने आईपीआर नहीं भरी, उनकी संख्या 44 है। तीन साल से अधिक समय तक आईपीआर न भरने वाले भी मौजूद हैं।

संसदीय स्थायी समिति ने जब डीओपीटी से जवाब मांगा, तो रटा-रटाया जवाब दे दिया गया। उसमें नियमों का हवाला दिया गया था। ये नहीं बताया गया कि आईएएस, अपनी अचल संपत्ति को क्यों छिपाना चाहते हैं। संसदीय समिति ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को सिफारिश की है कि सतर्कता मंजूरी से इनकार करने के अलावा अन्य कड़े उपायों को सूचीबद्ध किया जाए। इन उपायों को उन आईएएस अधिकारियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर वार्षिक अचल संपत्ति रिटर्न दाखिल करने में विफल रहते हैं। डीओपीटी ने अपने उत्तर में कहा, अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16(2) के अनुसार, प्रत्येक लोकसेवक के लिए अचल संपत्ति के संबंध में पूर्ण विवरण देना अनिवार्य है। लोक सेवक को विरासत में संपत्ति मिली है, उसके स्वामित्व में है, उसके द्वारा अर्जित की गई है, पट्टे पर है, गिरवी रखी गई है, उसके नाम पर है, परिवार के किसी सदस्य के नाम पर है या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर है, इसका विवरण देना आवश्यक है।

डीओपीटी ने आईपीआर को ऑनलाइन दाखिल करने की सुविधा अप्रैल 2015 से शुरू की थी। जनवरी 2017 को स्थापना अधिकारी एवं अपर सचिव ने डीओ पत्र दिसंबर 2017 को सभी संवर्गों के मुख्य सचिवों को संबोधित करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र से संबंधित सभी आईएएस अधिकारियों को समय पर आईपीआर ऑनलाइन दाखिल करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। इसके बाद, सचिव (पी) ने डीओ पत्र दिनांक दिसंबर 2018, नवंबर 2019 और ईओ और एएस ने पत्र जनवरी 2021 के माध्यम से सभी राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए हैं कि आईएएस अधिकारी निर्धारित समय के अनुसार आईपीआर मॉड्यूल में अपने आईपीआर ऑनलाइन जमा करें।

● **सुनील सिंह**

ई-ऑफिस सिस्टम की सांस फूली

मप्र सरकार द्वारा लोगों को बेहतर और पारदर्शी रूप से योजनाओं का लाभ पहुंचाने व पेपर लैस कार्य की दिशा में सरकारी विभागों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई है। लेकिन स्थिति यह है कि प्रदेश में ई-ऑफिस सिस्टम में भी फाइलें मैन्युअली दौड़ रही हैं। यानी प्रदेश में ई-ऑफिस का सिस्टम फेल हो गया है। गौरतलब है कि ई-ऑफिस को राज्य मंत्रालय से लेकर जिलों और तहसील कार्यालयों तक लागू करने की कोशिश की गई, लेकिन सारे मंसूबे फिलहाल फेल नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने राज्य मंत्रालय में मैन्युअल फाइलों को ट्रैक करने एफएमएमएस एप्लीकेशन बंद करने का फैसला किया है। इसे बंद कर सिर्फ ई-ऑफिस ट्रैकिंग सिस्टम से ही मैन्युअल फाइल्स भी ट्रैक की जाएंगी।

गौरतलब है कि सरकार के बार-बार ताकीद करने के बाद भी नए सिस्टम का क्रियान्वयन नहीं किया गया। इस पर सरकार ने नाराजगी जताई है। इसी कड़ी में 29 जून को फिर से विशेष ट्रेनिंग दी गई, ताकि ई-ऑफिस के ट्रैकिंग सिस्टम को अपनाकर लागू किया जा सके। इसके अलावा जिलों के मैन्युअल फाइल सिस्टम की स्थिति भी ठीक नहीं है। खासतौर पर आचार संहिता लागू होने के बाद ई-ऑफिस की बजाय मैन्युअल फाइलिंग बढ़ गई है। इसलिए भी सख्ती करने की तैयारी है। गौरतलब है कि सरकार ने ई-ऑफिस सिस्टम सबसे पहले राज्य मंत्रालय में लागू किया था। इसके तहत मैन्युअल फाइल को धीरे-धीरे बंद कर ई-फॉर्मेट की फाइलिंग करनी थी। लेकिन यह पूरी तरह नहीं अपनाया गया। कुछ विभाग ही 80 प्रतिशत तक ई-फाइलिंग कर रहे हैं। बाकी विभाग महज 10 से 20 फीसदी तक ही ई-फाइलिंग हो रही है। पुरानी एफएमएमएस एप्लीकेशन बंद की जा रही है। इसकी ट्रेनिंग भी दी गई।

दिलचस्प ये कि प्रदेश में ई-ऑफिस का पेपरलैस सिस्टम लागू करने के प्रयास करीब 12 साल से हो रहे हैं, लेकिन अब तक यह पूरी तरह साकार नहीं हो सका। सबसे पहले 2007-08 में पेपरलैस वर्किंग के लिए ई-ऑफिस का सिस्टम लागू करने के प्रयास हुए थे। तब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही थे। इसके बाद 2017 में शिवराज ने ही वापस इसे लागू करने के कदम उठाए। इसके बाद 2018 में विधानसभा चुनाव आ गए, तो यह सिस्टम ठप हो गया। फिर कांग्रेस की कमलनाथ सरकार आई, तो 2019 के मध्य में वापस इसे गंभीरता से लागू करने के कदम उठे। पूरी गाइडलाइन तक जारी की गई, लेकिन मामला परवान नहीं चढ़ सका। बाद में सत्ता परिवर्तन हुआ, तो फिर शिवराज सरकार आ गई। इस बार फिर शिवराज सरकार ने मई 2020 और फिर जनवरी 2021 में इसे लागू करने सख्ती दिखाई, लेकिन अब भी यह पूरी तरह लागू नहीं हो पाया है। 7 मार्च व 28 मार्च 2022 को ई-ऑफिस सिस्टम से ही मैन्युअल फाइल ट्रैकिंग सिस्टम को लागू करना तय किया। 26 अप्रैल 2022 को मैन्युअल फाइल ट्रेकिंग के लिए एफएमएमएस एप्लीकेशन बंद करने के निर्देश दिया गया। 23 जून 2022 को एफएमएमएस एप्लीकेशन बंद न करने पर नाराजगी जताई। अब एफएमएमएस एप्लीकेशन बंद करके केवल ई-ऑफिस एप्लीकेशन से ही फाइल ट्रेकिंग होगी।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने 2007-08 में विभागों को पेपरलेस करने के लिए ई-ऑफिस सिस्टम लागू किया था, ताकि सरकारी योजनाओं को लेकर होने वाली परेशानियों का समाधान हो और सिस्टम में पारदर्शिता आए। लेकिन 12 साल बीत जाने के बाद भी अभी भी फाइलें चपरासी और क्लर्कों के हाथ भेजी जा रही हैं। ई-ऑफिस को राज्य मंत्रालय से लेकर जिला और तहसील कार्यालय में लागू करने की कोशिश की गई, जबकि सारी कोशिशें फेल साबित हो रही हैं। वहीं मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल, देश की पहली बिजली वितरण कंपनी बन गई है, जिसमें पूरे कंपनी कार्यक्षेत्र के कॉर्पोरेट से लेकर मैदानी दफ्तरों तक ई-ऑफिस सिस्टम के तहत काम करना शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, कंपनी ने निर्णय लिया है कि अब से एनआईसी ई-ऑफिस सिस्टम के जरिए ही ई-फाइल और लेटर भेजे जाएंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ई-ऑफिस प्रणाली लागू करने पर पूरे स्टाफ को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि इससे कोरोना संक्रमण के दौरान उपभोक्ताओं को घर बैठे सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में एक दर्जन से भी अधिक आईटी के ऐसे कई प्रयोग लागू किए, जो कि देश के पावर सेक्टर में एक मिसाल बन गए हैं। इन ई-अनुप्रयोगों से अब उच्च दाब से लेकर निम्न दाब, कृषि उपभोक्ता, गैर घरेलू उपभोक्ता और अन्य श्रेणी के सभी उपभोक्ताओं को ऑनलाइन आवेदन करने पर कनेक्शन उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

● राजेश बोरकर

अब भी नहीं हुआ पेपरलैस सिस्टम

प्रदेश के सरकारी विभागों में पेपरलैस सिस्टम लागू करने के जितने भी प्रयास हुए हैं वे असफल रहे हैं। अक्टूबर 2019 तक सभी विभागाध्यक्ष कार्यालयों में लागू होना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। आधे से ज्यादा कार्यालयों में अब तक लागू नहीं किया गया। वहीं मंत्रालय स्तर पर भी ई-ऑफिस पूरी तरह सफल नहीं हो पाया। मुख्यमंत्री सचिवालय, जीएडी, स्कूल शिक्षा, आईटी सहित कुछ विभाग जरूर ई-ऑफिस का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन बाकी विभागों में मैन्युअल फाइलिंग ही ज्यादा है। मंत्रालय में डाक को लेकर भी एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना दिया है। वहां ई-फाइलिंग हो जाती है, फिर भी मैन्युअल डाक पहुंचती है। इसे लेकर भी दिक्कतें हैं। पीएस व सचिव स्तर पर सुविधा के हिसाब से ई-फाइलिंग हैं। वहीं जिलों व संभाग से आने वाली फाइलों को भी ई-फार्मेट में ही भेजना तय किया गया था। इसके अलावा मैन्युअल फाइलिंग खत्म करने की डेडलाइन तय की गई, लेकिन ई-फार्मेट के साथ हर फाइल की अभी मैन्युअल फाइलिंग भी हो रही है। इससे जिलों व संभाग स्तर पर सरकारी कार्यालयों में भी ई-ऑफिस सिस्टम अधूरा है। इसमें ट्रेकिंग सिस्टम इसलिए असरदार नहीं हो पाया है।

हम ही हैं यहां के थानेदार...

कार्रवाई तो हम अपने हिसाब से ही करेंगे

सूत्रों का कहना है कि एक तो चोरी और ऊपर से सीना जोरी करने वाले नेताओं ने अपने विरोध को इज्जत का मुद्दा बना लिया और वे इस पर अड़े रहे कि हर हाल में मोनू गोहिल पर केस दर्ज होना चाहिए। बताया जाता है कि सत्तारूढ़ पार्टी के माननीय के दबाव में पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया, लेकिन यह भी संकेत दे दिया कि आप लोग के कहने पर हम केस तो दर्ज कर ले रहे हैं, लेकिन जांच अपने हिसाब से करेंगे। यह इस बात का संकेत है कि राजधानी में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भी पुलिस किस हद तक राजनीतिक दबाव में काम करने को मजबूर हो रही है।

भोपाल और इंदौर में जब पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू हुई तो आम जनता को लगा था कि अपराधों के साथ ही तमाम तरह की परेशानियों से निजात मिलेगी। लेकिन अपराध पर अंकुश लगना तो दूर व्यवस्था पहले से भी बदहाल नजर आ रही है। आलम यह है कि राजधानी में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के बाद भी नेताओं की ही चल रही है। शहर में इन दिनों एक नेताजी की तो तूती इस कदर बोल रही है कि वे अपने आपको राजधानी का 'थानेदार' समझने लगे हैं। यानी अपने आपको शासन-प्रशासन में सबसे ऊपर समझने लगे हैं।

माननीय का रसूख राजधानी में इस कदर बढ़ रहा है कि वे मनमाने तरीके से पुलिस अफसरों के तबादले तो करा ही रहे हैं, थानों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। यही नहीं अपने विरोधियों और प्रतिद्वंदियों पर नकेल कसने के लिए झूठे केस भी लगवा रहे हैं। अभी हाल ही में दो ऐसे मामले सामने आए हैं, जिससे माननीय की मनमानी की चर्चा प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक वीथिका में खूब हो रही है। अभी हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव के दौरान माननीय की दादागिरी देखने को मिली। दरअसल, 6 जुलाई को भाजपा के कुछ नेता हबीबगंज थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई कि एसयूवी में सवार इन भाजपा नेताओं पर वार्ड 45 की प्रत्याशी के पति समेत उनके समर्थकों ने हमला कर दिया। इस हमले में भाजपा नेताओं से मारपीट की गई। उनकी कार में जमकर तोड़फोड़ कर तलवारें लहराई गई। घटना के बाद सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना परिसर में धरना-प्रर्दशन किया। बाद में पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया। जबकि हकीकत कुछ अलग थी।

इस मामले में एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि शैतान सिंह चौराहा शाहपुरा निवासी धर्मेंद्र सिंह पाल जो भाजपा के अरेरा मंडल के उपाध्यक्ष हैं वे पूर्व जिला महामंत्री सुनील पांडे, साथी तजिंदर सिंह के साथ भीम दुबे की एसयूवी से छह नंबर स्थित मतदान केंद्र पहुंचते हैं और वहां के मतदाता न होते हुए भी वे मतदान केंद्र के अंदर घुसते हैं और मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान वहां के मतदाताओं और वार्ड 45 से निर्दलीय प्रत्याशी के पति मोनू गोहल के समर्थक इसका विरोध करने लगते हैं। विरोध और नारेबाजी को देखते हुए ये लोग मतदान केंद्र से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी की ओर बढ़ जाते हैं। इस दौरान लोग उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हैं। इस दौरान जब कार दूर निकल जाती है तो एक-दो लोग उस पर पत्थर फेंकते हैं। बस इसी को मुद्दा बनाकर भाजपा नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ थाने पहुंचकर मोनू गोहल के खिलाफ मनमानी धाराओं में केस दर्ज करवाते हैं। बताया जाता है कि पुलिसवाले हकीकत को जानते हुए केस दर्ज करने को तैयार नहीं थे, लेकिन माननीय के दबाव में उन्हें केस करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

उधर, नगर निगम भोपाल से वार्ड नंबर 45 के निर्दलीय पार्षद रहे मोनू गोहल ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेताओं द्वारा होने जा रहे मतगणना में धांधली और मनमानी करने के लिए विरोधियों पर झूठा प्रकरण दर्ज कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी शिखा गोहल ने वार्ड 45 से पार्षद पद हेतु भाजपा की टिकट मांगी थी, किंतु टिकट नहीं मिलने पर निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी। मतदान के दिन तक भाजपा के कई नेता मैदान से हटने के लिए उन्हें डराते धमकाते रहे किंतु वे अंत तक चुनाव मैदान में डटे रहे और पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा। मतदान के दिन अंकुर स्कूल मतदान केंद्र में भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों द्वारा फर्जी मतदान का प्रयास किया गया किंतु मेरे समर्थकों द्वारा इसे पूरी ताकत के साथ रोका गया और उसका वीडियो भी बनाया गया।

विरोध करने के बाद फर्जी मतदान करा रहे लोग फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर भाग गए। लेकिन पुलिस ने उनके ऊपर कारवाई करने के स्थान पर भाजपा नेताओं के दबाव में मेरे और मेरे दो समर्थकों के विरूद्ध हबीबगंज थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि मुझे और मेरे समर्थकों को मतगणना के कार्य से पृथक रखा जा सके और भाजपा के समर्थक अपनी मनमानी और धांधली करके चुनाव परिणाम को प्रभावित कर सके। उन्होंने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।

इससे पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव मनोज शुक्ला पर साइबर क्राइम ब्रांच ने आईटी एक्ट एवं अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। शुक्ला ने तथाकथित रूप से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर नरेला भाजपा महामाई मंडल के मंडल अध्यक्ष आनंद अग्रवाल एवं कार्यकर्ताओं का वीडियो वायरल किया था। इस वीडियो में जो लोग दिख रहे हैं वह ताश के पत्ते, नकद राशि एवं शराब के साथ बैठे हुए हैं। वीडियो में वे एक-दूसरे से बातें भी करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव मनोज शुक्ला ने सोशल मीडिया पर वीडियो को वायरल करते हुए यह दावा किया था कि अग्रवाल खुलेआम शराब एवं जुएं की प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्हें स्थानीय विधायक का समर्थन है। इसके बाद भाजपा ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की शिकायत पुलिस से की। क्राइम ब्रांच ने आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की है। इधर शुक्ला ने आरोप लगाया कि उन पर राजनीतिक दबाव निर्मित करने के लिए इससे पहले भी अशोका गार्डन एवं निशातपुरा थाना क्षेत्र में मामले दर्ज किए गए हैं। वह विधानसभा क्षेत्र में हो रहे भ्रष्टाचार एवं बिगड़ी कानून व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं जिसके चलते उन्हें जानबूझकर मुकदमों में घसीटा जा रहा है।

● **बृजेश साहू**

पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारने की कवायद

करीब 12 साल पहले राजधानी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देने के लिए 400 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, उसके बाद भी आधी राजधानी अब भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा से दूर है। करीब 10 लाख लोगों को अपने घर के पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट की दरकार है। इसको देखते हुए एक बार फिर से पूरे शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधारने की कवायद की जा रही है। इसके तहत 402 करोड़ रुपए की योजना बनाई गई है। इसके तहत 5 साल में 1000 बसें खरीदी जाएंगी।

शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जिम्मा संभालने वाली भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड (बीसीएलएल) ने शहर में करीब दो दर्जन रूट तय कर यहां बस सुविधा दे रखी है। फिर भी शहर की लगभग आधी आबादी को पब्लिक ट्रांस्पोर्ट का लाभ नहीं मिल पा रहा है। गौरतलब है कि बीसीएलएल ने 2010 से ही लो-फ्लोर बसों के माध्यम से शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का नया सिलसिला शुरू किया था। बीते 12 साल में करीब 350 से अधिक बसों को रूट्स पर उतारा। 2011 से 2013 के बीच 220 करोड़ रुपए की लागत से 225 बसें शहर की सड़कों पर उतारी। इसके बाद 2017 को मिडी बसों के तौर पर 102 बसें फिर संचालित की गई। ऐसे में शहर के हर क्षेत्र तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की पहुंच बनाने के लिए 400 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया जाएगा। इसके लिए एक हजार नई बस खरीदी जाएंगी। इसमें 300 सीएनजी बस होंगी। कुछ बस चलना भी शुरू हो गई हैं। साथ ही अंदरूनी मार्गों को जोड़ने के लिए फीडर सेवा शुरू की जाएगी। ई-बाइक और रिक्शा यहां चलाए जाएंगे। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड ने करीब एक दशक पहले लाल बसों के संचालन की शुरुआत की थी। वर्ष 2014 की स्थिति में 225 बस चलाई जा रही थी। इसमें 20 एसी बस भी शामिल थीं। यात्रियों के लिए 177 स्टॉप बनाए गए इस साल बसों की संख्या दोगुनी से ज्यादा यानि 515 तक पहुंच जाएगी। यात्री प्रतीक्षालय भी 425 हो जाएंगे। अगले पांच साल में बसों की संख्या बढ़ाकर 1500 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह बस स्टॉप भी 1100 हो जाएंगे। बीसीएलएल ने वर्ष 2020 में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) से चलने वाली 300 बस खरीदने का प्लान बनाया था इसे अमृत योजना में शामिल किया जाएगा। योजना में बसों के लिए केंद्र व राज्य सरकार अनुदान देंगी। इन बसों के संचालन के लिए रूट भी लगभग फाइनल किए जा चुके हैं। एक बस की कीमत 29 लाख रुपए है। यानि बस खरीदी पर 87 करोड़ रुपए खर्च होगा यह बसें पर्यावरण फ्रेंडली होंगी। इनसे प्रदूषण काफी कम होगा। कुछ बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। संभावना जताई जा रही है कि इस साल शहर की सड़कों पर 100 सीएनजी बस दौड़ने लगेंगी।

बीसीएलएल ने 100 इलेक्ट्रिक बस चलाने का प्लान बनाया। एक बस की कीमत करीब एक करोड़ रुपए है। इस हिसाब से एक अरब रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया। बसों की खासियत यह है कि अधिकतम तीन घंटे में पूरी तरह चार्ज हो जाएगी। एक बार में 200 किमी की दूरी तय कर सकेगी। बस 31 सीटर है। इसमें 15 लोग खड़े भी हो सकते हैं। ई-बसों से प्रदूषण नहीं होता और धुआं नहीं निकलता है। पहले चरण में इलेक्ट्रिक बसों के लिए तीन डिपो बनाने की योजना थी। केंद्र सरकार ई-बस खरीदने के लिए 40 फीसदी राशि मुहैया कराएगी। बाकी राशि चयनित ऑपरेटर खर्च करेगा। फिर बस चलाएगा। दिक्कत रखरखाव पर होने वाले खर्च की व्यवस्था करने में है। इसके लिए राज्य शासन से मदद मांगी थी संचालन के लिए राहत देने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन इसे हरी झंडी नहीं मिल पाई।

जानकारी के अनुसार नई योजना के तहत 75 करोड़ रुपए की बस खरीदी जाएगी। बाग सेवनिया, कोकता, वीर सावरकर सेतु, भानपुर खंती, पुराना आरटीओ कार्यालय, पुतलीघर, नादरा, आरिफ नगर, विद्या नगर में 125 करोड़ रुपए से नए बस डिपो बनेंगे। आईएसबीटी, जवाहर चौक और बैरागढ़ स्थित मौजूदा डिपो का 10 करोड़ से उन्नयन कार्य करवाए जाएंगे। वहीं खजूरी कलां में 53 करोड़ रुपए से नए आईएसबीटी का निर्माण किया जाएगा। साथ ही इलेक्ट्रिक साइकिल, ई-रिक्शा, **सीसीटीवी सर्विलांस कैशलेस** टिकटिंग, डिजिटल तकनीक पर 109.80 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

गौरतलब है कि अवधपुरी विद्यासागर तक ही बस है। इसके आगे 5 किमी तक बीडीए जैसी बड़ी कॉलोनियां हैं, यहां पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। निजामुद्दीन कॉलोनी में फोरलेन रोड बन गई, लेकिन बस सेवा संचालित नहीं हो पाई। कोलार के संस्कार उपवन से सलैया व 12 नंबर तक का रूट फोरलेन है, कई कॉलोनियां विकसित हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। आशिमा मॉल से केंद्रीय विद्यालय और इससे लगी हुई कॉलोनियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। गोपाल नगर एसओएस बालग्राम एक बड़ा रहवासी क्षेत्र है, लेकिन बसें नहीं हैं। कोलार के सीआई स्क्वायर से दानिशकुंज चौराहा और यहां से कलियासोत ब्रिज पार कर आने वाली कॉलोनियों के लिए कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, जबकि फोरलेन रोड है।

● **अरविंद नारद**

मुख्यमार्गों पर ही पूरा ट्रांसपोर्ट इसलिए दिक्कत

लो-फ्लोर के साथ सिटी बसें, मैजिक, ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े तमाम वाहनों का दबाव मुख्यमार्गों पर ही है। कमाई वाले इन मार्गों को छोड़ने कोई तैयार नहीं है। शहर के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम अब तक नहीं बन पाने की बड़ी वजह यही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक्सपर्ट जीएस गुलाटी का कहना है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हर कॉलोनी में हो तो लोग अपनी गाड़ी छोड़ेंगे। सड़कों पर निजी वाहन कम होने से जाम की स्थिति कम होगी तो बाजारों में पार्किंग की दिक्कत भी नहीं रहेगी। शहर में करीब 3500 किमी लंबी सड़कें हैं। इसमें मुख्य व इनके सहायक सड़कों की लंबाई 900 किमी के करीब हैं। अभी इसमें से 450 किमी पर ही पूरी बसें चल रही हैं। हर क्षेत्र तक बसें पहुंचाने अभी कम से कम 450 से 500 किमी की सहायक सड़कों पर भी बसों की जरूरत है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मप्र को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। इसके लिए प्रदेश में औद्योगिक विस्तार पर सबसे अधिक जोर दिया जा रहा है। औद्योगिक विस्तार की इस कड़ी में सरकार ने निवेश का नया रोडमैप तैयार किया है। इसके तहत प्रदेश में औद्योगिक कॉरिडोर का विस्तार किया जाएगा, जिसके माध्यम से विकास का सफर आगे बढ़ेगा और मप्र आत्मनिर्भर बनेगा। आने वाले दिनों में मप्र में कई औद्योगिक कॉरिडोर बनने जा रहे हैं। जिनके किनारे बड़े-बड़े उद्योग स्थापित किए जाएंगे। इससे प्रदेश में निवेश के साथ ही रोजगार की बहार आएगी।

कॉरिडोर बनेंगे विकास का सफर

2 साल तक कोरोना की गिरफ्त में रहने के बाद आज मप्र निवेश की राह पर बढ़ने की तैयारी में है। जनवरी 2023 में होने वाली ग्लोबल इंवेस्टर समिट से पहले निवेश का नया रोडमैप तैयार हो जाएगा। कई मल्टीनेशनल कंपनियां निवेश के लिए तैयार हैं। इनमें से कुछ से प्रारंभिक सहमति बन गई है तो कुछ जगह को लेकर मशक्कत में लगी हैं। आने वाले दिनों में आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई) और ड्रोन उद्योग से लेकर टैक्सटाइल-वेयरहाउसिंग जैसे परंपरागत उद्योगों तक में नए क्लस्टर आकार लेंगे। बता दें, कोरोना संक्रमण के कारण विदेशी निवेश लगभग बंद हो गया था। ऐसे में बंदिशों के कारण मप्र विदेशी निवेश को लेकर खास काम नहीं कर रहा था। अब स्थिति बदलने से वापस विदेशी निवेश पर फोकस किया गया है। उधर, प्रदेश में कई औद्योगिक कॉरिडोर बनाने की योजना बन रही है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। इसमें नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रस्ताव को प्राथमिकता से बनाने की बात हुई। यह कॉरिडोर मप्र के मुरैना, ग्वालियर, गुना, भोपाल, होशंगाबाद, बैतूल से होकर निकलेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि मप्र के कई जगह अलग-अलग क्लस्टर चिन्हित कर इसके लिए जमीन देने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस परियोजना की कार्ययोजना जितनी जल्दी होगी, उतनी जल्दी मप्र को लाभ मिलेगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मॉनिटरिंग अथॉरिटी की पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजन का ही कमाल है कि देश में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने वाले हैं, जो राज्यों की तकदीर व जनता की तस्वीर बदलने का कार्य करेगी। उनके विजन से दिशा मिलती है और इससे तेज गति से काम करने का प्रयास करते हैं। उनका कहना है कि दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जैसा प्रेजेंटेशन में दिखाया गया, मप्र तेज गति से काम किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के सपने को साकार करने के लिए मप्र में विकास की प्रतिबद्धता जाहिर की और कहा कि विक्रम उद्योगपुरी को प्रमोट में 202 एकड़ जमीन आवंटित की गई और इसमें 20 उद्योगपति जमीन भी ले चुके हैं तथा कई ने काम प्रारंभ कर दिए हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि नवंबर में एक कंपनी प्रोडक्शन प्रारंभ कर देगी। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि 15 कंपनियों के आवेदन आ चुके हैं जिन्हें बहुत जल्दी जमीन आवंटित की जाएगी। विक्रम उद्योगपुरी में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उद्योगपतियों को कोई दिक्कत नहीं होगी। मप्र वैसे भी इन्वेस्टर्स फ्रेंडली स्टेट है। उन्होंने कहा कि कोविडकाल में भी उद्योगिक विकास के लिए लगातार प्रयास किए हैं जिससे निवेश आने की गति ना रुके। उन्होंने डेलिगेशन ऑफ पावर को आश्वस्त किया कि वे तत्काल इस कार्य को पूरा करेंगे। दिल्ली-नागपुर कॉरिडोर के संबंध में कहा कि मप्र का वह क्षेत्र है जहां से यह निकलेगा, वहां भारतमाला परियोजना अंतर्गत 330 किलोमीटर के अटल एक्सप्रेस-वे का कार्य प्रारंभ कर रहे हैं। जिसके दोनों और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जमीन को चिन्हित कर लिया गया है और उद्योगपतियों को जमीन देने के लिए पूरी योजना भी तैयार की जा चुकी है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इसके लिए 11 हजार एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। मप्र में औद्योगिक विकास के लिए प्रधानमंत्री का जो विजन है उसे

मप्र में बनेंगे 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि प्रदेश में औद्योगिकीकरण के लिए 3 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, पहला इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अटल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के नाम से ग्वालियर के बीहड़ में बनाया जा रहा है। दूसरा जबलपुर से शुरू होकर सतना और रीवा का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तैयारी की जा रही है और तीसरा नर्मदा एक्सप्रेस-वे के नाम से नर्मदा के किनारे बनाया जाएगा। इन कॉरिडोर के बन जाने के बाद बड़ी तादाद में लोगों को रोजगार मिल सकेगा। वहीं प्रदेश के वाशिंदों को एक और सौगात मिलने जा रही है। यहां से दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गुजरेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि इस परियोजना का कार्य जितनी जल्दी होगा, मप्र को उतना ही लाभ मिलेगा। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मॉनिटरिंग अथारिटी की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बताया कि प्रदेश में इसके लिए कई जगह अलग-अलग क्लस्टर बनाए गए हैं। इसके लिए जमीन देने का काम भी प्रारंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने देश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की।

पूरा करने की तड़प भी है, जिसे पूरी तत्परता के साथ समय सीमा में विभिन्न परियोजना पर काम कर पूरा करेंगे।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलावा वाराणसी-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का प्रस्ताव दिया, जिसमें कहा कि पूर्वी मप्र खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न है। एल्युमीनियम व कोयला जैसे अलग-अलग खनिज प्रचुर मात्रा में है। यदि यह पश्चिम से जोड़ दिया जाए तो क्षेत्र में बेहतर रोड कनेक्टिविटी व मार्केट प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मप्र में निश्चित समय सीमा में कार्य होगा। उन्होंने कदम से कदम मिलाकर तथा कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने के साथ प्रधानमंत्री के सपनों को पूरा करने को कहा। वहीं दिल्ली-नागपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अब सागर के बाद नरसिंहपुर-सिवनी होते हुए नागपुर नहीं जाएगा। मप्र सरकार ने केंद्र सरकार को इसका रूट बदलने का प्रस्ताव दिया है। इसमें कहा गया है कि कॉरिडोर का मेन रूट तो दिल्ली से सागर तक पहले की ही तरह रखें, लेकिन सागर के आगे यह बीना, विदिशा, भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल होते हुए नागपुर तक बनाया जाए। बीते दिनों हुई प्रधानमंत्री गति शक्ति मिशन की बैठक में मप्र सरकार ने कहा है कि इस कॉरिडोर के पहले तय किए गए मेन रूट में कान्हा, पेंच नेशनल पार्क के साथ ही दुर्गम पहाड़ियों और नदियों के लंबे प्रवाह आ रहे हैं। यहां जमीन अधिग्रहण करना मुश्किल होगा। बड़े पैमाने पर प्राकृतिक संसाधन बर्बाद होंगे। इस क्षेत्र में कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया विकसित नहीं किया जा सकता। जबकि नया रूट राष्ट्रीय राजमार्ग-44 और 46 से होकर गुजरता है। यहां सरकार 20 हजार हेक्टेयर जमीन चिन्हित कर चुकी है। अधिग्रहण की प्रक्रिया अलग-अलग चरणों में जारी है। बीना में 2,500 हेक्टेयर में प्रस्तावित बीपीसीएल का पेट्रोकेमिकल पार्क, भोपाल से लगे मंडीदीप और तामोट जैसे प्रमुख इंडस्ट्रियल एरिया इस कॉरिडोर में आएंगे।

केंद्र नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश में 11 नेशनल कॉरिडोर बना रहा है। इसमें दिल्ली-नागपुर कॉरिडोर मप्र के

लिए अहम है। 1100 किमी लंबे कॉरिडोर का 70 प्रतिशत हिस्सा मप्र से गुजरेगा। नए प्रस्तावित रूट में मप्र के 23 जिलों के 32 इंडस्ट्रियल क्षेत्र आएंगे। इन 23 में से 18 जिलों से यह कॉरिडोर गुजरेगा, जबकि शेष पांच जिलों से इसकी आंशिक कनेक्टिविटी रहेगी। ये क्षेत्र उसके 150 किमी के दायरे में होंगे। सभी कॉरिडोर का काम 2025 तक पूरा होना है। इसके लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2000 करोड़ रुपए कर्ज दिया है। इस योजना में सरकार अलग-अलग इंडस्ट्रियल क्षेत्रों को जोड़ने के लिए सड़क, रेल और जलमार्ग के जरिए एक गलियारा बनाएगी। कॉरिडोर के नए रूट के 150 किमी के दायरे में मप्र के 13 नगरीय, 32 औद्योगिक क्षेत्र आएंगे। ये दिल्ली से शुरू होकर मथुरा, ग्वालियर, झांसी, ललितपुर, बीना, गंजबासौदा, विदिशा, भोपाल, नर्मदापुरम, इटारसी, बैतूल, मुलताई, पांढुरना, कोटल से होकर नागपुर पहुंचेगा।

दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) भले ही मप्र से होकर नहीं गुजर रहा हो, लेकिन यह प्रदेश के औद्योगिक विकास में अहम भूमिका निभाने वाला है। 1483 किलोमीटर लंबाई वाले इस कॉरिडोर के प्रभाव क्षेत्र में मप्र की 372 वर्ग किलोमीटर भू-भाग वाली इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप बस रही है। यह बहुत बड़ा इलाका है। इसके माध्यम से मप्र की आर्थिक तस्वीर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में मप्र की हिस्सेदारी, परियोजना के पहले चरण में दूसरे सबसे बड़े भू-भाग वाली हिस्सेदारी है। मप्र की इंडस्ट्रियल टाउनशिप में सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्योग लगाए जाएंगे। ये वे क्षेत्र हैं जो पहले ही तेज विकास के साथ अपनी उपयोगिता को साबित कर चुके हैं। इसके अलावा ऑटोमोबाइल क्षेत्र को भी प्राथमिकता दी जाएगी। दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर (डीएमआईसी) एक ऐसी परियोजना है जो उप्र, दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगी। इस परियोजना को 9000 करोड़ डालर से तैयार किया जा रहा है। खास बात यह है कि इनमें से चार राज्य ऐसे हैं जिनकी सीमा मप्र से सटी हुई है। इस कॉरिडोर के आसपास विकसित होने वाली औद्योगिक टाउनशिप में रोजगार के अपार अवसर होंगे। एक छोटे-मोटे शहर की तरह विकसित होने वाली इन औद्योगिक टाउनशिप में लोगों को उनकी योग्यता के अनुसार काम मिलना तय है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

पीथमपुर और देवास जैसे क्षेत्रों को मिलेगा लाभ

मप्र के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के प्रमुख सचिव संजय शुक्ला गत दिनों सीआईआई मप्र के वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचे। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी इसमें शामिल हुए। शुक्ला ने कहा कि इंदौर के 35 से 40 किमी के दायरे में अंतरराष्ट्रीय विमानतल बनने से पीथमपुर और देवास जैसे क्षेत्रों को लाभ मिलेगा। इंदौर और इसके आसपास मैन्युफैक्चरिंग उद्योग बड़ी संख्या में है। विमानतल तैयार होने से लॉजिस्टिक क्षेत्र बेहतर होगा। प्रदेश भारत के मानचित्र में बीच में आने से कई लाभ हैं। हम 12 घंटे के सफर में आसपास के किसी भी शहर में पहुंच सकते हैं। लॉजिस्टिक पार्क बनने से भी उद्योगों को गति मिलेगी। नई उद्योग नीति के संदर्भ में महिंद्रा और टाटा जैसी कई कंपनियों की राय भी ली गई है। इसमें कई तरह के प्रावधान रखे गए हैं, जिससे प्रदेश के उद्योगों को पहले से ज्यादा सुविधाएं मिल सकेंगी। आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर प्रदेश के लिए सरकार कई काम कर रही है। मेडिकल पार्क के साथ ही कई तरह के क्लस्टर बनाए जा रहे हैं, जहां सभी क्षेत्रों के उद्योगों को जगह मिलेगी।

नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा

मप्र में नर्सिंग कॉलेज संचालन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका में लॉ स्टूडेंट्स की याचिका पर आरोप लगाया कि प्रदेश के 453 कॉलेजों की फाइलों में से 37 हजार पेज गायब हैं। याचिकाकर्ता ने निरीक्षण में यह जानकारी कोर्ट को दी। जिस पर हाईकोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से जवाब मांगा है। नर्सिंग कॉलेजों में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने याचिका दायर की है। मप्र शासन की ओर से नर्सिंग काउंसिल में रखे हुए प्रदेश के 453 नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता के समस्त रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किए गए थे जिस पर हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन मप्र को रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति दी गई थी, संपूर्ण रिकॉर्ड के निरीक्षण के उपरांत याचिकाकर्ता की ओर से अपनी निरीक्षण रिपोर्ट उच्च न्यायालय के समक्ष पेश की गई। जिसमें बताया गया है कि नर्सिंग काउंसिल की ओर से कोर्ट में पेश किए गए रिकॉर्ड में से 37759 पन्ने गायब हैं, जिनका उल्लेख तो मान्यता की फाइलों में है लेकिन वास्तिवकता में वो कागजात फाइल में नहीं हैं। सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि समस्त रिकॉर्ड पेश किया जा चुका है।

नर्सिंग काउंसिल की ओर से पेश हुए उप महाधिवक्ता स्वप्निल गांगुली ने ग्वालियर हाईकोर्ट की तर्ज पर शेष 453 नर्सिंग कॉलेजों की जांच के लिए कमेटी बनाने के लिए आग्रह किया गया तो हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया। वहीं हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जाहिर करते हुए राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि आखिर उक्त पन्ने कहां गायब हो गए। चीफ जस्टिस रवि मलिमठ व जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने 11 जुलाई को फिर से सुनवाई करने के निर्देश दिए। अगली सुनवाई पर सरकार को स्पष्टीकरण पेश करना है। गौरतलब है कि लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विशाल बघेल ने प्रदेश के फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को चुनौती देते हुए एक जनहित याचिका दायर की थी।

पिछली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के आदेश के पालन में मप्र शासन द्वारा नर्सिंग काउंसिल में रखे हुए प्रदेश के 453 नर्सिंग कॉलेजों के मान्यता के समस्त रिकॉर्ड कोर्ट में पेश किए गए। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति दी थी। संपूर्ण रिकॉर्ड के निरीक्षण के बाद विशाल बघेल ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की। रिपोर्ट में बताया गया कि नर्सिंग काउंसिल द्वारा कोर्ट में पेश किए गए रिकॉर्ड में से 37759 पन्ने गायब हैं। इनका उल्लेख मान्यता की फाइलों में तो है, लेकिन वास्तिवकता में वो कागज नहीं हैं। नर्सिंग काउंसिल की ओर से ग्वालियर हाईकोर्ट की तर्ज पर शेष 453 नर्सिंग कॉलेजों की जांच के लिए कमेटी बनाने हेतु आग्रह किया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे नकार दिया। याचिकाकर्ता की निरीक्षण रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। रिपोर्ट में 80 कॉलेजों की सूची भी पेश की है, जिसमें प्राचार्य एवं अन्य शैक्षणिक स्टाफ को एक ही समय में एक से अधिक संस्थाओं में कार्यरत दर्शाया गया है। ऐसे अनेक कॉलेजों की फोटो पेश की गई है जो एक ही भवन में अलग-अलग पाठ्यक्रमों की मान्यता लेकर कॉलेज संचालित कर रहे हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा ने वर्ष 2020-21 के नर्सिंग कॉलेजों द्वारा ऑनलाइन फार्म में भरे गए शैक्षणिक स्टाफ तथा अन्य दस्तावेज सॉफ्ट कॉपी में मांगे हैं। कोर्ट ने काउंसिल को समस्त रिकॉर्ड का एक्सेस याचिकाकर्ता को प्रदान करने के निर्देश दिए।

गौरतलब है कि प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस पर गाज गिरी है। प्रदेश के 200 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता रद्द कर दी गई है। लगातार फर्जीवाड़े और शिकायतों के चलते विभाग ने इसको लेकर जांच पड़ताल कराई थी। पड़ताल में नियमों का उल्लंघन करने वाले 200 से नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द की गई है। तकनीकी शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को खत्म किया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है इस सेक्टर को पूरी तरह से शुद्ध करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सुनिश्चित किया जाएगा कि इस सेक्टर में पूरी तरह से शुद्धता और सुचिता आए। नर्सिंग सेक्टर में नियम कानूनों का पालन किया जाए। फर्जी तरीके से चल रहे नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि यह हमारी बड़ी सफलता है। तकनीकी शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा हमने इस क्षेत्र को साफ सुथरा करने का निर्णय लिया था। जिसके कारण ये कार्रवाई की गई है। नर्सिंग कॉलेजों की लंबे समय से लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इसके बाद मामलों की जांच की गई। पड़ताल में आरोप सही पाए जाने के बाद ही 200 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। मंत्री सारंग ने कहा कि नर्सिंग कॉलेजों का शुद्धिकरण किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में फर्जीवाड़ा नहीं होने दिया जाएगा। फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को संचालित नहीं होने दिया जाएगा। छात्र-छात्राओं के भविष्य को लेकर मंत्री का कहना है कि कॉलेज गलत होंगे तो कहां के शिक्षक और कहां के छात्र। छात्र-छात्राओं का अहित कहीं नहीं होगा। किसी भी छात्र का हम नुकसान नहीं होने देंगे। माफियागिरी शिक्षा में नहीं चलेगी।

● **राकेश ग्रोवर**

कॉलेजों में हो रहा था जमकर फर्जीवाड़ा

फर्जी नर्सिंग कॉलेज में लगातार दलाल सक्रिय हैं। दलालों के सक्रिय होने को लेकर लगातार शिकायतें की जा रही थी। जिसमें छात्र-छात्राओं को एडमिशन किसी और कॉलेज में दिया जा रहा है और पढ़ाई किसी और कॉलेज में कराई जा रही है। किसी और कॉलेज के नाम से फीस जमा कराई जा रही है। ज्यादातर नर्सिंग कॉलेजों में ना तो लैब है और ना ही एक्सपोर्ट टीचर हैं। प्रदेश में नर्सिंग कॉलेजेस पर गाज गिरी है। प्रदेश के 200 से ज्यादा नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता रद्द कर दी गई है। लगातार फर्जीवाड़े और शिकायतों के चलते विभाग ने इसको लेकर जांच पड़ताल कराई थी। पड़ताल में नियमों का उल्लंघन करने वाले 200 से नर्सिंग कॉलेज की मान्यता रद्द की गई है। तकनीकी शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को खत्म किया है। तकनीकी शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है इस सेक्टर को पूरी तरह से शुद्ध करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि सुनिश्चित किया जाएगा कि इस सेक्टर में पूरी तरह से शुद्धता और सुचिता आए। नर्सिंग सेक्टर में नियम-कानूनों का पालन किया जाए। फर्जी तरीके से चल रहे नर्सिंग कॉलेजों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। इसको लेकर मंत्री सारंग ने कहा कि यह हमारी बड़ी सफलता है।

कागजों पर वाटर हार्वेस्टिंग

राजधानी में वाटर हार्वेस्टिंग की पाबंदी के बाद भी कई क्षेत्रों में भू-जल स्तर 500 मीटर तक पहुंच गया है। यह इस बात का संकेत है कि शहर में वाटर हार्वेस्टिंग का प्लान केवल कागजों पर चल रहा है। आलम यह है कि नगर निगम आम लोगों पर तो वाटर हार्वेस्टिंग के लिए कड़ाई कर रहा है, लेकिन बड़ी-बड़ी सरकारी संस्थानों पर वाटर हार्वेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसा हो जाता तो बड़ी मात्रा में पानी जमीन के नीचे जाता और भू-जल का स्तर उठता।

गौरतलब है कि नगर निगम की बिल्डिंग परमिशन शाखा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए नया प्रस्ताव तैयार कर रही है। इसके तहत यदि आप 140 वर्ग मीटर से छोटे प्लॉट पर भी अपना नया मकान या व्यापारिक संस्थान बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके साथ ही आपको रूफ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाना होगा। अब तक ये बंदिशें इससे बड़े प्लॉट पर हो रहे भवन निर्माण तक ही सीमित थीं। ऐसे ही नई कॉलोनी बनाने के दौरान कॉलोनाइजर को भी जमीन पर फैले बारिश के पानी को ग्राउंड वाटर रिर्चाजिंग सिस्टम लगवाना होगा। इसके बाद ही उन्हें कॉलोनी की परमिशन दी जाएगी। लेकिन बड़े-बड़े सरकारी संस्थानों के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। अगर शहर में स्थित 122 बड़े संस्थानों की छत पर वाटर हार्वेस्टिंग हो जाए तो जमीन में 61 करोड़ लीटर पानी जा सकता है। लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। शाहपुरा क्षेत्र में नगर निगम का भवन अनुज्ञा शाखा का 4000 वर्गफीट छत का ऑफिस है। यहां सिस्टम ही नहीं लगा। माता मंदिर स्थित निगम भवन की छत करीब 7000 वर्गफीट की है। यहां भी निगम ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम नहीं लगा रखा है। 6 नंबर स्थित डायरेक्टोरेट अर्बन डेवलपमेंट में बहुत पहले एक सिस्टम लगाया था। मौजूदा समय में अनदेखी का शिकार होकर बेकार हो गया। ये करीब 20 हजार वर्गफीट की छत है और यहां से भी 20 लाख लीटर पानी जमीन में उतारा जा सकता है। निगमायुक्त केवीएस चौधरी का कहना है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जागरुकता सभी स्तरों पर की जा रही है। निगम भी खुद के नए भवन पर इसके लिए काम करवा रहा है। पुराने के लिए भी हम प्रावधान करेंगे। सरकारी भवनों के लिए संबंधित विभागों से चर्चा की जाएगी, ताकि पानी जमीन में उतरे।

सरकार आम लोगों के घरों की छत पर वाटर हार्वेस्टिंग कराने तमाम नियम कानून और शुल्क तय किए हुए हैं, लेकिन खुद के ही संस्थानों की छतों का पानी जमीन में उतारने की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर में 122 सरकारी संस्थानों के बड़े भवन हैं। इनकी छत का औसत क्षेत्रफल 8000 वर्गफीट ही मानें तो इनसे एक बारिश में 61 करोड़ लीटर पानी जमीन में उतारा जा सकता है। ये शहर के 1.35 लाख लोगों की एक माह की जल जरूरत के समान है। स्थिति ये है कि खुद नगर निगम के कई भवनों में ये व्यवस्था नहीं है। स्मार्टसिटी ने जरूर अपने भवन पर वाटर हार्वेस्टिंग कराई थी, लेकिन दो साल में उसका भी कोई हिसाब नहीं रखा गया। अगर, यही पानी सहेज लें तो काफी कुछ ग्राउंड वॉटर रीचार्ज हो सकता है।

निगम ने 26 दिसंबर 2009 से मप्र भूमि विकास नियम 1984 की धारा 78 के तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य किया था। निगम में 140 वर्गमीटर से बड़े प्लॉट पर बिल्डिंग परमिशन लेने के दौरान ही सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाना होता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते वक्त बिल्डिंग परमिशन शाखा को आरडब्ल्यूएच की स्थिति देखनी जरूरी होती है। यदि भवन संचालक ने आरडब्ल्यूएच नहीं लगवाया है तो जमा हुई फीस से ये काम बिल्डिंग परमिशन शाखा करेगी। 2009 से 31 मई 2022 तक इस शाखा के पास करीब 18 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। 2017-18 और इसके बाद भी इस राशि से आरडब्ल्यूएच लगवाने के लिए अभियान चलाने के लिए कई बार बैठकें हो चुकी हैं फिर भी फील्ड स्तर पर कोई काम नजर नहीं आया है।

इंदौर की बात करें तो बारिश के पानी में शहर डूबने से बचाने में असफल नगर निगम पानी सहेजने में भी पीछे है। कुछ महीने पहले वाटर हार्वेस्टिंग का अभियान शुरू किया था, हर वार्ड में औसतन 10 हजार घरों में रैन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य करवाना था, बारिश शुरू हो गई है लेकिन आधा भी पूरा नहीं हुआ है। करीब 1 लाख 90 हजार जगह वाटर हार्वेस्टिंग का दावा था, 50 प्रतिशत भी पूरी नहीं होने से लगता है कि सिर्फ कागजों में ही बारिश का पानी बचा रहे हैं। दो दिन पहले तक करीब 70 हजार वाटर हार्वेस्टिंग किए गए थे, जीयो टैगिंग की हालत तो और खराब है। मात्र 549 जगह जीयो टैगिंग की जा सकी है। नगर निगम प्रशासन दो महीने से पानी सहेजने के अभियान में लगा है लेकिन मैदानी अमले से सहयोग नहीं मिल पा रहा है। निगमायुक्त ने फटकार लगाते हुए वेतन रोकने की चेतावनी भी दी है लेकिन फिलहाल इसका असर नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि रैन वाटर हार्वेस्टिंग में बारिश का मौसम शुरू होने के बाद भी आधा लक्ष्य भी ढंग से हासिल नहीं हो पाया है। नगर निगम के 19 जोन है। 1 लाख 90 हजार जगह पर वाटर हार्वेस्टिंग की योजना थी। इसके लिए टीम भी बनाई गई है लेकिन उसका भी सहीं इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है।

● **लोकेंद्र शर्मा**

भोपाल में कई क्षेत्रो में 500 फीट पर पानी भी नहीं

सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की रिपोर्ट में भोपाल को सेमी क्रिटिकल कैटेगरी में रखा गया है। शहर में ऐसे कई स्थान हैं, जहां 500 फीट पर भी पानी उपलब्ध नहीं है। भोपाल में 2859.06 हेक्टेयर मीटर में से 2271.72 हेक्टेयर मीटर पानी निकाला जा रहा है। ऐसा केवल इसलिए क्योंकि बरसात में ग्राउंड वाटर कम रीचार्ज हुआ है। ये रीचार्ज आरडब्ल्यूएच लगाने से ही हो सकेगा। आम लोग भी बेपरवाह हैं। वाटर हार्वेस्टिंग की शर्त पर निर्माण अनुमति लेने वाले 140 वर्गमीटर से अधिक दायरे के 6172 भवनों ने शर्त का पालन नहीं किया। 2008 के बाद इसे अनिवार्य किया हुआ है। 140 वर्गमीटर की छत से सिस्टम के माध्यम से 8 लाख लीटर पानी जमीन में उतारा जा सकता है। इसमें बमुश्किल 15 हजार रुपए तक खर्च आता है। निजी प्लंबर से भी काम कराया जा सकता है।

इंदौर-भोपाल में दौड़ेगी फ्रांस की मेट्रो ट्रेन

इंदौर और भोपाल में तैयार हो रही मेट्रो रेल के ट्रैक पर अत्याधुनिक फ्रांसिसी मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी। फ्रांसिसी कंपनी एल्स्टाम को भोपाल और इंदौर के लिए 156 मोविया मेट्रो कार की आपूर्ति का टेंडर मिलना तय हो गया है। मप्र मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एमपीएमआरसीएल) की ओर से निकाले गए टेंडर में कंपनी ने सबसे कम दरें भरी हैं, इसके बाद अब वर्क ऑर्डर जारी होने की प्रक्रिया बाकी रह गई है। कंपनी के अधिकारियों ने बताया कि मेट्रो ट्रेनों और विभिन्न प्रणालियों की आपूर्ति के लिए 3200 करोड़ रुपए का टेंडर लिया गया है। जिसके तहत भोपाल के लिए 27 और इंदौर के लिए 25 ट्रेन चलाने की जिम्मेदारी मिल रही है। इसमें ट्रेनों की स्थापना, संचालन और 15 वर्षों तक रखरखाव का काम कंपनी की ओर से किया जाएगा। इस परियोजना से इन दोनों शहरों के 57 लाख से अधिक लोगों को परिवहन सुविधा का फायदा मिलेगा।

कंपनी 52 गेज मोविया मेट्रो यात्री ट्रेन बनाएगी, जो तीन-कार वाली होगी। ये अत्याधुनिक, बेहद हल्की ट्रेनें भोपाल में 31 किमी लाइन पर 30 स्टेशनों के साथ 80 किमी प्रति घंटा की अधिकतम गति से संचालित होंगी। वहीं इंदौर में 29 स्टेशनों के साथ 31.5 किमी लाइन पर इनका संचालन होगा। इनका निर्माण एल्सटाम की गुजरात के सावली में अत्याधुनिक रोलिंग स्टाक निर्माण इकाई में किया जाएगा।

मेट्रो प्रोजेक्ट में अब बड़े ठेकों की मंजूरी भी होने लगी है। रेल कोच के साथ-साथ इलेक्ट्रीफिकेशन का ठेका भी फाइनल हो गया है। 33.53 किलोमीटर का जो पहला चरण इंदौर मेट्रो का है उसके साथ गांधीनगर डिपो के भी इलेक्ट्रीफिकेशन का ठेका 568.31 करोड़ में कल्पतरू पॉवक ट्रांसमिशन लिमिटेड को मिला है। 6 अन्य कंपनियों को पछाड़कर यह ठेका कल्पतरू की झोली में गया, तो दूसरी तरफ 1100 करोड़ अधिक में 156 कोच का ठेका एल्स्टाम ट्रांसपोर्ट इंडिया को 3248 करोड़ में दिया गया है।

इंदौर मेट्रो का काम सुपर कॉरिडोर से लेकर एमआर-10 और विजय नगर होते हुए रोबोट चौराहा तक तेज गति से चल रहा है। मप्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने रोलिंग स्टॉक यानी कोच व अन्य कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय टेंडर बुलाए, जिसमें इलेक्ट्रीफिकेशन सहित अन्य काम भी शामिल हैं। मेट्रो कोच यानी रेल के डिब्बों के लिए दो कंपनियों ने हिस्सा लिया। इंदौर और भोपाल में 156 कोच खरीदे जाएंगे, जिसमें से 81 कोच भोपाल के और 75 कोच इंदौर के रहेंगे, जो कि पहले चरण में दौड़ने वाली 25 मेट्रो ट्रेन में इस्तेमाल किए जाना है। इसके लिए एल्स्टाम ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 3248 करोड़ के टेंडर भरे थे। हालांकि यह 1100 करोड़ रुपए अधिक कीमत के थे। बावजूद इसके इन टेंडरों को अभी मंजूरी दी गई है। दरअसल निर्माण सामग्री सहित अन्य कीमतों में जो वृद्धि हुई, उसके चलते कोच की लागत भी बढ़ गई है। हालांकि इसके टेंडर 2145 करोड़ के ही थे और 51 फीसदी अधिक राशि के टेंडर प्राप्त हुए। वहीं दूसरी तरफ इलेक्ट्रीफिकेशन का ठेका कल्पतरू पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड को मिला है। इंदौर मेट्रो के पहले चरण में जो 33.53 किलोमीटर की जो यलो लाइन रहेगी उसके संपूर्ण इलेक्ट्रीफिकेशन, जिसमें एलिवेटेड और अंडरग्राउंड स्टेशनों के साथ-साथ गांधी नगर सुपर कॉरिडोर पर जो 75 एकड़ में विशाल डिपो बनाया जा रहा है उसका भी इलेक्ट्रीफिकेशन इस टेंडर में शामिल रहेगा। कल्पतरू ने 568.31 करोड़ रुपए का टेंडर भरा, जो कि अन्य 6 प्राप्त टेंडरों की राशि में कम रहा। दूसरे स्थान पर स्टर्लिंग एंड विल्सन लिमिटेड रही, जिसने 601 करोड़, तीसरे स्थान पर सीमंस लिमिटेड का टेंडर 609.47 करोड़ और चौथे स्थान पर लॉर्सन एंड टूब्रो लिमिटेड रही, जिसने 646 करोड़, वहीं उससे ज्यादा लिंग्सन इंडिया लिमिटेड ने 648.51 करोड़, वहीं केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड ने 677.34 करोड़ और अलस्टॉम ट्रांसपोर्ट लिमिटेड ने सर्वाधिक 788.75 करोड़ का टेंडर भरा था। इसी कंपनी को 156 कोच का ठेका मिला है।

पिछले दिनों मप्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने रोलिंग स्टॉक खरीदी के ये टेंडर बुलाए थे। इसके साथ-साथ सिग्नलिंग, ट्रेन कंट्रोल सिस्टम, टेली कम्यूनिकेशन के काम भी शामिल रहेंगे। 7 साल तक कंपनी रखरखाव के साथ-साथ अन्य कार्य भी करेगी। इंदौर में जो मेट्रो प्रोजेक्ट अमल में लाया जा रहा है, उसमें एक मेट्रो ट्रेन की लंबाई 140 मीटर रहेगी और इस लंबाई के अनुरूप ही पहले चरण के प्रोजेक्ट के लिए 29 स्टेशनों का निर्माण किया जा रहा है। 33.53 किलोमीटर के ट्रैक पर 25 मेट्रो ट्रेन दौड़ेगी और हर एक ट्रेन में तीन-तीन कोच रहेंगे, जिसके चलते 75 कोच, यानी मेट्रो कार रोलिंग स्टॉक की खरीदी की जा रही है। जब दूसरे ट्रैक के प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे, तब उसके लिए फिर अलग से कोच और अन्य सिस्टम लगेगा। अभी तक फ्रांस और जर्मनी की कंपनियां ही मेट्रो कोच सहित अन्य सामग्री निर्मित करती रही, मगर फिलहाल देश में कई बड़े शहरों में मेट्रो प्रोजेक्ट शुरू हो गए। लिहाजा कई देसी कंपनियों ने भी विदेशी कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम में कोच सहित अन्य सामग्रियों का निर्माण शुरू कर दिया है। हालांकि अधिकांश तकनीक और सामग्री विदेशी कंपनियों से ही लेना पड़ रही हैं, लेकिन असैम्बलिंग सहित अन्य कार्य देश में ही होने लगे हैं।

● **जितेंद्र तिवारी**

ट्रेन संचालन का पूरा सिस्टम विकसित करेगी कंपनी

कंपनी को मिलने वाले टेंडर में ट्रेन नियंत्रण (सीबीटीसी) सिग्नलिंग प्रणाली के साथ ट्रेन नियंत्रण एवं दूरसंचार प्रणाली लगाने का काम शामिल है। कंपनी दोनों प्रणालियों का 7 साल तक रखरखाव भी करेगी। एल्स्टाम इंडिया क्लस्टर के निदेशक ने बताया कि एल्सटाम इंडिया भारत में दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, लखनऊ, कोच्चि शहरों में मेट्रो का संचालन कर रही है। वहीं आगरा-कानपुर मेट्रो परियोजना का काम भी कर रही है। इसके अलावा कंपनी वर्तमान में आगरा-कानपुर, मुंबई मेट्रो लाइन तीन के लिए मेट्रो ट्रेनों और भारत की पहली सेमी हाई-स्पीड दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस परियोजना के लिए आधुनिक ट्रेनों का निर्माण कर रही है।

मप्र से भर रहा उप्र का खजाना

मप्र की खनिज संपदा से पड़ोसी राज्य उप्र सरकार अपना खजाना भर रही है। प्रदेश से जाने वाली हर तरह की खनिज संपदा को एंट्री देने के लिए उप्र सरकार 950 प्रति घन मीटर के हिसाब से इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (आईएसटीपी) की वसूली कर रही है। यूं तो मप्र से कई खनिज उप्र व दूसरे राज्यों में जाते हैं, लेकिन रेत, काली गिट्टी और सफेद पत्थर प्रतिदिन सबसे ज्यादा उप्र जाता है।

खनिज कारोबार से जुड़े व्यापारियों के अनुसार इन तीन खनिज संपदाओं के लगभग 17 हजार डंपर रोजाना सिर्फ उप्र के तमाम शहरों में सप्लाई के लिए भेजे जाते हैं। जिनसे रोजाना उप्र सरकार लगभग 2 करोड़ रुपए वसूल रही है। इस आईएसटीपी का असर ये हुआ है कि बढ़ती महंगाई के कारण खनिज कारोबारियों ने अपनी गिट्टी के दाम 100 रुपए प्रति टन तक बढ़ा दिए हैं। जिससे निर्माण कार्यों की लागत भी बढ़ती जा रही है। वहीं राजस्थान से प्रतिस्पर्धा में महंगा होने के कारण इनका कारोबार भी कम हो रहा है। छतरपुर क्रेशर एसोसिएशन के तत्कालीन अध्यक्ष मनोज मिश्रा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आईएसटीपी की व्यवस्था को खत्म करने का आग्रह किया है।

गौरतलब है कि एक गाड़ी में 24 घनमीटर काली गिट्टी आती है और प्रति घन मीटर 50 रुपए आईएसटीपी का शुल्क रॉयल्टी स्लिप तैयार होते समय देना पड़ता है। ऐसे में एक गाड़ी पर 1200 रुपए का शुल्क उप्र में एंट्री के लिए चुकाना पड़ रहा है। ये भुगतान रॉयल्टी कटते वक्त ही ऑनलाइन उप्र सरकार के खजाने में जमा होता है। इंटर स्टेट ट्रांजिट पास यानी कि आईएसटीपी देश में सिर्फ उप्र की सीमा पर लागू किया गया है। उप्र सरकार की कैबिनेट ने इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है कि दूसरे राज्यों से जो भी खनिज संपदा उप्र की सीमा में लाई जाएगी। उस पर 50 रुपए प्रति घनमीटर शुल्क लिया जाएगा। ग्वालियर के बिलौआ स्टोन क्रेशर एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह कंषाना के अनुसार राजस्थान से खनिज सामग्री कम दूरी के कारण कम ट्रांसपोर्ट खर्च पर उप्र, दिल्ली आदि तक पहुंच जाती है। वहीं हम लोग पहले से ही राजस्थान, उप्र की तुलना में ज्यादा महंगा डीजल और महंगी बिजली के साथ व्यापार कर रहे थे। अब आईएसटीपी ने व्यापार में महंगाई और बढ़ा दी। करीब डेढ़ महीने पहले जो गिट्टी 260 रुपए प्रति टन थी। उसकी कीमत अब ग्वालियर में 360 रुपए प्रति टन है। जो जनता को चुकानी पड़ रही है। और हम मजबूरी में जनता पर भार डाल रहे हैं। प्रदेश के खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि ये मामला मेरे संज्ञान में है। हम हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। मप्र सरकार ने भी एंट्री पर खनिज उत्पादों पर 25 रुपए प्रति घनमीटर का शुल्क लगाने का प्रयास किया था। लेकिन ये मामला मप्र हाईकोर्ट में चला गया है।

राज्य सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी मप्र में रेत, गिट्टी का अवैध उत्खनन नहीं रुक रहा है। लिहाजा सरकार अब इस क्षेत्र में अच्छा काम करने वाले राज्यों की मदद लेगी। खनिज साधन विभाग ने उप्र, महाराष्ट्र, कर्नाटक सहित दो अन्य राज्यों से खनिज नीति की मांग की है। इसमें देखा जाएगा कि संबंधित राज्यों ने किस प्रकार अवैध उत्खनन पर रोक लगाई है और इन राज्यों ने क्या परिणाममूलक प्रयास किए हैं। राज्यों की खनिज नीति का अध्ययन करने के बाद विभाग के अधिकारियों का दल संबंधित राज्यों का दौरा भी करेगा।

प्रदेश में पिछले साल खनिज, पुलिस और वन विभाग ने मिलकर अवैध रेत उत्खनन व परिवहन के 1800 प्रकरण दर्ज किए हैं। इनमें 24 हजार 932 घन मीटर रेत जब्त की गई है। एक हजार 792 चार पहिया वाहन जब्त हुए हैं और 23 वाहन राजसात किए गए हैं। इस स्थिति ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। विभाग की समीक्षा के समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभाग के अधिकारियों को अवैध उत्खनन पर रोक लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद खनिज विभाग ने इन राज्यों के खनिज विभाग को पत्र लिखकर खनिज नीति की मांग की है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि संबंधित राज्य अवैध उत्खनन पर रोक लगाने में कामयाब रहे हैं। अन्य राज्यों से मांगी गई खनिज नीति में यह भी देखा जाएगा कि मप्र में ट्रांजिट परमिट (टीपी), उत्खनन और परिवहन को व्यवस्थित करने के लिए क्या किया जा सकता है। रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन के लिए प्रदेश के आठ जिले कुख्यात हैं। पिछले साल छतरपुर, ग्वालियर, सीहोर, राजगढ़ और खरगोन में अवैध रेत परिवहन के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। खरगोन, रतलाम, टीकमगढ़, जबलपुर और छतरपुर में सबसे ज्यादा रेत जब्त की गई है।

● **विकास दुबे**

सरकारी बंद खदानों पर माफिया का राज, अंधाधुंध खनन कर रहे

नर्मदापुरम संभाग एवं प्रदेश के सबसे अधिक खनिज राजस्व देने वाले नर्मदापुरम जिले में खदानों का मसला सुलझ ही नहीं पा रहा। बीते अक्टूबर माह से बंद चल रही ठेके की 118 वैध खदानें अभी तक चालू नहीं हो सकी हैं। इन सरकारी खदानों पर माफिया राज कर रहे हैं। खुलेआम और अंधाधुंध खनन कर लाखों रुपए की काली कमाई जुटाई जा रही है, लेकिन शासन-प्रशासन को अपनी खदानों को चालू कर वैध खनन और परिवहन शुरू कराकर रेत खनिज राजस्व को फिर से अर्जित करने की सुध ही नहीं है। ठेका कंपनी आरकेटीसी को बंद खदान अवधि के दौरान अब तक करीब डेढ़ सौ करोड़ का नुकसान हो चुका है, जबकि खनिज निगम-विभाग के पास कंपनी का 70 करोड़ रुपए एडवांस में पेड रॉयल्टी के रूप में जमा है। बता दें कि ठेका कंपनी ने खदानें निरस्त करने के बाद हाईकोर्ट में प्रकरण लगाया हुआ है। जिसमें शासन-विभाग अपना पक्ष ही मजबूती से नहीं रख पा रहा है। मसला सुलझ ही नहीं पा रहा है। अगली सुनवाई जुलाई माह में तय की गई है। समूचा रेत काराबोर ठप पड़ा हुआ है। वैध खदानों में खनन-परिवहन के बंद रहने से शासन को भी आर्थिक आय का घाटा उठाना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नर्मदा-तवा नदी के इन बंद खदानों में इन दिनों रेत माफिया का राज चल रहा है। अवैध कारोबारी डंपर और ट्रैक्टर-ट्रॉलियों से तट-खदानों से अंधाधुंध अवैध खनन कर रेत की चोरी कर रहे हैं, जबकि कुछ जगहों पर खदानों के रास्तों को भी जेबीसी से खुदवाकर बंद कराया गया था।

31 हजार हेक्टेयर जंगल की वैध कटाई

जंगलों की तरफ बढ़ते विकास कार्यों से वनों और वन्य जीवों का दायरा घट रहा है। पिछले 10 वर्ष में 31 हजार हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि विकास कार्यों की चपेट में आ चुकी है। वन विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार इन वर्षों में सिंचाई, विद्युत, खनिज और रोड सहित अन्य 371 बड़ी परियोजनाएं लॉन्च की गईं। केन-बेतवा लिंक परियोजना, बंदर हीरा खदान सहित करीब 6 बांध परियोजनाएं वन भूमि में शुरू होनी हैं। इसमें लगभग 10 हजार हेक्टेयर वन भूमि जाएगी।

वनों की वैध-अवैध कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। वन्य जीवों को विचरण में भी परेशानी आ रही है। उनका दायरा सिमट रहा है। नतीजतन टेरिटोरियल फाइट से प्रति वर्ष औसतन करीब 12 बाघ जान गंवा रहे हैं। शाकाहारी, अन्य वन्य जीव पर्याप्त जगह और चारागाह की समस्या के चलते गांव की तरफ भागते हैं। खेत की फेंसिंग में फंस जाते हैं या शिकार हो जाता है या फिर कुएं में गिर जाते हैं। हाईवे के चौड़ीकरण में हजारों हेक्टेयर वन भूमि चली गई। भोपाल-जबलपुर, भोपाल-बैतूल-नागपुर, जबलपुर-नागपुर, जबलपुर-शहडोल सहित करीब 6 एनएच चौड़े किए गए। इन मार्गों का 10-15 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्रों से निकलता है। प्रदेश में प्रति वर्ष अवैध कटाई के 44 हजार से ज्यादा केस दर्ज होते हैं। सबसे ज्यादा अवैध कटाई गांव के आसपास के जंगलों में होती है। लोग लकड़ी बेच देते हैं। वनभूमि को खेत में तब्दील कर उसमें खेती करना शुरू कर देते हैं।

पिछले 10 से 15 सालों के अंदर वन अधिकार पट्टे के तहत वनवासियों को 3 लाख 14 हजार भूमि दे दी गई। फिलहाल 50 हजार वनवासियों को वन अधिकार पट्टे देने की कार्रवाई फिर से की जा रही है। देखा जाए तो वन अधिकार पट्टों के अलावा 1980 से अब तक विभिन्न कार्यों के लिए करीब 2 लाख 90 हजार हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। 2010 से अब तक सिंचाई की 105, विद्युत की 69, खनिज की 43 अन्य की 154 परियोजनाओं के लिए वनों की कटाई की गई है। वन बल प्रमुख आरके गुप्ता का कहना है कि विकास कार्य भी जरूरी है। कार्यों के लिए दी जाने वाली वन भूमि के संबंध में कंपनसेशन का प्रावधान है। इसके तरह पौधरोपण की राशि और कुछ राजस्वभूमि उपलब्ध कराई जाती है। वहीं पूर्व वन बल प्रमुख राजेश श्रीवास्तव का कहना है कि केंद्र के प्रोजेक्ट में जमीन के बदले बिगड़े वनों में पौधरोपण के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाती है। राज्य के प्रोजेक्ट में जमीन के बदले जमीन दी जाती है।

प्रदेश के सिंगरौली जिले में कोयले की खुदाई की जानी है। इसके लिए यह इलाका एक निजी कंपनी को सौंपा गया है। दावा है कि सरई क्षेत्र के कई गांवों में अब निजी कंपनियों का कब्जा हो चुका है। जंगल काटकर अब कोयला खनन करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। जिले में कोयला खनन के लिए निजी कंपनियों को ब्लॉक आवंटित किया गया है। साथ ही अब निजी कंपनियां भी खनन के लिए आ रही हैं।

बताया जा रहा है कि जल्द से जल्द कोयला खनन की तैयारी में लगी कंपनियों द्वारा वन विभाग और राजस्व सहित निजी भूमि पर मौजूद लाखों की संख्या में पेड़ों को धराशायी किया जाएगा। पर्यावरण संतुलन खतरे में पड़ गया है। पेड़ों की कटाई की वजह से सालों बाद पिछले महीने 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा तापमान पर्यावरण असंतुलन का नतीजा माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नियमानुसार खनन के लिए कोल ब्लॉक आवंटित होने के बाद जंगली क्षेत्र से दो गुना रकबा कंपनियों को वन विभाग को देना पड़ता है। साथ ही पौधरोपण के लिए खर्च भी अदा करना पड़ता है। वन विभाग पौधरोपण कराता है। यही प्रक्रिया राजस्व की जमीन में जंगल होने पर पूरी की जाती है। नियम-शर्तों का फायदा उठाते हुए निजी कंपनियां जंगल भले सिंगरौली का उजाड़ रही हैं, लेकिन पौधरोपण के लिए जमीन दूसरे जिलों में दी जा रही है। नतीजा सिंगरौली को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। वन विभाग के डीएफओ मधु वी राज ने बताया कि कोयला खनन के लिए आने वाले कंपनियों को वन भूमि पर खनन की अनुमति इसी शर्त पर दी जाती है कि वह बदले में जमीन व पौधरोपण के लिए खर्च देंगी। एक कंपनी से अभी हाल में रकम मिली है। जमीन संजय टाइगर रिजर्व और बगदरा सहित कई इलाकों में चिह्नित है। पौधरोपण की प्रक्रिया शुरू है, बाकी की कंपनियों की प्रक्रिया प्रचलन में हैं।

● **जय सिंह**

जंगलों में धड़ल्ले से काटा जा रहा सागौन

वन माफिया जहां सागौन के जंगल साफ कर रहे हैं वहीं पेड़ काटने के बाद जंगल की जमीन पर अतिक्रमण भी करवा रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सीहोर जिले में सामने आया है। यहां के ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद अभी तक वन विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की है। सीहोर जिले का कुल क्षेत्रफल 6578 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें से 1520 वर्ग किलोमीटर में सागौन के वृक्षों का बेशकीमती जंगल है। वन अमले की मिलीभगत से माफिया लगातार जंगलों में सागौन के पेड़ों को काटकर उनकी जगह खेती की जमीन तैयार कर रहे हैं। ग्रामीणों ने इस मामले की शिकायत वन विभाग से भी की, लेकिन आरोप है कि उन्होंने इससे पल्ला झाड़ लिया है। इस मामले में नया मोड़ उस समय आया जब जिले के नसरुल्लागंज ब्लॉक के वन परिक्षेत्र लाड़कुई के वन बीट सिंहपुर के कक्ष क्रमांक 428 में वन विभाग नाके से मात्र 100 मीटर की दूरी पर वन माफियाओं ने सागौन के पेड़ों को काटकर वहां पर अवैध अतिक्रमण कर लिया। जिले में फैले सागौन के जंगल को अतिक्रमणकारियों का स्वर्ग माना जाता है। जिले के वन अफसरों और कर्मचारियों की नाक के नीचे वन माफिया के हौंसले इतने बुलंद हो गए हैं कि रात में ट्रैक्टर से वन भूमि पर जुताई कर खेती करने में लगे हैं। हैरत की बात ये है कि जब ग्रामीणों को इस अतिक्रमण की जानकारी है और वो शिकायत कर रहे हैं तो भला वन अमला क्यों इस ओर से मुंह मोड़ कर बैठा है। इस अतिक्रमण में वन विभाग के अफसरों पर मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं।

केंद्र सरकार के सहारे भाजपा

छत्तीसगढ़ में साल 2023 के नवंबर-दिसंबर में विधानसभा का चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव से पहले पिछले चुनावों के कड़वे अनुभवों को देखते हुए केंद्रीय भाजपा अभी से चुनावी मोड में आ चुकी है। दरअसल प्रदेश के नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि उनसे विधानसभा और संसदीय क्षेत्र में कमजोर बूथ की पहचान करें और उसे दुरूस्त करने के लिए कार्यक्रम सहित योजनाएं तैयार करें, जिसकी तैयारी भाजपा में शुरू हो चुकी है।

भाजपा के रायपुर सांसद सुनील सोनी ने कहा कि कमजोर बूथों की पहचान की जा रही है। उन बूथों पर केंद्र की योजनाओं को बताने का प्लान किया जा रहा है। क्योंकि इससे भ्रम फैलाने वाली कांग्रेस पार्टी से लड़ने यह एक बेहतर तरीका है। बता दें कि हाल ही में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली में एक बैठक आयोजित की। बैठक से लौटने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा था कि ऐसे राज्य जहां भाजपा की सरकार नहीं है या फिर वहां भाजपा की स्थिति ठीक नहीं है, उन राज्यों में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति बनाई गई है।

भाजपा भले ही अभी से मिशन 2023 में जुट गई हो, मगर छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल कांग्रेस इसे बेफिजूल मेहनत करार दे रही है। कांग्रेस प्रवक्ता राजू घनश्याम तिवारी का कहना है कि भाजपा कितना भी दम लगा ले कोई भी योजना बना ले, छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस के साथ है। इस बार भी जनता उनका ही साथ देगी। वहीं वरिष्ठ राजनीति विश्लेषक बाबूलाल शर्मा मानते हैं कि भाजपा की यह कवायद उसे संगठनात्मक रूप से मजबूती देगी, जिसका लाभ आने वाले दिनों में मिल सकता है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार की योजनाओं के सहारे राज्य की **सत्ता में वापसी** की कवायद भाजपा कर रही है। लगातार 15 सालों तक सत्ता में रहने वाली भाजपा 2018 की हार को भुलाते हुए 2023 में सत्ता में वापसी करना चाहती है, जिसकी तैयारी अभी से शुरू हो चुकी है। ऐसे में भाजपा की यह कवायद कितना रंग लाएगी यह तो वक्त तय करेगा। फिलहाल इतना तो तय है कि भाजपा की इस तैयारी से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज है।

पिछले 15 सालों तक सत्ता में रहने वाली छत्तीसगढ़ भाजपा को साल 2018 के विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा। इन चुनावों में मिली हार के बाद भाजपा इतनी हताश और निराश हो गई कि आज तक कोई बड़ी जीत हासिल नहीं कर पाई है। चार-चार उपचुनाव सहित नगरीय निकाय चुनावों में भाजपा को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इसको लेकर अब पार्टी आलाकमान ने संज्ञान लिया है। माना जा रहा है कि बीते दिनों दिल्ली में चार बड़े चेहरों को तलब किया गया था। जिसमें डॉ. रमन सिंह, धरमलाल कौशिक, विष्णुदेव साय और पवन साय शामिल थे। सूत्रों की मानें तो चारों को चेहरा परिवर्तन का कड़ा संदेश दे दिया गया है। कहा गया है कि आप बेहतर विकल्प तलाश कीजिए वरना नाम सीधे ऊपर से तय किया जाएगा। बहरहाल छत्तीसगढ़ भाजपा की स्थिति पर दिल्ली में हुए मंथन के बाद सूबे में सियासत गर्म है। राजनीतिक जानकारों की मानें तो भाजपा चाहे चेहरा बदलने की बात कहे या नेतृत्व परिवर्तन, मगर सच्चाई यह है कि आज भी रमन सिंह के चेहरे से बड़ा चेहरा भाजपा के पास मौजूद नहीं है।

छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद भाजपा ने बतौर विपक्ष तीन सालों तक सरकार और सत्ताधारी दल कांग्रेस के खिलाफ ऐसा माहौल बनाया कि 15 सालों तक सत्ताशीन रही। मगर साल 2018 के बाद आज तक भाजपा उस फॉर्म में नजर नहीं आई। यही वजह है कि अब चेहरा सहित नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा आम हो चली है। बहरहाल भाजपा की अंदरूनी स्थिति से सत्ताधारी दल कांग्रेस की बांछे खिल गई हैं। वहीं भाजपा बचाव करती नजर आ रही है। कांग्रेस कह रही है कि भाजपा के नेता 15 सालों तक सत्ता की मलाई खाते रहे और सभी पर कमोबेश भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसी कारण चेहरा कोई भी आरोप तो पहले से ही तय हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव का दावा है कि भाजपा संगठन आधारित पार्टी है ना कि चेहरा आधारित। भाजपा में चेहरे और नेतृत्व पर चर्चा के बीच एक सच्चाई यह भी है कि जब साल 2000 में राज्य गठन हुआ था तब डॉ. रमन सिंह ना तो प्रदेश के चेहरे थे और ना ही नेतृत्व। इसके बाद भी भाजपा ने विपक्ष के तौर पर यहां जमकर माहौल बनाया।

● **रायपुर से टीपी सिंह**

नए चेहरों की तलाश में भाजपा

भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अंदरूनी कलह और गुटबाजी से ग्रस्त अपनी छत्तीसगढ़ इकाई को कठोर संदेश देते हुए कहा है कि वह अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सभी मतभेद दूर करे। पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में नए नेतृत्व की संभावना तलाश रही है। भाजपा ने 2003 से 2018 तक 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ पर शासन किया। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. रमन सिंह 15 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे। छत्तीसगढ़ में भाजपा की राजनीति लगभग दो दशकों तक रमन सिंह के इर्द-गिर्द घूमती रही और उनका अब भी काफी प्रभाव है। पिछले महीने हुए उपचुनावों में हार ने अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा में चिंता बढ़ा दी है। भाजपा को सबसे बड़ी चिंता खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र को लेकर है, क्योंकि यह पूर्व मुख्यमंत्री सिंह के गृह जिले के अंतर्गत आता है। पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा, खैरागढ़ में मिली हार ने रमन सिंह के नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े किए। नतीजे बताते हैं कि वह अपनी पकड़ खोते जा रहे हैं। ऐसे में पार्टी को छत्तीसगढ़ में नेतृत्व की भूमिका के लिए नए चेहरों की तलाश है। पिछले महीने, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ के नेताओं के साथ राज्य में पार्टी मामलों पर विचार-विमर्श किया। सूत्रों ने दावा किया कि केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ भाजपा के कामकाज से खुश नहीं है और वर्तमान स्थिति के लिए राज्य नेतृत्व की खिंचाई की। उन्होंने कहा, राज्य भाजपा नेतृत्व ने स्पष्ट किया है कि पार्टी अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए मुख्यमंत्री पद का चेहरा पेश नहीं करेगी। एक वरिष्ठ नेता को पार्टी के चुनाव अभियान के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया जाएगा और उन्हें चुनाव संबंधी सभी मामलों के प्रबंधन के लिए पूरी छूट दी जाएगी।

भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि और प्रथम नागरिक होता है। इस बार राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। इस बार के राष्ट्रपति चुनाव को सत्तापक्ष और विपक्ष की राजनीति का शक्ति परीक्षण माना जा रहा है। भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने जहां द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है तो विपक्षी खेमे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उतारा है। प्रत्याशी चयन में ही एनडीए ने जो आदिवासी कार्ड खेला है, उससे विपक्ष दो खेमों में बंट गया है।

● राजेंद्र आगाल

राष्ट्रपति चुनाव, ये महज देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान होने वाले व्यक्ति का चुनाव नहीं है, बल्कि मिशन 2024 यानी लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष का प्रैक्टिस मैच भी है। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि उसमें विपक्ष पूरी तरह उलझकर रह गया है। मोदी-शाह के आगे, विपक्ष एक क्षत्रप तक नहीं ढूंढ पा रहा है, जो मिशन 2024 में उनका नेतृत्व कर सके। राष्ट्रपति चुनाव, जिसे 2024 का प्रैक्टिस मैच माना जा रहा है, उसके लिए विपक्षी टीम को पर्याप्त संख्या में सियासत के खिलाड़ी तक नहीं मिल पा रहे हैं। जो मिले भी हैं, उनमें टीम भावना और तालमेल का अभाव है। दरअसल, मुख्य विपक्षी पार्टियां एकता का राग तो अलापती हैं, लेकिन वे इस कोशिश में रहती हैं कि **गठबंधन** में उनका वर्चस्व कायम रहे। राष्ट्रपति चुनाव से पहले की यह स्थिति आगामी लोकसभा चुनाव के हालात बयान करने के लिए काफी है।

कांग्रेस मुक्त भारत में भाजपा सफल

भाजपा ने पहले कांग्रेस मुक्त भारत की घोषणा की थी। पार्टी उसमें काफी हद तक सफल भी रही है। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों ने बहुत हद तक इस तस्वीर को साफ कर दिया है। भाजपा के रणनीतिकार इस बात को अच्छे से समझ चुके हैं कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्ष, बिखराव की राह पर जा सकता है। कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दलों की इसी कमजोरी का फायदा भगवा टोली उठा रही है। अब इसके निशाने पर वे राज्य हैं, जहां गैर भाजपा दलों की सरकारें हैं। वहां पर किसी न किसी तरह, विवाद खड़ा कर भाजपा, खुद को पिक्चर में ला रही है। महाराष्ट्र इसका ताजा उदाहरण है। गोवा में भी प्रयास हुआ है। भले ही वर्तमान में पंजाब की सियासत के प्लेटफार्म पटल पर भगवा टोली कहीं नहीं ठहरती, लेकिन उसने 2024 की तैयारी शुरू कर दी है।

राजनीतिक जानकार कहते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव, विपक्षी एकता परखने के लिए एक प्रयोग है। अभी तक इसमें विपक्ष चारों खाने चित रहा है। महाराष्ट्र में सत्ता से बाहर हो चुकी शिवसेना ने भी एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दे दिया है। संभवतया चुनाव के दिन तक कई दूसरे विपक्षी दल भी यूपीए प्रत्याशी यशवंत सिन्हा का साथ छोड़कर, मुर्मू के समर्थन में न खड़े हो जाएं। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में बीजेडी और वाईएसआर, कांग्रेस के साथ कैसे आएंगे। शरद पवार और फारुख अब्दुल्ला ने राष्ट्रपति चुनाव में अपना नाम क्यों नहीं आगे बढ़ाया। यहां कई समस्याएं हैं। विपक्षी दल राष्ट्रपति चुनाव या लोकसभा चुनाव में एक हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद विधानसभा में क्या होगा। वहां तो सभी अलग-अलग ही लड़ेंगे। वह सोच, इन्हें अब एकत्रित नहीं होने दे रही है। देश के वर्तमान राजनीतिक हालात को देखें तो विपक्षी एकता में यही सोच, सबसे बड़ी बाधा है।

विपक्ष में एक सूत्रधार की कमी

कांग्रेस में ऐसा कोई क्षत्रप नहीं है, जो विपक्ष को एक प्लेटफार्म पर ला सके। सोनिया गांधी और राहुल गांधी सहित कई कांग्रेसी अभी ईडी के रडार पर हैं। भले ही चुनाव में विपक्ष को, भाजपा से अधिक वोट मिलते हैं, लेकिन बिखराव के चलते उनकी कीमत जीरो हो जाती है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, के चंद्रशेखर राव और अखिलेश, ये सब खुद को आगे रखना चाहते हैं। सामान्य विचार बन ही नहीं पाता। तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख के चंद्रशेखर राव, कांग्रेस के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। 2014 व 2019 के मुकाबले 2024 में विपक्ष के सामने बड़ी चुनौती है। उस वक्त आम राय थी कि एनडीए को हराना है। आज भाजपा से टकराव है। प्रशांत किशोर को देखकर लगता था कि वे विपक्ष को एक मंच पर ला सकते हैं, लेकिन वे भी अलग-थलग पड़ गए। विपक्ष में इच्छा शक्ति नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कल्पना के खेल में ही रहे। अब तो क्षेत्रीय दल ही कांग्रेस को हाशिये पर ले जाने लगे हैं। विपक्ष में एक सूत्रधार की कमी है। चंद्रबाबू नायडू व दूसरे कई लोगों ने कोशिश की थी, मगर फेल हो गए। कांग्रेस, एकला चलो पर आगे बढ़ना चाहती है। ऐसे समय में बड़ी पार्टी पहल करती है, लेकिन कांग्रेस तो अपने ही घर में घिरी है। कहीं ऐसा न हो कि पहले आप, पहले आप के चक्कर में 2024 भी विपक्ष के हाथ से न निकल जाए।

भारत का राष्ट्रपति देश का सर्वोच्च प्रतिनिधि और प्रथम नागरिक होता है। इस समय राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार अभियान चल रहा है। भाजपा नेतृत्व वाले राजग ने जहां द्रौपदी मुर्मू को प्रत्याशी बनाया है तो विपक्षी खेमे ने पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को उतारा है। विपक्षी प्रत्याशी की हार निश्चित दिख रही है। शायद इसी से खिन्न सिन्हा ने शिगूफा छेड़ा है कि राष्ट्रपति रबर स्टाम्प नहीं होना चाहिए। उनका संकेत मुर्मू की ओर है, लेकिन शायद वह भूल गए मुर्मू झारखंड की राज्यपाल रही हैं।

जिंदगी में पहली बार हुआ ऐसा स्वागत

समर्थन मांगने भोपाल पहुंचीं एनडीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत के हृदय पावन मप्र ने मुझे जिस तरह का स्वागत दिया, ये भव्य स्वागत मेरी जिंदगी में पहली बार हुआ है। इसे मैं कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मप्र की जनता को भी नमन करती हूं। मैंने मेरे लिए नहीं, इस देश की जनता को गर्व महसूस कराने के लिए राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनने के लिए हां भरी। मुर्मू ने कहा कि मेरे आगे-पीछे कोई नहीं है। देश की जनता के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए काम करना है। मैं अपने संवैधानिक दायरे में रहकर सेवा करने को तैयार हूं। मुझे खुशी है कि आज संगठन के अलावा दूसरे दल भी मुझे समर्थन देने के लिए आगे आ रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज आनंद और प्रसन्नता का विषय है। द्रौपदी मुर्मू औपचारिक रूप से राष्ट्रपति नियुक्त होंगी, जिस तरह से कई दल समर्थन कर रहे हैं। शिवसेना ने समर्थन कर दिया, आंध्रप्रदेश में तो सारे के सारे वोट उन्हीं के पक्ष में जा रहे हैं। भाजपा ने भी समर्थन किया। एक नहीं कई दल समर्थन लगातार करते जा रहे हैं। शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं कि पहली बार एक जनजातीय आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा, मुर्मूजी के जीवन की आप गहराई देखेंगे तो संघर्षों से भरा, संयमपूर्ण और दृढ़-संकल्प वाला रहा है। आपकी जानकारी में होगा उनके पति का स्वर्गवास हुआ, जिसके बाद वे टूटी नहीं। उन्होंने हिम्मत रखी, दो बेटे एक्सीडेंट में चले गए उसके बाद भी हिम्मत नहीं हारी। शिक्षक रहते हुए फिर वे भाजपा के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में आईं।

यह है वोट का गणित

राष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं। 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में से 233 सांसद ही वोट डाल सकते हैं। लोकसभा के सभी 543 सदस्य वोटिंग में हिस्सा लेंगे, जिनमें वो भी सीटें शामिल हैं जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के कुल 4 हजार 33 विधायक भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डालेंगे। राष्ट्रपति चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या फिलहाल 4 हजार 809 होगी। हालांकि, इनके वोटों की वैल्यू अलग-अलग होती है। इस तरह से लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा

सदस्यों के वोटों की वैल्यू मिलाकर देखते हैं तो वोटर्स के वोटों की कुल वैल्यू 10 लाख 86 हजार 431 होती है। इस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में जीत के लिए आधे से एक वोट ज्यादा की जरूरत होगी। यानी, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए कम से कम 5,43,216 वोट चाहिए होंगे।

किसका पलड़ा भारी?

राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने वाले इन सियासी गठबंधनों की ताकत की बात करें तो कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के पास फिलहाल 23 फीसदी के लगभग वोट हैं जबकि भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास लगभग 48 प्रतिशत वोट हैं। ऐसे में यूपीए के मुकाबले में तो भाजपा को बड़ी बढ़त हासिल है, लेकिन अगर सभी विपक्षी दल मिलकर संयुक्त तौर पर कोई उम्मीदवार खड़ा करते हैं तो सियासी समीकरण बदल जाएंगे। देश के सभी क्षेत्रीय दल उसे अपना समर्थन देते हैं तो एनडीए के उम्मीदवार के लिए समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि भाजपा विरोधी सभी दलों के एकजुट होने की स्थिति में उनके पास एनडीए से करीब दो प्रतिशत ज्यादा यानी 51 प्रतिशत के लगभग वोट हो जाते हैं। इसलिए भाजपा नेतृत्व इसी दो प्रतिशत वोट की खाई को पाटने के मिशन में जुट गया है तो विपक्षी दल साझा उम्मीदवार को उतारने के लिए मशक्कत शुरू कर दिए हैं।

किसके पास कितने वोट?

भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में जेडीयू, एआईएडीएमके, अपना दल (सोनेलाल), एलजेपी, एनपीपी, निषाद पार्टी, एनपीएफ, एमएनएफ, एआईएनआर कांग्रेस जैसे 20 छोटे दल शामिल हैं। इस तरह से एनडीए के पास कुल 10,86,431 में से करीब 5,35,000 मत हैं, जिसमें उसके सहयोगियों दलों को वोट शामिल हैं। मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से एनडीए को अपने राष्ट्रपति उम्मीदवार को जीत दिलाने के लिए 13 हजार वोटों की और जरूरत पड़ेगी। भाजपा और उसके सहयोगियों के पास कुल वोट का करीब 48 फीसदी वोट है। कांग्रेस के अगुवाई वाले यूपीए के पास अभी 2 लाख 59 हजार 892 वैल्यू वाले वोट थे। इनमें कांग्रेस के अलावा, डीएमके, शिवसेना, आरजेडी, एनसीपी जैसे दल शामिल हैं। वहीं, अन्य दलों के वोट को देखें तो 2 लाख 92 हजार 894 वोट हैं, जिनमें टीएमसी, सपा, वाईएसआर, टीआरएस, बीजेडी, आम आदमी पार्टी, लेफ्ट पार्टी शामिल हैं। इस तरह से विपक्ष के सारे दल एक साथ आते हैं तब उनका वोट करीब 51 फीसदी हो रहा है। इस तरह से विपक्षी दल एनडीए को टक्कर देने की स्थिति में नजर आएंगे। लेकिन विपक्षी पार्टियां दो फाड़ हो गई हैं। विपक्ष के एक और दल शिवसेना ने ममता बनर्जी की अगुवाई में खड़े किए गए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का साथ छोड़ दिया है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का फैसला किया है। शिवसेना के समर्थन के साथ अब यह तय हो गया है कि विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद की रेस में बहुत पीछे हो गए हैं और द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय है। और यह भी साफ है कि तृणमूल कांग्रेस नेता ममता बनर्जी की अगुवाई में विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश धराशायी हो गई है। विपक्ष का एकजुट नहीं हो पाना ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका है, जो कि आने वाले समय में उनके नेशनल प्लान के लिए सेटबैक साबित हो सकता है।

विपक्ष को एकजुट नहीं कर पाईं ममता

राष्ट्रपति पद के लिए जब ममता बनर्जी ने विपक्ष को एकजुट कर राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश की थी, तो शुरू से ही उनकी रणनीति फेल होती नजर आ रही थी। पहले उन्होंने एनसीपी प्रमुख शरद पवार को मनाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक

राष्ट्रपति चुनाव में वोट

राष्ट्रपति चुनाव में उप्र के विधायकों के मत का मूल्य सबसे ज्यादा है। इसके बाद तमिलनाडु और झारखंड का नंबर आता है। इन दोनों राज्यों के विधायकों के वोट का मूल्य 176 है। बिहार के विधायकों के वोट का मूल्य 173 है। प्रथम नागरिक के चयन के लिए जरूरी वोट मूल्य का न्यूनतम मान सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र, मेघालय, और मणिपुर का है। इन राज्यों के विधायकों के वोट का मूल्य क्रमशः 7, 8, 8, 9, 16, 17 और 18 है। राष्ट्रपति चुनाव में राज्य के विधायक के वोट का मूल्य इस प्रकार है:-

राष्ट्रपति चुनाव 2022

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	राज्य के मतों का कुल मूल्य
आंध्रप्रदेश	27,825
अरुणाचल प्रदेश	480
असम	14,616
बिहार	42,039
छत्तीसगढ़	11,610
गोवा	800
गुजरात	26,754
हरियाणा	10,080
हिमाचल प्रदेश	3,468
झारखंड	14,256
कर्नाटक	29,344
केरल	21,280
मप्र	30,130
महाराष्ट्र	50,400
मणिपुर	1,080
मेघालय	1,020
मिजोरम	320
नगालैंड	540
ओड़िशा	21,903
पंजाब	13,572
राजस्थान	25,800
सिक्किम	224
तमिलनाडु	41,184
तेलंगाना	15,708
त्रिपुरा	1,560
उत्तराखंड	4,480
उप्र	83,824
पश्चिम बंगाल	44,394
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	4,060
पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र	480
कुल	5,43,231

अब्दुल्ला और महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी ने भी उम्मीदवार बनने से इनकार कर दिया। उसके बाद ममता बनर्जी ने पूर्व भाजपा नेता और इस समय तृणमूल कांग्रेस के सदस्य यशवंत सिन्हा के नाम पर विपक्ष का समर्थन जुटाया। लेकिन यशंवत सिन्हा के खिलाफ विपक्ष की एकजुटता, भाजपा द्वारा एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के ऐलान के बाद से ही बिखरने लगे। और अब तक विपक्ष में बैठी शिवसेना, टीडीपी, बीजेडी, वाईएसआर कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, जेडी (एस), बहुजन समाज पार्टी ने समर्थन दे दिया है।

वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी मुर्मू के पक्ष में वोट डालने के संकेत हैं। हालांकि अभी तक उसने औपचारिक ऐलान नहीं किया है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों में बिखराव के बाद एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत लगभग तय हो गई है। क्योंकि एनडीए के पास पहले से ही 48 फीसदी से ज्यादा वोट है। और उसे बहुमत के लिए केवल 12-13 हजार वोटों की जरूरत थी। ऐसे में शिंदे गुट के अलावा शिवसेना, बीजू जनता दल वाईआरएस कांग्रेस, बसपा, तेलगुदेशम पार्टी, शिरोमणि अकाली दल, जेडी (एस), बसपा और अन्य गैर एनडीए दलों का समर्थन मुर्मू को मिल गया है तो एनडीए उम्मीदवार के लिए जीत के लिए जरूरी 5.43 लाख से ज्यादा वोट जुटाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस बार के चुनाव में इलेक्टोरल कॉलेज में 4809 सदस्य शामिल है। इनमें लोकसभा के 543, राज्यसभा के 233 और विधानसभाओं के 4033 सदस्य वोटिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे। इसके आधार पर चुनाव के लिए 10.86 लाख से ज्यादा वोट वैल्यू होगी।

असल में जब भाजपा ने एनडीए उम्मीदवार के रूप में आदिवासी उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को उतारा तो यह ऐसा दांव था, जो कि विपक्ष के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाला था। क्योंकि करीब 60 लोकसभा सीटों पर आदिवासी समुदाय का सीधा असर है। इस समय 543 सदस्यों वाली लोकसभा में 47 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा करीब 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर आदिवासी समुदाय का असर है। वहीं गुजरात, राजस्थान, मप्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, त्रिपुरा, झारखंड, मणिपुर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य हैं, जहां पर आदिवासी समुदाय का अच्छा खासा असर है। इसी चुनावी फायदे को देखते हुए अब ममता बनर्जी भी कह रही है कि अगर भाजपा ने उन्हें पहले बताया होता कि आदिवासी समुदाय से आने वाली द्रौपदी मुर्मू उम्मीदावर होंगी तो आम राय बन सकती थी। इस राजनीतिक दांवपेंच में सबसे ज्यादा नुकसान यशवंत सिन्हा और ममता बनर्जी को होता दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि तृणमूल कांग्रेस में होते हुए भी यशवंत सिन्हा अभी तक पश्चिम बंगाल में प्रचार करने नहीं गए हैं, जबकि वह तृणमूल कांग्रेस का गढ़ है। और अगर उन्हें चुनावों में बेहद कम वोट मिलते हैं तो उनके राजनीतिक कैरियर के साथ-साथ ममता बनर्जी के लिए झटका होगा, क्योंकि वह पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद से यही जताने की कोशिश कर रही है कि वह विपक्ष की अकेली नेता हैं जो 2024 में मोदी को चुनौती दे सकती हैं और विपक्ष को एकजुट कर सकती हैं।

कहां है विपक्षी एकता?

अब उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेगी। यह अपने आप में एक खबर है, क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि जिस भाजपा के चलते ठाकरे की सरकार चलती बनी, उसी भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन उन्हें करना पड़ रहा है। वे कहते हैं कि यह समर्थन उन्होंने मजबूरी में नहीं किया है। पहले भी उन्होंने प्रतिभा पाटिल और प्रणब मुखर्जी का समर्थन किया था, जबकि ये दोनों कांग्रेस के उम्मीदवार थे और शिवसेना भाजपा के साथ गठबंधन में थी। उद्धव ठाकरे का यह तर्क मजबूत दिखाई पड़ता है लेकिन इस बार दो कारण से जो पहले आजादी थी, वह अब शर्मनाक मजबूरी बन गई है। पहला तो यह है कि इस बार भाजपा ने आपको अपदस्थ कर दिया है। फिर भी आप उसके उम्मीदवार का समर्थन कर रहे हैं। दूसरा आपके सांसदों में से ज्यादातर ने साफ-साफ कह दिया है कि वे मुर्मू का समर्थन करेंगे। यदि ठाकरे अपने सांसदों की बात नहीं मानते तो उन्हें पता था कि वे सब दल-बदल करके भाजपा में शामिल हो जाते। अपनी बची-खुची पार्टी को बचाए रखने के लिए यही व्यावहारिक कदम था। अब यह स्पष्ट होता जा रहा है कि मुर्मू जीतेंगी और यशवंत सिन्हा हारेंगे। सिर्फ ठाकरे की शिवसेना ही नहीं कई राज्यों की प्रांतीय पार्टियां भी अब खुलकर मुर्मू के समर्थन में आ गई हैं। बहुजन समाज पार्टी, देवेगौड़ा का जनता दल, अकाली दल और झारखंड की जेएमएम भी भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करेगी। तेलंगाना राष्ट्र समिति ने सिन्हा के समर्थन की घोषणा की है लेकिन ओडिशा की पटनायक सरकार मुर्मू का समर्थन करेंगी। कोई आश्चर्य नहीं कि आप पार्टी के नेता भी मुर्मू का समर्थन कर दें, क्योंकि कांग्रेस के साथ उनकी पंजाब और दिल्ली में तगड़ी लड़ाई है।

ममता ने की विपक्षी एकता की अगुवाई

राष्ट्रपति के चुनाव में अब गिने-चुने दिन ही बाकी हैं। चुनाव से पहले ही एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। सिर्फ यह देखना बाकी है कि वो विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कितने वोटों से हराती हैं? द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनने वाली पहली आदिवासी महिला होंगी। इसलिए भाजपा उन्हें बड़े अंतर से चुनाव जिताना चाहती है। इसके लिए विपक्षी दलों में सेंधमारी का काम लगातार जारी है। पिछले कई चुनावों में सत्तापक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को 65 से 70 प्रतिशत और विपक्ष के उम्मीदवार को 30 से 35 प्रतिशत वोट मिलते रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति के चुनाव के ऐलान से पहले ही विपक्ष ने एक साझा उम्मीदवार उतारकर सत्तापक्ष के उम्मीदवार को हराने की रणनीति बनानी शुरू कर दी थी। इसकी पहल मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने तो नहीं की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विपक्षी एकता की अगुवाई कर रही हैं। इसे लेकर उन्होंने दिल्ली में सभी विपक्षी दलों की अहम बैठक बुलाकर साझा उम्मीदवार उतारने की रणनीति पर विचार किया था। लेकिन इस बैठक से आम आदमी पार्टी, टीआरएस, अकाली दल समेत 5 पार्टियों ने

किनारा कर लिया था। तभी विपक्षी एकता इस मसले पर दरकती नजर आने लगी थी। एनडीए की तरफ से द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के ऐलान के बाद विपक्षी एकता ताश के पत्तों की तरह बिखरती दिखने लगी। चुनाव आते-आते विपक्षी खेमे से कई और दलों के सत्तापक्ष की तरफ खिसकने की संभावना है।

राष्ट्रपति के चुनाव में भाजपा उप्र से लेकर महाराष्ट्र विपक्षी खेमे में सेंध लगाने में कामयाब रही है। उप्र में अखिलेश यादव राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर अपने गठबंधन को एकजुट नहीं रख पाए। न तो वो अपने चाचा शिवपाल को भाजपा के खेमे में जाने से रोक पाए और न ही अपने महत्वपूर्ण सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओमप्रकाश राजभर को। वहीं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे भी अपने सांसदों के दबाव में विपक्षी एकता को छोड़कर सत्तापक्ष के खेमे में चले गए हैं। बता दें कि शिवसेना के 18 में से 13 सांसदों ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की मांग की थी। उद्धव ठाकरे इस मांग को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए।

भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाकर चलने वाले ओडिशा के मुख्यमंत्री और भाजपा प्रमुख नवीन पटनायक ने सबसे पहले द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया था। राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए एनडीए के पास 13,000 वोटों की कमी थी। नवीन पटनायक के ऐलान के साथ ही उसे 31,000 अधिक वोट मिल गए थे। वहीं झारखंड में कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार चला रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन भी आदिवासी उम्मीदवार के नाम पर भाजपा की तरफ खिसक लिए। हेमंत सोरेन के समर्थन से एनडीए को 21,000 और वोटों की बढ़त मिल गई। उप्र में बसपा, सुभासपा और महाराष्ट्र में शिवसेना के एनडीए के साथ आने से उसके वोटों में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है। लेकिन भाजपा और खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मकसद राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत के इस अंतर को और बढ़ाना है ताकि संदेश दिया जा सके कि किसी आदिवासी महिला को देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठाने के उनके

फैसले का उनकी पार्टी और गठबंधन के अलावा बाहर से भी उन्हें व्यापक समर्थन मिला है।

बड़े अंतर से जीते थे अब्दुल कलाम

राष्ट्रपति का चुनाव साल पहले हुए राष्ट्रपति के चुनाव की याद दिला रहा है साल 2002 में हुए राष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए ने अपने उम्मीदवार डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को भारी बहुमत से जिताया था। भाजपा के सत्ता में रहते राष्ट्रपति का यह पहला चुनाव था। तब भी विपक्ष ने एकजुट होकर एनडीए के उम्मीदवार को नहीं जीतने देने की कसम खा रखी थी। लेकिन एनडीए की तरफ से डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में सामने आने के बाद विपक्षी एकता ताश के पत्तों की तरह बिखर गई थी। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी कलाम के विरोध की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। तब वामपंथी दलों ने कैप्टन लक्ष्मी सहगल को डॉ. कलाम के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा था। अपने उम्मीदवार के साथ वो अकेले ही चुनाव मैदान में खड़े रह गए थे। उस चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम को 4,152 वोट मिले थे। ये कुल पड़े वोटों का 89.6 प्रतिशत थे और इनकी कुल वैल्यू 9,22,884 थी। कैप्टन लक्ष्मी सहगल को सिर्फ 459 वोट मिले थे। ये कुल वोटों का 10.4 प्रतिशत थे और इनकी कुल वैल्यू 1,07,366 थी। पिछले 20 वर्षों में राष्ट्रपति का चुनाव इतने बड़े अंतर से जीतने वाले डॉ. कलाम अकेले राष्ट्रपति रहे। हालांकि उनसे पहले 1997 डॉ. केआर नारायणन भी बड़े अंतर से चुनाव जीते थे। लेकिन फर्क यह है कि नारायणन सत्तापक्ष और विपक्ष के साझा उम्मीदवार थे। उनके खिलाफ पूर्व चुनाव आयुक्त टीएन शेषन में निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था।

क्या हुआ था पिछले चुनाव में?

पिछला यानी 2017 में हुआ राष्ट्रपति का चुनाव एनडीए के सत्ता में रहते दूसरा चुनाव था। इस चुनाव में भाजपा ने अपने दूरगामी एजेंडे के तहत एक दलित को राष्ट्रपति बनाने का फैसला किया और रामनाथ कोविंद को अपना उम्मीदवार बनाया। कोविंद उस समय बिहार के राज्यपाल थे तब बिहार में जेडीयू और आरजेडी गठबंधन की सरकार चल रही थी। लेकिन नीतीश कुमार ने तब यूपीए के उम्मीदवार मीरा कुमार के बजाय एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद का समर्थन किया था। उसमें भी भाजपा ने विपक्षी खेमे में सेंध लगाकर रामनाथ कोविंद को बड़े अंतर से जिताया था। तब रामनाथ कोविंद को 65.65 प्रतिशत और मीरा कुमार को 34.35 प्रतिशत वोट मिले। कोविंद को मिले वोटों की वैल्यू 7,02,044 थी। जबकि मीरा कुमार को मिले कुल वोटों की वैल्यू 3,67,314 थी। इस बार भाजपा खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के उम्मीदवार की जीत का अंतर बढ़ाना चाहते हैं।

2007 में भी विपक्ष नहीं दिखा पाया था कमाल

हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता को लेकर आज भाजपा जिस तरह की बातें कर रही है विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने सत्तापक्ष के उम्मीदवार को हराने की हर मुमकिन कोशिश की। साल 2007 में भाजपा ने यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के ऐलान से पहले ही तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरो सिंह शेखावत को अपना उम्मीदवार घोषित करके चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी थी तब भाजपा को उम्मीद थी कि शेखावत के नाम पर देशभर ठाकुर सांसद और विधायक राष्ट्रपति पद के लिए उनका समर्थन कर देंगे। लेकिन तब कांग्रेस ने महाराष्ट्र की बेटी और राजस्थान की बहू और राजस्थान की ही राज्यपाल प्रतिभा सिंह पाटिल को चुनाव मैदान में उतारकर गेम पलट दिया था। उस चुनाव में प्रतिभा सिंह पाटिल को 65.8 प्रतिशत वोट मिले थे और भैरो सिंह शेखावत को सिर्फ 34.2 प्रतिशत वोट ही मिल पाए थे। प्रतिभा पाटिल को मिले कुल वोटों की वैल्यू 6,38,116 थी भैरो सिंह शेखावत को मिले वोटों की वैल्यू महज 3,31,306 ही थी। तब भाजपा का विपक्ष में रहते सत्तापक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को हराने का सपना चकनाचूर होकर बिखर गया था।

अब 'सहकारी क्षेत्र' पर नजर

आमूमन अमित शाह का नाम गृह मंत्रालय में कामकाज के उनके तौर-तरीकों या उनकी राजनीतिक रणनीतियों और उस पर अमल के मामले में बातचीत में उछल आता है। लेकिन सहकारिता मंत्रालय के मुखिया के नाते उनका राजकाज भी कम खास नहीं है और उसकी राजनीतिक संभावनाओं के लिए भी महत्व है। दशकों से भारतीय राजनीति में सहकारिता क्षेत्र को पैसों के घालमेल, राजनीति और विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, ताकि लोगों तक पहुंच बनाई जा सके और अपनी पार्टी की राजनीतिक पैठ बढ़ाई जा सके। नए मंत्रालय की गतिविधियों के मद्देनजर यह साफ है कि शाह का नया प्रेम सहकारी क्षेत्र है।

आजादी के बाद से ही भारत का सहकारिता क्षेत्र अपने समाजवादी और लोकतांत्रिक मूल्यों का वाहक रहा है और समावेशी विकास के मॉडल को ऐसे आगे बढ़ाता रहा है, जिसकी पैठ बाकी किसी की नहीं रही है। देश के सबसे नए केंद्रीय मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय में कोई विजिटर रूम नहीं है और 500 से भी कम आधिकारी-कर्मचारी हैं और करीब 900 करोड़ रुपए का बजट है, फिर भी सबसे महत्वाकांक्षी और व्यस्त मंत्रालयों में एक है। आखिरकार उसका काम रक्षा, वित्त से लेकर कपड़ा और नरेंद्र मोदी सरकार के सभी मंत्रालयों को छूता है। कृषि भवन में स्थित यह मंत्रालय 8 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसायटी (पीएसी), हजारों जिला और राज्य सहकारी समितियों के जरिए देश के विशाल शासन-प्रशासन के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाए उस पर विचार विमर्श कर रहा है।

शाह ने हाल ही में हर गांव, कस्बे और शहर में पहुंच के एजेंडे के साथ ज्ञानेश कुमार को सहकारिता मंत्रालय का सचिव बनाया है। संस्था के करीबी सूत्रों ने दावा किया कि शाह पीएसी के आधुनिकीकरण को तेज करना चाहते हैं और देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ इफ्को और अमूल जैसी स्थापित सहकारी संस्थाओं की कानूनी अड़चनों को दूर करना चाहते हैं। सूत्रों के मुताबिक, मोदी सरकार पीएसी के कारोबार का दायरा बढ़ाना चाहती है, उसके टर्नओवर में इजाफा करना चाहती है और उसे प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, कर्ज वितरण योजना (आईएसएस), फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और खाद तथा बीज वितरण का नोडल एजेंसी बनाना चाहती है। केंद्र की मंशा यह भी है कि पीएसी इस क्षेत्र में सार्वजनिक बैंक का एकाधिकार तोड़े।

कई सुधारों के बाद मोदी सरकार 400 से अधिक केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं, परियोजनाओं और सेवाओं के लिए पीएसी को आखिरी समांतर ढांचा बनाना चाहती है। दिलचस्प यह है कि पूंजीपतियों को मदद करने का आरोप झेलने वाली मोदी सरकार सहकारिता को शासन की रीढ़ बनाना चाहती है। मौजूदा हालात में सब नहीं तो कई पीएसी नाकारा, गोरखधंधे में लिप्त और भारी राजनीतिक असर में हैं। इसलिए सही दिशा में पहला कदम यह होगा कि उन्हें पारदर्शी बनाया जाए। प्राथमिक, जिला और राज्य सहकारिता बैंकों में निवेश तभी होगा, जब वे डिजिटल हों। इसके जरिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और यहां तक कि सचिव ज्ञानेश कुमार भी दिल्ली में बैठे सहकारी मंडलियों में कर्ज और जमा राशि का पता लगा सकेंगे। पिछले हफ्ते 29 जून को मोदी मंत्रिमंडल ने फैसला किया कि 63,000 पीएसी को 2,516 करोड़ रुपए की लागत से कंप्यूटरीकरण किया जाएगा, जिससे 13 करोड़ छोटे और सीमांत किसानों को लाभ होगा। 8.5 लाख सदस्यों वाले भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ के अध्यक्ष दिलीप संघाणी ने कहा, 'हम आधुनिक बन रहे हैं। हम प्राइमरी क्रेडिट सोसायटीज को 17 भाषाओं में सॉफ्टवेयर मुहैया कराएंगे। आपको याद रखना है कि हमारा फायदा कभी निजी हाथों में नहीं जाता।'

सहकारिता क्षेत्र से अमित शाह का यह पहला सबक नहीं है। वे 90 के दशक में गुजरात के सहकारी क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। वे सुर्खियों में तब आए, जब वे अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट सहकारिता बैंक के चेयरमैन बने, जो (भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन से) दिवालिएपन की कगार पर था। लेकिन उन्होंने जल्दी ही उसे राज्य में सबसे मुनाफे वाले सहकारी बैंकों में बदल दिया। वे कामयाब सहकारी संस्थाओं के कल-पुर्जे, स्थानीय अर्थव्यवस्था और दलगत राजनीति में उसके फायदों से बखूबी वाकिफ हैं। सहकारी संस्थाओं पर कब्जे का मतलब है उस 'भीड़' तक पहुंच, जिससे नेताओं को खासा लगाव है।

सो, शाह देश में सहकारी क्षेत्र को नया अवतार देने के लिए हड़बड़ी में हैं। मंत्रालय ने हाल ही में आधुनिकीकरण की अपनी कोशिशों के लिए स्थानीय भाषाओं में वेब पोर्टल लॉन्च किया। उसने पहली बार राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार करने के लिए एक लाख से अधिक सहकारिता सदस्यों के लिए राष्ट्रीय कानक्लेव का भी आयोजन किया। राष्ट्रीय सहकारिता यूनिवर्सिटी भी आने वाली है। सहकारिता में विभिन्न स्तरों पर मैनेजरों की ट्रेनिंग का व्यापक कार्यक्रम भी चल रहा है। सहकारिता क्षेत्र के लिए कई कानूनी संशोधन भी किए जाएंगे, ताकि सरकार उन्हें कारोबार देने के लिए अधिक जोखिम उठा सके।

● धर्मेंद्र सिंह कथूरिया

लक्ष्यों पर नजर

प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की सहकारी क्षेत्र में दिलचस्पी जाहिर है कि ये राजनीति के खेल का हिस्सा है। सहकारी क्षेत्र में 30 करोड़ देशवासी जुड़े हुए हैं। महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक इसके अग्रिम मोर्चे पर हैं। केरल और उप्र जैसे कई दूसरे राज्य भी अपने सहकारी क्षेत्र को व्यापक बनाने की जोरदार कोशिश कर रहे हैं। पीएसी संस्थाओं का सालाना टर्नओवर करीब 8 लाख करोड़ रुपए है। शहरी सहकारिता बैंकों का कारोबार करीब 5 लाख करोड़ रुपए बैठता है। मोदी सरकार डिजिटलीकरण के सहारे गांव से लेकर शहर सहकारी क्षेत्र को 30 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। सरकार चाहती है कि सहकारी क्षेत्र कमाई और रोजगार के मामले में कॉर्पोरेट क्षेत्र को होड़ दे।

संसद का मॉनसून सत्र शुरु होने को है। तो नेता लोग हो जाएं सावधान! नहीं...नहीं... बारिश और खराब ड्रेनेज सिस्टम या बरसात से लगने वाले जाम से नहीं, बल्कि संसद के दोनों सदनों में अभद्र भाषा के इस्तेमाल से सावधान हो जाएं। क्योंकि असंसदीय शब्दों की नई सूची तैयार की गई है। जिनके बोलने पर लोकसभा और राज्यसभा में मनाही होगी। दरअसल, पिछले कुछ सालों से संसद में अप्रिय और असंसदीय शब्दों का चलन तेजी से बढ़ गया था। अतः इन पर रोक लगाना आवश्यक था।

अब असंसदीय शब्दों पर बैन

संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इस बार संसद में भारतीय सभ्यता और संस्कृति के रंग में नेता दिखेंगे। यानी वे अपशब्द बोलने से कतराएंगे। ऐसा इसलिए कि अब संसद की कार्यवाही से असंसदीय शब्दों को हटा दिया गया है। सबसे बड़ी परेशानी की बात ये है कि इस लिस्ट में ऐसे कॉमन शब्द शामिल किए गए हैं जिनका आम बोलचाल में धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। ऐसे में नेतोओं को और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी।

अब सोचिए कोई विपक्षी सांसद अगर कह दे कि सरकार तानाशाह हो गई है या सत्तापक्ष का कोई सांसद कहे कि विपक्ष तानाशाही कर रहा है। तो संसद के नए नियमों के अनुसार इन दोनों ही शब्दों को यानी तानाशाह और तानाशाही को असंसदीय माना जाएगा और इस संबोधन को संसद की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। कोई सांसद किसी को विनाश पुरुष या खालिस्तानी नहीं बोल पाएगा। आपको याद होगा कुछ समय पहले कुछ शब्दों के बाद जीवी शब्द लगाकर बोलने का बड़ा चलन हुआ था। लेकिन अब संसद में जीवी वाला एक शब्द तो बैन हो जाएगा और वो है - जुमलाजीवी। ये शब्द असंसदीय माना जाएगा।

लोकसभा और राज्यसभा में 18 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र में ये नियम लागू हो जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी एक नई बुकलेट में कहा गया है कि शकुनि, खून से खेती, ढिंढोरा पीटना और बहरी सरकार जैसे शब्दों को असंसदीय माना जाएगा। यानी कि संसद की कार्यवाही के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। इसका अर्थ है कि संसद में डिबेट अथवा किसी अन्य मौके पर अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो इसे सदन की कार्यवाही से हटा दिया जाएगा। देश में अलग-अलग विधानसभाओं में अध्यक्ष द्वारा समय-समय पर कुछ शब्दों और अभिव्यक्तियों को असंसदीय घोषित किया जाता है।

इन शब्दों की सूची को भी लोकसभा सचिवालय द्वारा संदर्भ के लिए संकलित किया गया है। राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष के पास इन शब्दों और भावों को सदन की कार्यवाही से हटाने का अंतिम अधिकार होगा। इस सूची में कहा गया है कि कुछ शब्द तब तक अंससदीय मालूम नहीं पड़ते जब तक कि संसदीय कार्यवाही के दौरान इन्हें अन्य संबोधन के साथ मिलाकर नहीं देखा जाता है।

अध्यक्ष व सभापति पर आरोप को लेकर भी कई वाक्यों को असंसदीय श्रेणी में रखा गया है। इसमें आप मेरा समय खराब कर रहे हैं, आप हम लोगों का गला घोंट दीजिए, चेयर को कमजोर कर दिया है और ये चेयर अपने सदस्यों का संरक्षण नहीं कर पा रही है, आदि शामिल हैं। अगर कोई सदस्य पीठ पर आक्षेप करते हुए ये कहता है कि जब आप इस तरह से चिल्लाकर वेल में जाते थे, उस वक्त को याद करूं या आज जब आप इस आसन पर बैठे हैं तो इस वक्त को याद करूं। तो ऐसी बातों को असंसदीय मानते हुए इन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

अब संसद में कोई कायर नहीं बोल सकता!

कायर शब्द भी अब संसद की वर्जित सूची में शामिल किया जा चुका है। आपको याद होगा, एक बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दफ्तर में सीबीआई का सर्च अभियान चल रहा था। 15 दिसंबर, 2015 को ट्विटर पर अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कायर और मनोरोगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। मामला कोर्ट में भी गया पर अदालत ने इसे न तो अपमानजनक माना न ही देशद्रोह का, लेकिन आगे से संसद में कोई कायर शब्द का इस्तेमाल करता है तो उसे असंसदीय माना जाएगा और अरविंद केजरीवाल को भी ये सब बोलने के लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। एक वकील ने केजरीवाल की टिप्पणी के लिए अदालत से आईपीसी की धारा-124 ए (देशद्रोह) और धारा-500 (मानहानि) के तहत मुकदमा चलाने की मांग की थी। वकील ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल के बयान में देशद्रोह की भावना छिपी थी, जिसने प्रधानमंत्री के खिलाफ नफरत और अवमानना का प्रसार किया है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायत वाली याचिका ये कहते हुए खारिज कर दी कि अरविंद केजरीवाल ने राज्य की शांति भंग करने या फिर संप्रभुता को नुकसान पहुंचाने जैसा कोई काम नहीं किया।

वो कहते हैं ना कि आप बोलते हैं न बोलते रहिए। बोलना जरूरी है और बोलना हमारी आजादी भी है। लेकिन बोलते वक्त शब्दों का चयन बहुत जरूरी होता है। हम इंसान हैं। कुछ न कुछ ऐसा बोल ही जाते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हमारा बोलना और सांसदों का संसद में बोलना, दोनों में बड़ा अंतर है। संसद में बोली गई बातें हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती हैं। हमारी तरह हमारे सांसद भी इंसान ही हैं। वो भी यदा-कदा कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उन्हें नहीं बोलना चाहिए। अब इसकी पहचान कैसे हो कि संसद में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं इसलिए एक लिस्ट बनाई गई ऐसे शब्दों की जिसे संसदीय भाषा में असंसदीय कहा जाता है।

आपने कभी सोचा है कि पहला असंसदीय शब्द क्या हो सकता है। सोचिए जरा अजी वो ऐसा शब्द है या यूं कह लीजिए किरदार है जो लगभग हर किसी की जिंदगी में आता ही है। चलिए छोड़िए ये बताइये आपकी शादी हो गई? नहीं हुई तो भी कोई बात नहीं। आपके नाना की बातें तो आपको याद होंगीं। आप आपने नाना के बड़े लाडले रहे होंगे...अजी! नाना होंगे आपके लिए लेकिन वो रिश्ते में आपके पिताजी के क्या लगते हैं...ठीक कहा...ससुर।

मप्र विधानसभा में अगस्त 2021 को एक किताब का विमोचन किया गया था। ये किताब असंसदीय शब्दों का एक संग्रह है। इस बुकलेट में 1161 असंसदीय शब्द रखे गए हैं। इसके अलावा उस शब्द के आगे वो तारीख भी लिखी गई है, जिस तारीख को असंसदीय शब्द मानकर उस शब्द को हटाया गया है। इसमें पहला शब्द ससुर है जो 23 सितंबर 1954 को इस्तेमाल हुआ था। गंदी सूरत शब्द 2 अक्टूबर 1954 को इस्तेमाल किया गया था। इसमें आखिरी शब्द मिस्टर बंटाधार है। ये 16 मार्च 2021 को इस्तेमाल हुआ था। अब आपको असंसदीय शब्दों के नियम और कानून बताएं उससे पहले मप्र विधानसभा की कुछ असंसदीय शब्दों की लिस्ट दिखाते हैं। इनमें कुछ शब्द सुनकर आपको हंसी आएगी और कुछ हैरान कर देंगे। चोर मचाए शोर, मिर्ची लग गई, दादागिरी नहीं चलेगी, आप 302 हत्या के मुलजिम हो, मंत्री की बहू ने आत्महत्या कर ली, शर्म करो, यह झूठ का पुलिंदा है, बंधुआ मजदूर, चमचा, भेदभाव, वेंटीलेटर, चापलूस, नौटंकी, पप्पू, माई का लाल, मुक्का मारा, व्यभिचारी, शर्मनाक, पप्पू पास हो जाएगा, चड्डी वाला, गोलमाल, मुर्गा और दारू में पैसे खत्म कर देते हैं, सोच में शौच भरा है, फर्जी पत्रकार, आपने चड्डी पहनी है क्या? इन असंसदीय शब्दों को सुनकर क्या आपको मिर्ची लगी या फिर आपको हंसी आई... हंसी ही आई होगी। चलिए अब बात करते हैं नियमों की।

हिंदी या अंग्रेजी समेत विभिन्न भारतीय भाषाओं में कई ऐसे शब्द हैं, जिन्हें असंसदीय माना गया है। लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति का काम सदन की कार्यवाही के रिकॉर्ड से इन शब्दों को दूर रखना होता है। इसके लिए नियम 381 के मुताबिक, सदन की कार्यवाही का जो हिस्सा हटाना होता है, उसे मार्क किया जाएगा और कार्यवाही में एक फुटनोट इस तरह से डाला जाएगा कि अध्यक्ष के आदेश के मुताबिक उसे हटा दिया जाए। इस पूरी प्रक्रिया में मदद के लिए लोकसभा सचिवालय ने असंसदीय अभिव्यक्ति नाम से एक किताब भी निकाली हुई है। इस किताब को सबसे पहले साल 1999 में तैयार किया गया था। साल 2004 में इस किताब का नया एडिशन आया था इसमें 900 पन्ने थे। इस सूची में कई शब्द और एक्सप्रेशन्स शामिल हैं जिन्हें देश की ज्यादातर भाषाओं और संस्कृतियों में असभ्य या अपमानजनक माना जाता है।

हालांकि इसमें कुछ ऐसे भी शब्द शामिल हैं, जिनके बारे में बहस की जा सकती है कि ये ज्यादा नुकसानदायक नहीं हैं। इस किताब को तैयार करने के दौरान आजादी से पहले केंद्रीय विधानसभा, भारत की संविधान सभा, प्रोविजनल संसद, पहली से दसवीं लोकसभा और राज्यसभा, राज्यों की विधानसभा और कॉमनवेल्थ संसदों की बहसों से वो संदर्भ लिए गए थे, जिन्हें असंसदीय घोषित किया गया था।

एक खास बात ये है कि कुछ शब्द जैसे शिट, बदमाशी, स्कमबैग और बैंडीकूट आदि शब्दों को अगर कोई सांसद किसी और के लिए इस्तेमाल करता है तो उसे असंसदीय माना जाएगा, लेकिन अगर वो अपने लिए करता है तो ये चल सकता है। वहीं अगर कार्यवाही को कोई महिला अधिकारी संचालित कर रही हैं, तो कोई भी सांसद उन्हें प्रिय अध्यक्ष कहकर संबोधित नहीं कर सकता है। रिश्वत, रिश्वतखोरी, ब्लैकमेल, डकैत, चोर, डैम, डार्लिंग जैसे सभी शब्द असंसदीय माने जाते हैं।

भारतीय राजनीति में समय के साथ-साथ राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। सदन के अंदर एक-दूसरे की आलोचना करने में कोई बुराई नहीं लेकिन इस आलोचना का एक दायरा होना चाहिए। कई बार तो नेताओं ने ऐसे-ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसे दोबारा न तो लिखना सही है और न ही उनका जिक्र करना। महुआ मोइत्रा समेत कई नेताओं ने सरकार के नए असंसदीय शब्दों पर सवाल खड़ा किया है। उनका इशारा साफ है कि सरकार अपनी आलोचना भी सुनना पसंद नहीं करती इसलिए तानाशाही और जुमलाजीवी जैसे शब्दों को भी असंसदीय मान रही है।

● **विपिन कंधारी**

क्या कहता है नियम ?

संविधान के आर्टिकल 105 (2) में साफ निर्देश है कि संसद सदस्यों को इस तरह की आजादी नहीं होती कि सदन की कार्यवाही के दौरान कोर्ट या कमेटी के सामने कुछ भी बोल दें, सदन के अंदर अनुशासन कायम रखना होता है। लोकसभा में प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के नियम 380 (एक्सप्रेशन) के मुताबिक, अगर अध्यक्ष को लगता है कि बहस में अपमानजनक, असंसदीय, अभद्र या असंवेदनशील शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, तो वो सदन की कार्यवाही से उन्हें हटाने के लिए आदेश दे सकता है। अगर आप सांसद हैं तो सदन में किसी पर झांसा देने का आरोप नहीं लगा सकते हैं। स्पीकर पर दोहरे दिमाग, डबल स्टैंडर्ड, आलसी, घटिया या उपद्रवी होने का आरोप नहीं लगा सकते हैं। कोई भी सांसद सदन में किसी दूसरे सांसद के खिलाफ कट्टरपंथी या एक्सट्रीमिस्ट और डाकू जैसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। विपक्ष को सरकार को अंधी-गूंगी कहने का अधिकार भी नहीं है। इसकी जगह सरकार के खिलाफ अली बाबा और 40 चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी सांसद को अजायबघर भेजने की सलाह देना भी असंसदीय है। अनपढ़ सांसद के लिए अंगूठा छाप जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल करने की मनाही है।

परिवारवादी पार्टियों के नेताओं का सामंतवादी रवैया और रहन-सहन दूसरी पीढ़ी आते-आते आम लोगों को खटकने लगता है। चूंकि भाजपा परिवारवाद को मुख्य राजनीतिक विमर्श के रूप में स्थापित करने में कामयाब रही है इसलिए परिवारवादी राजनीति के पैरोकार उसके बचाव में सक्रिय हो गए हैं। जब बुराई में अच्छाई दिखाने की कोशिश होने लगे तो समझिए कि तर्क और ताकत दोनों ही नहीं बचे हैं।

खतरे में परिवारवाद की राजनीति

भाजपा ने अगले लोकसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया है। यह बदलाव पार्टी का नए भौगोलिक क्षेत्रों में विस्तार करने के लिए है। भाजपा को लग रहा है कि वंचित वर्ग को अपने साथ जोड़ने, सामाजिक समीकरण बिठाने और सुशासन पर अपनी पहचान स्थापित करने में वह कामयाब रही है। इसके अलावा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मुद्दे पर भी अब उसे चुनौती देने की स्थिति में कोई दल नहीं है। अब पार्टी की चुनौती परिवारवादी क्षेत्रीय दल हैं। इन्हें पराजित किए बिना भाजपा सही मायने में राष्ट्रीय पार्टी नहीं बन पाएगी।

दक्षिण के चार में से 3 राज्यों, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, तेलंगाना और पूरब के बंगाल, बिहार एवं ओडिशा में से 5 राज्यों में उसकी न तो कभी सरकार बनी और न ही वह सरकार बनाने के आसपास पहुंची। बिहार में वह सत्ता में साझीदार तो रही, लेकिन कभी अपना मुख्यमंत्री नहीं बनवा पाई। ये सभी राज्य ऐसे हैं जहां भाषाई और क्षेत्रीय अस्मिता बाकी सब मुद्दों पर भारी पड़ते हैं। भाजपा के जो कोर मुद्दे हैं, उनके जरिये वह जहां तक पहुंच सकती थी, लगभग पहुंच चुकी है। इससे आगे विस्तार के लिए उसे नए रास्ते, नए नारे और नई रणनीति की जरूरत है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का एक विशेष गुण है। इसका चाणक्य नीति से सीधा संबंध है। यह है कछुए की तरह व्यवहार करना। जैसे कछुआ अपने शरीर का उतना ही अंग बाहर निकालता है, जितनी जरूरत होती है। उसी तरह मोदी अपनी रणनीति के बारे में उतना ही बताते हैं, जितनी उस समय की जरूरत होती है। वह पिछले 8 साल से परिवारवाद की बात कर रहे हैं। अपनी पार्टी में इसे रोकने का लगभग सफल प्रयास कर चुके हैं। भाजपा में वह जो कर रहे हैं, वह परिवारवाद को रोकने की कोशिश है, लेकिन समस्या की जड़ परिवारवाद नहीं वंशवाद है। हालांकि यह भी सच है कि वंशवाद की शुरुआत होती परिवारवाद से ही है। भाजपा में वंशवाद नहीं है। कोई ऐसा नेता नहीं है जो यह दावा कर सके कि उसके पद पर उसके परिवार का ही कोई व्यक्ति आएगा।

मोदी की योजना वास्तव में कांग्रेस के जरिये क्षेत्रीय दलों तक पहुंचने की है। इसी रणनीति के तहत राजनीति में परिवारवाद पर पहली बार नियोजित तरीके से हमला करने का फैसला हुआ है। हैदराबाद में भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यह केंद्रीय मुद्दा रहा। क्षेत्रीय दलों को घेरने के लिए भाजपा की यह नई रणनीति है। 8 साल तक कांग्रेस मुक्त भारत अभियान चलाने के बाद भाजपा की निगाह अब क्षेत्रीय दलों पर है। क्षेत्रीय दलों का सबसे कमजोर पक्ष है उनका परिवार, पर मोदी जो कर और कह रहे हैं वह केवल परिवार तक सीमित नहीं है।

परिवारवादी पार्टियों के नेताओं का सामंतवादी रवैया और रहन-सहन दूसरी पीढ़ी आते-आते आम लोगों को खटकने लगता है। बात इतनी ही होती तो शायद गनीमत होती, लेकिन मामला उससे आगे चला गया है। मोदी और भाजपा को समझ में आ गया है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, सुशासन (केंद्रीय योजनाओं का असर) और सामाजिक गठजोड़ एक सीमा के बाद असर नहीं डालता। मतदाता लोकसभा चुनाव में दूसरी तरह मतदान करता है और वह मोदी के साथ खड़ा नजर आता है, पर विधानसभा चुनावों में भाजपा का मत प्रतिशत गिर जाता है।

मोदी की परिवारवाद विरोधी मुहिम में कई और मुद्दे समाहित हैं। यह महज दुर्योग नहीं अधिकतर परिवारवादी पार्टियां और उनके नेता भ्रष्ट भी हैं और छद्म पंथनिरपेक्ष भी। इसे यूं भी कह सकते हैं कि ये हिंदू विरोध और मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इसलिए इनके

बाल ठाकरे जैसा नहीं...

उद्धव ठाकरे कुछ भी दावा करें, उनमें बाल ठाकरे जैसा करिश्मा नहीं। एक समय राज ठाकरे को बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी माना जाता था, लेकिन शायद बाला साहब पुत्र मोह का शिकार हो गए। भले ही उद्धव ठाकरे के समर्थक उन्हें एक काबिल मुख्यमंत्री का दर्जा देते रहे हों, लेकिन वह एक कमजोर मुख्यमंत्री के रूप में ही सामने आए। वह कुछ अपने स्वभाव और कुछ कोविड महामारी के चलते न केवल आम जनता, बल्कि अपने विधायकों और मंत्रियों से भी कट गए। रही-सही कसर इस धारणा ने पूरी कर दी कि महाविकास आघाड़ी सरकार तो शरद पवार चला रहे हैं। यह धारणा इसलिए और मजबूत हुई, क्योंकि उद्धव ठाकरे कई मुद्दों पर शिवसेना की विचारधारा के विपरीत जाकर काम और बात करते नजर आए। उनके पास यह अवसर था कि वह बहुमत परीक्षण का सामना करते और उसी दौरान अपनी बात सदन में कहते, लेकिन उन्होंने फेसबुक लाइव का सहारा लिया और उसी समय त्यागपत्र देने की घोषणा की। ऐसा करके उन्होंने अपने को एक कमजोर नेता ही साबित किया। अब ठाकरे परिवार के लिए बीएमसी का चुनाव जीतना कठिन हो सकता है, जहां उसका एक लंबे समय से दबदबा है।

खिलाफ जनता को खड़ा करने में आज के बदले माहौल में थोड़ी आसानी दिख रही है। तुष्टीकरण की राजनीति को मतदाता बार-बार नकार रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों के लिए इसका बचाव करना दिन-प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। स्थिति यह हो गई है कि मुस्लिम वोटों के दम पर दशकों तक राजनीति करने और राज करने वाली पार्टियां अब मुसलमानों के मुद्दे उठाने से बचने लगी हैं। वे चाहती हैं कि मुसलमान चुपचाप उन्हें वोट दे दें। कम से कम चुनाव के समय तो अपना मुंह बंद ही रखें। इस सबके बावजूद भाजपा की राह इतनी आसान नहीं है। उसके सामने दो समस्याएं और आती हैं। एक तो इन राज्यों में पार्टी जमीनी संगठन का ढांचा तैयार करना और दूसरा राज्य स्तर का नेतृत्व उभारना।

परिवारवाद पर प्रधानमंत्री के हमले का असर इतनी जल्दी दिखना शुरू हो जाएगा, इसकी उम्मीद नहीं थी। चंद्रशेखर राव की बौखलाहट तो कुछ दिनों से दिख रही है। नई आवाज उठी है तमिलनाडु से। द्रमुक नेता ए. राजा ने भाजपा और केंद्र सरकार को चेतावनी दी है वे उनकी पार्टी को अलग तमिल देश की मांग के लिए मजबूर न करें। उधर बंगाल से ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है। एक बात तो स्वीकार करना पड़ेगी कि परिवारवाद के खिलाफ देश में माहौल बन गया है। चूंकि भाजपा परिवारवाद को मुख्य राजनीतिक विमर्श के रूप में स्थापित करने में कामयाब रही है इसलिए परिवारवादी राजनीति के पैरोकार सक्रिय हो गए हैं। तर्क दिया जा रहा है कि मोदी के परिवार मुक्त राजनीति के नारे का वास्तविक लक्ष्य विपक्ष मुक्त राजनीति है। एक तरह से परिवारवाद के समर्थकों ने परोक्ष रूप से मान लिया है इस देश में विपक्ष को बचाने के लिए परिवारवाद को बचाना जरूरी है। जब बुराई में अच्छाई दिखाने की कोशिश होने लगे तो समझिए कि तर्क और ताकत, दोनों ही नहीं बचे हैं।

आखिरकार शिवसेना में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुआ विद्रोह उद्धव ठाकरे सरकार को ले डूबा। शिवसेना के अधिसंख्य विधायकों के शिंदे के साथ खड़े हो जाने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया था कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार के दिन पूरे हो गए हैं। कायदे से उद्धव ठाकरे को पहले ही त्यागपत्र दे देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने यह काम तब किया, जब राज्यपाल के बहुमत परीक्षण के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया। महाविकास आघाड़ी सरकार के पतन के बाद जब यह माना जा रहा था कि शिंदे गुट के समर्थन से देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तब भाजपा ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला कर सबको चौंका दिया।

लोग तब भी चौंके, जब देवेंद्र फडणवीस ने यह कहा कि वह सरकार में शामिल नहीं होंगे। बाद में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की पहल से वह उपमुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हुए। जो लोग इस पर उनका उपहास उड़ा रहे हैं, उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनकी ही राजनीतिक सक्रियता से महाविकास आघाड़ी सरकार का पतन हुआ और वह भविष्य में फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, क्योंकि एक तो उम्र उनके साथ है और दूसरे, यह मानना सही नहीं होगा कि उपमुख्यमंत्री बनने से उनका कद कम हुआ है। ऐसा लगता है कि भाजपा नेतृत्व ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला अंतिम क्षणों में लिया, ताकि उद्धव ठाकरे को यह कहकर लोगों की हमदर्दी हासिल करने का अवसर न मिले कि भाजपा ने सत्ता पाने के लिए उनके रूप में एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने का काम किया। खुद को असली शिवसेना बता रहे एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे के लिए यह सिद्ध करना और कठिन होगा कि केवल वही बाल ठाकरे की विरासत का नेतृत्व कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जिस तरह खुद को शिवसेना की विचारधारा का नेतृत्व करने वाला बता रहे हैं और उन्होंने जिस प्रकार अपनी प्रोफाइल फोटो में खुद को बाल ठाकरे के अनुयायी के रूप में दिखाया, उसके बाद उद्धव ठाकरे को अपने बचे-खुचे समर्थकों को अपने साथ बनाए रखना कठिन हो सकता है। इसमें कोई दोराय नहीं हो सकती कि महाविकास आघाड़ी सरकार एक बेमेल सरकार थी। शिवसेना ने पिछला विधानसभा भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था। उसे 56 सीटें मिली थीं और भाजपा को 105। कायदे से दोनों दलों को मिलकर सरकार बनानी चाहिए थी, लेकिन शिवसेना अचानक इस पर अड़ गई कि मुख्यमंत्री का पद उसे दिया जाए।

भाजपा इसके लिए तैयार नहीं हुई और इसका कारण यह था कि उसने ऐसा कोई वादा नहीं किया था कि मुख्यमंत्री पद शिवसेना को दिया जाएगा। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने के लिए इतना लालायित थे कि उन्होंने समान विचारधारा वाली भाजपा से नाता तोड़कर उस कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हाथ मिला लिया, जो उसकी कट्टर विरोधी थीं और उसे हर समय सांप्रदायिक बताती रहती थीं। चूंकि महाविकास आघाड़ी हर लिहाज से एक अस्वाभाविक गठबंधन था, इसलिए उसे न केवल विफल होना था, बल्कि यह भी तय था कि उसकी कीमत शिवसेना को चुकानी पड़ेगी। आखिरकार ऐसा ही हुआ। एकनाथ शिंदे के साथ शिवसेना के 40 के करीब विधायक खड़े हो गए तो इसीलिए, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि उद्धव ठाकरे की रीति-नीति शिवसेना का बेड़ा गर्क कर रही है। इन विधायकों के लिए अपने लोगों के इस सवाल का जवाब देना भी मुश्किल हो रहा था कि वे कांग्रेस और राकांपा के साथ सत्ता में भागीदारी कैसे कर सकते हैं?

● इन्द्र कुमार

महाराष्ट्र में दो परिवारवादी पार्टियों को पटखनी

भाजपा को हाल में महाराष्ट्र में दो परिवारवादी पार्टियों को पटखनी देने में सफलता मिली है। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी, दोनों को गहरा राजनीतिक आघात लगा है। इनके लिए इससे संभलना बहुत कठिन है, खासतौर से उद्धव ठाकरे की शिवसेना के लिए। आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में शिवसेना को ठाकरे परिवार में मुक्ति मिल जाए तो आश्चर्य नहीं। महाराष्ट्र के बाद भाजपा की नजर अब तेलंगाना पर है। इस साल के आखिर में गुजरात और हिमाचल में विधानसभा चुनाव हैं। इसके बावजूद भाजपा ने अपनी कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में की। भाजपा को साफ दिखाई दे रहा है कि तेलंगाना में के. चंद्रशेखर राव की सरकार और परिवार, दोनों के प्रति आम लोगों में नाराजगी बढ़ रही है।

विवादों वाली उद्धव सरकार!

महाराष्ट्र में महाविकास अघाडी सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे को जिस सबसे बड़े विवाद का सामना करना पड़ा, वो सुशांत सिंह राजपूत केस था। 14 जून 2020 को सुशांत की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी। उनसे पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की भी संदिग्ध मौत हुई थी। सुशांत की मौत के बाद आरोप लगा कि उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने ही दिशा की हत्या कराई है। उसके बाद सुशांत को भी मरवा दिया है। इतना ही नहीं सुशांत केस को दबाने का भी उद्धव ठाकरे पर आरोप लगा था। इस मामले की वजह से ठाकरे परिवार की रातों की नींद हराम हो गई थी। बहुत मुश्किलों और लंबे समय के बाद ये मामला शांत हुआ था।

सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत सबसे ज्यादा मुखर थीं। उन्होंने उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे का नाम लेकर उन पर निशाना साधा था। महाराष्ट्र में चाहे किसी भी तरह की घटना हो, कंगना उसे लेकर उद्धव को घेरने से कभी पीछे नहीं रहती थीं। यही वजह है कि शिवसेना भी उनके खिलाफ आक्रामक हो गई थीं। मुंबई नगर निगम ने उनका दफ्तर तोड़ दिया। इसकी वजह से उनका करोड़ों का नुकसान हुआ था। उस वक्त कंगना ने कहा था, उद्धव ठाकरे तुझे क्या लगता है तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बदला ले लिया है। आज मेरा घर टूटा है कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सुशांत सिंह राजपूत केस की वजह से ही उद्धव सरकार और अर्नब गोस्वामी के बीच विवाद हुआ था। उस वक्त अर्नब का कहना था कि सुशांत की हत्या हुई है। इसमें उद्धव ठाकरे का परिवार शामिल है। सरकार कातिलों को बचा रही है। इसे लेकर वो अपने चैनल पर लगातार प्रोग्राम कर रहे थे। सीधे उद्धव ठाकरे और उस वक्त के मुंबई पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह का नाम लेकर उनको चुनौती दिया करते थे। इसके बाद अचानक मुंबई पुलिस ने 53 साल के एक इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के मामले में अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। इस मामले को लेकर पूरे देश में बहुत हंगामा हुआ था। सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा जमकर फूटा था। हालांकि, बाद में अर्नब को जमानत मिल गई थी।

साल 2019 में महाराष्ट्र के पालघर में दो साधुओं समेत तीन लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। तीनों एक साथी के अंतिम संस्कार में शामिल होने कांदिवली से सूरत जा रहे थे। रास्ते में गड़चिनचले के पास वन विभाग के एक गार्ड ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद वह गांव के रास्ते गुजरात जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी दौरान गांव में अफवाह फैला दी गई कि ये लोग चोर हैं। भीड़ ने इन्हें पीटना शुरू कर दिया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे देश में इस मामले ने तूल पकड़ लिया था। इसमें वारदात के दौरान कुछ पुलिसवाले भी वहां खड़े हुए नजर आए थे। ऐसे में कहा गया कि पुलिस की मिलीभगत की वजह से जानबूझकर साधुओं की हत्या कराई गई है।

उद्धव सरकार में गृहमंत्री रहे अनिल देशमुख और मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के बीच हुआ विवाद भी बहुत चर्चित रहा था। परमबीर ने देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि देशमुख ने कुछ चुनिंदा पुलिस अधिकारियों से रेस्टोरेंट और बार से प्रति महीने 100 करोड़ रुपए लेने को कहा था। देशमुख ने इन आरोपों को गलत बताया था लेकिन बाद में उन्हें अपने पद से हटना पड़ा था। इसके बाद प्रर्वतन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में देशमुख को गिरफ्तार कर लिया था। इस केस के तार बाद में एंटीलिया कांड से भी जुड़े थे। इसके मुख्य किरदारों में अनिल देशमुख, परमबीर सिंह और सचिन बझे का नाम सामने आया था। सचिन वझे को उद्धव का खास माना जाता था।

25 फरवरी, 2021 को दक्षिण मुंबई के पैडर रोड स्थित मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया से 300 मीटर की दूरी पर विस्फोटक से भरी एक स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी मिली थी। इसमें 20 जिलेटिन की छड़ें और एक धमकी भरा लेटर बरामद हुआ था। लेटर जैश-उल-हिंद नामक आतंकी संगठन की तरफ से था, जिसमें अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इस तरह अंबानी परिवार को भयभीत करके उनसे पैसों उगाही करने की कोशिश की गई थी। 5 मार्च, 2021 को इसके मालिक मनसुख हिरेन का शव रेती बंदर की खाड़ी से बरामद हुआ था। इस मामले की साजिश रचने के आरोप में बाद में मुंबई पुलिस के अफसर सचिन वझे, प्रदीप शर्मा और सुनील माने का नाम सामने आया था। केस एनआईए को सौंपा गया था। एनआईए ने अपनी जांच के बाद इन अफसरों को दोषी पाया, जिसके बाद इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। सचिन वझे को उद्धव सरकार बनने के बाद बहाल किया गया था।

बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अक्टूबर, 2021 में मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया गया था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर समीर वानखेड़े की अगुवाई में एनसीबी की टीम ने क्रूज पर छापा मारकर आर्यन खान सहित 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। इस मामले में कहा गया था कि आर्यन के पास से ड्रग्स मिला था। उन्होंने क्रूज पर ड्रग्स का सेवन भी किया था। कई अदालती सुनवाई, बहुत सारे ड्रामे और लंबी हिरासत के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 25 दिन बाद जमानत दी थी। उसके 7 महीनों बाद उनको क्लीन चिट भी मिल गई। इस मामले में भी उद्धव ठाकरे सरकार को लोगों ने घेरा था। उनके सरकार के ही एक मंत्री ने आर्यन के बचाव में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।

● **बिन्दु माथुर**

नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन

महाराष्ट्र के कैबिनेट मिनिस्टर नवाब मलिक को अंडरवर्ल्ड के साथ कनेक्शन की वजह से ईडी ने गिरफ्तार किया था। नवाब मलिक पर आरोप था कि साल 1993 बम धमाकों के दो आरोपियों से मुंबई के कुर्ला इलाके में तीन एकड़ जमीन खरीदी थी। यह जमीन कौड़ियों के दाम पर खरीदी गई थी। ईडी ने उसी दौरान दाउद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर को महाराष्ट्र की ठाणे जेल से गिरफ्तार किया था। पूछताछ के दौरान कासकर ने भी नवाब मलिक का नाम लिया था। इसके बाद ईडी की टीम मलिक से लंबी पूछताछ की थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। नवाब मलिक उद्धव सरकार के कद्दावर मंत्री माने जाते थे। उनकी गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र सरकार की बहुत किरकिरी हुई थी।

बोतल से निकला निकम्मा का जिन्न

राजस्थान में जबसे कांग्रेस की सरकार बनी है, तभी से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच खींचतान मची हुई है। आलम यह है कि कई बार गहलोत पायलट को भला-बुरा कह जाते हैं। लेकिन पायलट जिस तरह अपना अपमान बर्दाश्त कर रहे हैं, उसके कुछ अलग संदेश हैं।

राजस्थान की राजनीति में नाकारा-निकम्मा नाम का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है। इससे प्रदेश की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। प्रदेश में अशोक गहलोत और सचिन पायलट की गुटबाजी में बंटी कांग्रेस में ऐसी बयानबाजी अब आम हो चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर इस शब्द के जरिए सचिन पायलट और गजेंद्र सिंह शेखावत पर निशाना साधा है।

पिछले दिनों सचिन पायलट ने गहलोत को अनुभवी, वरिष्ठ और पितातुल्य बताकर अपना बड़प्पन दिखाया था। बदले में गहलोत ने नाकारा-निकम्मा बच्चे को पिता द्वारा डांटने के लहजे में कहने की कहावत का हवाला देकर पायलट को झगड़ने वाला बच्चा करार दे दिया है। हांलाकि गहलोत ने अपने संबोधन के दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को भी निशाने पर लिया है। लेकिन गहलोत के इस बयान को सीधे तौर पर पायलट से जोड़कर देखा जा रहा है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गत दिनों कांग्रेस विधायकों और नेताओं को संबोधित करते हुए नाकारा और निकम्मा शब्द की व्याख्या की। इस दौरान गहलोत ने कहा कि निकम्मा का मतलब क्या होता है। पड़ोस में बच्चे कोई झगड़ा करते हैं। बच्चे आपस में झगड़ते हैं तो एक पड़ोसी दूसरे के घर जाता है। बच्चे की शिकायत करता है। तब उस बच्चे के पिता उसे कहते हैं कि अभी बुलाकर डांटता हूं। वह नाकारा-निकम्मा है। यही तो कहते हैं, ये तो कहावतें होती हैं। वह अपने बच्चे के लिए कहता है। गहलोत ने कहा- यही बात मैं कहता हूं कि निकम्मा-नाकारा है। इसका मतलब यही होता है कि यह बच्चा है। इसने गलती कर दी होगी। मैं इसे डांटता हूं। कई बार प्रेम से भी कहा जाता है। अब मैं प्रेम से भी कहूं तो कई लोग बुरा मान जाते हैं। उसका मैं क्या कर सकता हूं।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जयपुर के बिड़ला सभागार में **ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट** को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के मसले पर 13 जिलों के विधायकों और कांग्रेस नेताओं के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्र में जलशक्ति मंत्री हैं। बावजूद इसके राजस्थान को उसका हक नहीं दिलवा पा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री शेखावत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए हुए वादे को भूल गए। शेखावत अब्सेंट माइंड हैं। उन्होंने राजस्थान के लिए कुछ नहीं किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने ईडी की कार्रवाई का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा को भी निशाने पर लिया।

सचिन पायलट ने दो साल पहले राजस्थान का उपमुख्यमंत्री रहते हुए जुलाई के महीने में अपने समर्थित विधायकों को साथ लेकर गहलोत सरकार को अस्थिर करने की कोशिश थी। वे अपने साथी विधायकों के गुड़गांव के मानेसर में एक होटल में चले गए थे। इसके बाद प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार संकट में आ गई थी। खुद अशोक गहलोत को अपने विधायकों की जयपुर के एक होटल में बाड़ेबंदी करनी पड़ी थी। इस दौरान गहलोत ने अपने एक बयान के दौरान पायलट को नाकारा-निकम्मा बताते हुए बागी करार दिया था। उनका उपमुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष पद छीन लिया गया था। बावजूद इसके पायलट ने पार्टी नहीं छोड़ी।

जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी के पायलट के धैर्य की तारीफ को गहलोत खेमा पचा नहीं पा रहा है। इसलिए मुख्यमंत्री गहलोत रणनीति के तहत पायलट को निशाने पर ले रहे हैं। सत्तारूढ़ पार्टी में छिड़ी लड़ाई का यह पटाक्षेप नहीं है। सत्ता पर वर्चस्व को लेकर संघर्ष अभी रुकेगा नहीं। सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी का आंतरिक संघर्ष जारी रहेगा। सचिन पायलट गाहे-बगाहे सरकार रिपीट नहीं होने की बात कहकर गहलोत पर निशाना साधते रहे हैं।

राजस्थान की राजनीति में भाजपा नेताओं की सचिन पायलट से हमदर्दी चर्चा बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ सचिन पायलट की मुक्तकंठ से तारीफ कर रहे हैं। शेखावत ने कहा- पायलट से चूक हो गई वरना राजस्थान में मध्यप्रदेश जैसे हालात होते। सचिन पायलट सम्मानीय नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा- पायलट जमीन से जुड़े नेता हैं। जनाधार रखते हैं। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने भी सचिन पायलट की तारीफ की है। भाजपा नेताओं की पायलट के प्रति हमदर्दी चर्चा में है। हालांकि, सचिन पायलट ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर पलटवार किया है। पायलट ने कहा कि हमसे चूक हो गई। जोधपुर की जनता से 2024 के लोकसभा चुनावों में चूक नहीं होगी।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

राजस्थान में 2023 में होंगे चुनाव

राजस्थान में 2023 के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी चाहते हैं कि गहलोत और पायलट मिलकर पार्टी के लिए काम करें। राहुल गांधी ने पिछले दिनों सचिन पायलट की तारीफ कर संकेत दिया कि पायलट को विधानसभा चुनाव से पहले बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। साल 2020 में पायलट गुट की बगावत के बाद से ही पायलट बिना किसी पद के हैं। हालांकि, पायलट समर्थक विधायकों को एडजस्ट किया गया है। सचिन पायलट राहुल गांधी की तारीफ के बाद पूरी तरह से आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पार्टी की मांगों की अनदेखी से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ सकता है।

नेता-नौकरशाह का टकराव...

योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में दूसरी बार चुनी गई उप्र सरकार अपने 100 दिन पूरे होने तथा अपने वायदों पर खरा उतरने का जश्न मना रही थी, उसी दिन शाम को वायरल हुए एक पत्र ने रंग में भंग डाल दिया। यह पत्र उपमुख्यमंत्री व स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के मंत्री ब्रजेश पाठक ने अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को लिखा था। पत्र में आरोप था कि अपर मुख्य सचिव ने उनसे सलाह लिए बिना तथा तबादला नीति का अनुपालन किए बिना ही स्वास्थ्य विभाग में तमाम तबादले कर डाले हैं।

सरकार के 100 दिन पूरे होने पर लिखे गए इस गोपनीय पत्र के सार्वजनिक होने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह केवल विभाग में मंत्री और अधिकारी की आपसी खींचतान का मामला है, या फिर कोई राजनीतिक कारण है! लखनऊ के राजनीतिक गलियारों में सवाल यह भी उठ रहा है कि आखिर ऐसा कौनसा पहाड़ टूट रहा था कि राज्य सरकार के 100 दिन की प्रेस कांफ्रेंस होने के तुरंत बाद ही उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उसे सार्वजनिक करने की हड़बड़ी हो गई?

दरअसल, यह पहला वाकया नहीं है जब विभागीय मंत्री और उसके अधिकारी के बीच ठनी है। अतीत में भी कल्याण सिंह की भाजपा की सरकार में इसी तरह तत्कालीन नगर विकास मंत्री लालजी टंडन और लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रभात कुमार के बीच ठन गई थी, लेकिन तब पत्र लिखने की नौबत नहीं आई थी। बात 1997 की है। भाजपा-बसपा गठबंधन सरकार गिर जाने के बाद छोटे दलों के सहयोग से कल्याण सिंह उप्र के मुख्यमंत्री बने थे और लालजी टंडन नगर विकास मंत्री थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से सांसद और देश के प्रधानमंत्री थे। लखनऊ का सांसद होने के नाते अटलजी का पूरा काम लालजी टंडन ही संभालते थे। वह अटलजी के विशेष कृपापात्र थे।

कल्याण सिंह भले मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनसे तनिक भी कम हनक लालजी टंडन की नहीं थी। कल्याण सिंह कतई नहीं चाहते थे कि उनके समानांतर **सत्ता का संचालन** हो इसलिए कल्याण सिंह ने लखनऊ विकास प्राधिकरण में अपने एक खास चहेते अधिकारी प्रभात कुमार को वीसी बनाकर तैनात कर दिया। प्रभात कुमार की पहचान ईमानदार, लेकिन झक्की अधिकारी की थी। टंडन ने लखनऊ में अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिया। प्रभात कुमार ने टंडनजी के फैसले पर अमल किया, लेकिन अतिक्रमण हटाओ अभियान की गिरफ्त में उन लोगों को भी ले लिया जो कथित तौर पर लालजी टंडन के करीबी थे। इस घटना के बाद प्रभात कुमार एवं टंडन के बीच ठन गई। टंडन ने कल्याण सिंह से कुछ कहने की बजाय अटलजी के माध्यम से दबाव बनाकर प्रभात कुमार को एलडीए से विदा करा दिया। इस घटना के बाद से ही अटलजी और कल्याण सिंह के बीच दूरियां बढ़ने का सिलसिला शुरू हुआ, जो कल्याण सिंह के भाजपा छोड़ने पर जाकर खत्म हुआ।

दरअसल, लगभग हर पार्टी की सरकार में मंत्री एवं विभागीय अधिकारी के बीच तनातनी के मामले रहे हैं, लेकिन वह कभी इस तरह पत्र लिखकर सार्वजनिक नहीं किए गए। पिछली योगी सरकार में तत्कालीन ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा एवं आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार में ठन चुकी है। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओमप्रकाश राजभर एवं गाजीपुर के डीएम संजय खत्री के बीच भी विवाद सुर्खियों में आया था। अभी हाल में ही राज्यमंत्री एवं हस्तिनापुर से विधायक दिनेश खटीक का स्थानीय थानेदार से एक मामले को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने की धमकी देते हुए सुरक्षा वापस कर दी थी। अगर उपमुख्यमंत्री एवं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा के बीच तनातनी की बात की जाए तो इसकी नींव योगी सरकार के पहले ही कार्यकाल में पड़ चुकी थी, जब विधि एवं न्याय मंत्री के पद पर रहते हुए ब्रजेश पाठक ने कोरोनाकाल में चिकित्सा सुविधाओं पर सवाल उठाते हुए तत्कालीन अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद को लेकर सवाल उठाया था तथा पत्र लिखा था। इस पत्र से अपर मुख्य सचिव के साथ योगी सरकार की भी किरकिरी हुई थी।

अब इसे राजनीति कहें या संयोग कि भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल में ब्रजेश पाठक प्रमोशन पाकर उपमुख्यमंत्री बने और उनको वही स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग मिल गया, जिस पर वह सवालिया निशान उठा चुके थे। मंत्री बनते ही ब्रजेश पाठक ने छापेमारी शुरू कर दी। अपने साथ कैमरा टीम लेकर ब्रजेश पाठक छापेमारी से यह स्थापित करने लगे कि स्वास्थ्य विभाग एवं इससे जुड़े लोग लापरवाह और नाकारा हैं। मंत्री तो सब बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी भ्रष्ट हैं। ब्रजेश पाठक की इस कार्रवाई का दोतरफा असर हुआ। एक तरफ जहां योगी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य सुविधाओं के दुरुस्त होने के दावों की हवा निकली, वहीं दूसरी ओर अपर मुख्य सचिव पर भी उंगली उठी। इस बीच 16 करोड़ की दवा खराब होने की खबर पर छापेमारी ने अमित मोहन प्रसाद की छवि को गहरा धक्का दिया।

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

सरकार के लिए टकराव नुकसानदेह

ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर भी मंत्रियों-विधायकों में लंबे समय से नाराजगी रही है, क्योंकि योगी ने स्पष्ट कर रखा है कि अगर व्यक्तिगत मामला ना हो तो विधायक एवं कार्यकर्ता ट्रांसफर-पोस्टिंग के मसले से दूर रहें। ऐसा इसलिए कि पूर्ववर्ती सरकारों में ट्रांसफर-पोस्टिंग एवं वसूली के कई मामलों में सरकार की किरकिरी हो चुकी है। किसी भी सरकार के लिए ऐसा टकराव नुकसानदेह होता है क्योंकि ऐसे टकराव का सीधा प्रभाव सरकार के कामकाज पर पड़ता है। उम्मीद करनी चाहिए कि उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे टकराव को रोकने के लिए अवश्य ही कोई उचित कदम उठाएंगे ताकि भाजपा में फिर कोई अटल-कल्याण प्रकरण न दोहराया जाए।

नीतीश का डोलता मन

महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास

नीतीश का हालिया रुख यह बतलाता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में अपनी सियासी जमीन खोने के बावजूद वे न सिर्फ विपक्ष बल्कि अपनी सहयोगी पार्टी की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं पर अंकुश लगाने के प्रयास में लगे हैं। कुछ दिनों पूर्व तक यह मुश्किल दिख रहा था जब राजनीतिक हलकों में यह खबर फैली या फैलाई गई कि नीतीश बिहार की राजनीति छोड़कर केंद्र में जाना चाहते हैं। यह भी कयास लगाए जाने लगे कि नीतीश भाजपा को बिहार की सत्ता सौंपकर उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। स्वयं नीतीश ने भी यह कहकर इसे तूल दिया कि वे लोकतंत्र के चार सदनों (लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद) में से सिर्फ राज्यसभा के सदस्य नहीं बने हैं। यह भी अफवाह जोर से फैली कि नीतीश राज्यसभा के एक उपचुनाव सहित दो सीटों के लिए बिहार में होने वाले चुनाव में जदयू के प्रत्याशी बन सकते हैं। चुनाव राज्यसभा के जदयू सदस्य महेंद्र प्रसाद की मृत्यु और पार्टी के दूसरे सदस्य, केंद्रीय इस्पात मंत्री आरसीपी सिंह का 6 वर्ष का कार्यकाल जुलाई में समाप्त होने के कारण तय हुआ था। लेकिन, नीतीश ने 'किंग' महेंद्र की जगह अनिल हेगड़े और आरसीपी की जगह पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो को उम्मीदवार बनाकर यह जगजाहिर कर दिया कि उनका फिलहाल बिहार की राजनीति छोड़ने का कोई इरादा नहीं है।

राजनीति में समय से ज्यादा संख्याबल बलवान होता है, और कुछ मामलों में परिस्थितियां भी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संदर्भ में कुछ ऐसा ही लगता है। अमूमन किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में तीसरे स्थान पर आई पार्टी को सत्ता की बागडोर नहीं मिलती, वह भी तब जब उसकी गठबंधन के किसी अन्य दल को उससे अधिक सीट पर विजय मिली हो। और अगर कभी-कभार संयोगवश मिलती भी है तो अनिश्चितता के बादल सरकार के भविष्य पर मंडराते रहते हैं। लगातार दो बार अपनी पार्टी के सहयोगी दलों से पिछड़ने के बावजूद मुख्यमंत्री बनने वाले नीतीश के साथ कुछ ऐसा ही होने की आशंका थी।

नवंबर 2020 के चुनाव में जदयू को मात्र 43 सीटों पर जीत मिली, जो उसकी सहयोगी भाजपा से 21 सीटें कम थीं। 243-सदस्यीय सदन में राजद 75 सीटें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। 2005 में पंद्रह वर्ष के राजद शासन का अंत होने के बाद यह पहला मौका था जब एनडीए में जदयू भाजपा से पिछड़ गई थी। इसके बावजूद चुनाव पूर्व समझौते के मुताबिक नीतीश मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज तो हुए लेकिन इस बार उन्हें भाजपा के बदले स्वरूप से दो-चार होना था। गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका मिलने से प्रदेश में न सिर्फ भाजपा की महत्वाकांक्षाएं आसमान छूने लगीं, बल्कि राजनीतिक विश्लेषक यह भी आंकलन करने लगे कि नीतीश सरकार की चाबी मुख्यमंत्री के पास नहीं होगी। लेकिन, सरकार के बनने के लगभग 20 महीनों बाद नीतीश के लिए फिलहाल सुकून खोने का कोई कारण नहीं दिखता। इसके विपरीत, हाल के घटनाक्रम से तो प्रथमदृष्टया यही लगता है कि भाजपा के निरंतर बढ़ते प्रभुत्व के बावजूद उन्होंने अपने सहयोगी को ही बैकफुट पर ला दिया है। पिछले 1 जून को नीतीश ने **जाति जनगणना** के मुद्दे पर एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें भाजपा को भी इच्छा या अनिच्छा से शिरकत करनी पड़ी। इससे पहले प्रदेश भाजपा नेतृत्व ने स्पष्ट किया था कि पार्टी सिर्फ दो ही जाति (अमीर और गरीब) में विश्वास करती है। भाजपा की इस बदली रणनीति का मुख्य कारण था नीतीश और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव का इस मुद्दे पर एकमत होना।

राजनीतिक जानकारों के अनुसार, सर्वदलीय बैठक के पूर्व नीतीश और तेजस्वी प्रसाद यादव की इस मुद्दे पर अचानक मुलाकात और दोनों का एक-दूसरे की इफ्तार पार्टी में जाने-आने से भाजपा के लिए इस बैठक में जाने की मजबूरी हो गई। बिहार जैसे प्रदेश में, जहां जाति समीकरण अब भी चुनावी रणनीति का अभिन्न अंग हैं, पार्टी अपने आपको इस पहल के विरोधी के रूप में दिखाने का जोखिम नहीं मोल सकती थी, न ही जदयू और राजद को फिर से करीब लाने का। नीतीश के लिए यह दोहरे फायदे के अवसर के रूप में आया। इससे भाजपा को न सिर्फ जाति जनगणना पर अपना रुख स्पष्ट करना पड़ा, बल्कि राजद को भी इस मुद्दे पर अकेले राजनीतिक लाभ लेने से वंचित होना पड़ा।

गौरतलब है, राजद ने ही पूरे देश में जाति जनगणना की मांग सबसे पहले उठाई थी। लालू ने 2014 के लोकसभा चुनावों के पूर्व तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार द्वारा 2011 में कराए गए एक सर्वेक्षण की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की मांग की थी, ताकि विभिन्न जातियों की वर्तमान संख्या का पता चल सके। राजद प्रमुख ने कहा था कि 1931 में कराई गई अंतिम जाति जनगणना के समय से वंचित-पिछड़ी जातियों की संख्या बहुत बढ़ गई है और अब उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण और अन्य नीतियों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। बाद में नीतीश ने विधानसभा से सर्वसम्मति से जाति जनगणना का संकल्प पारित कराकर केंद्र को भेजा। पिछले वर्ष, नीतीश के नेतृत्व में बिहार का सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला, लेकिन केंद्र ने इस मामले में फिर कोई पहल नहीं की। इसके विपरीत, संसद में गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने घोषणा की कि केंद्र सरकार में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलावा कोई जातिगत जनगणना करने का प्रस्ताव नहीं है। हालांकि भाजपा नेताओं ने बाद में यह स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर जाति गणना कराने को स्वतंत्र हैं।

जाहिर है, नीतीश के लिए यह एक तीर से दो शिकार करने जैसा मौका था। आश्चर्य नहीं कि सर्वदलीय बैठक के एक सप्ताह के भीतर बिहार में जाति गणना करने की सरकारी पहल तेज कर दी गई। मुख्यमंत्री के अनुसार, अब न सिर्फ बिहार में रहने वालों की, बल्कि प्रदेश के बाहर रहने वाले बिहारियों की भी गणना होगी, चाहे वह किसी भी मजहब का हो। उन्होंने कहा कि अगड़ी जाति हो या बैकवर्ड, दलित हो या आदिवासी, सबकी आर्थिक स्थिति समेत पूरी जानकारी ली जाएगी। दरअसल, बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस गणना में रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलामानों के साथ-साथ ऐसे मुस्लिमों की गिनती करने पर आगाह किया है जो फॉरवर्ड से बैकवर्ड बन रहे हैं।

● **विनोद बक्सरी**

फिर जल उठी लंका

विदेशी कर्ज का बोझ पिछले 12 सालों से लगातार बढ़ रहा

श्रीलंका पर विदेशी कर्ज का बोझ पिछले 12 सालों से लगातार बढ़ रहा था। हालात ये हो गए कि जरूरी चीजों का आयात घटाना पड़ा। दवाओं, पेट्रोल-डीजल, गैस और खाद्य वस्तुओं की कमी होने लगी। श्रीलंकाई रुपए की कीमत तेजी से गिरने लगी। जनता का आक्रोश देखते हुए 2019 में राष्ट्रपति गोटबाया ने उन्हें लुभाने के लिए टैक्स कम करने शुरू कर दिए। इससे सरकार का राजस्व 2020 में 656 करोड़ डॉलर रह गया, 2017 में यह 1095 करोड़ डॉलर था। सबसे ज्यादा कमाई वाला श्रीलंका का पर्यटन उद्योग कई वजहों से खत्म होने लगा। आतंकवादी गतिविधियां बढ़ने लगीं। 2019 में तौहीद जमात नामक मुस्लिम संगठन ने ईस्टर पर चर्च में तीन बम विस्फोट करवाए, 260 निर्दोष नागरिकों की जान गई। इन घटनाओं से दुनियाभर से आने वाले करीब 25 प्रतिशत पर्यटकों ने यहां आना बंद कर दिया। उसके बाद कोरोनाकाल ने और तबाही मचाई और पर्यटन उद्योग पूरी तरह चौपट हो गया। दूसरी तरफ सत्ता पर कब्जे के खेल में राजपक्षे परिवार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस परिवार ने सभी प्रमुख पदों पर कब्जा कर लिया। महिंदा प्रधानमंत्री बने तो भाइयों में से गोटबाया को राष्ट्रपति, बासिल राजपक्षे को वित्तमंत्री, चामल राजपक्षे को सिंचाई व कृषि मंत्री व बेटे नामल राजपक्षे को खेल मंत्री बना दिया।

श्रीलंका में विद्रोह की लपटें पिछले तीन-चार महीनों से उठने लगी थीं। इस बार ये आग रामभक्त हनुमान की पूंछ ने नहीं लगाई है, क्योंकि अब न तो लंका सोने की रह गई है और न पीतल की। अब लंका को जलाने वाली खुद वहां की बदहाल, परेशान जनता है जो लंबे समय से भूख, गरीबी और भीषण महंगाई के बीच जीने को अभिशप्त हो गई है। महंगाई तो छोड़िए, वहां के सत्ताधारियों ने जनता के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। तमाम तीसरी दुनिया के देश कर्ज लेते हैं और तकरीबन हर देश अमेरिका, चीन, जापान, रूस जैसे विकसित देशों के कर्जजाल में फंसा हुआ है। पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो या फिर श्रीलंका, इन अमीर देशों की नजर में भारतीय उपमहाद्वीप के इन देशों को अपना आर्थिक गुलाम बनाने की प्रक्रिया बदस्तूर जारी रहती है। रिश्ते बेहतर बनाने और मदद के नाम पर यहां के हर सत्ताधारी विकास का हवाला देकर इस चक्रव्यूह में फंसते हैं और इसका खामियाजा उठाती है वहां की जनता। अगर आपका प्रबंधन ठीक नहीं है तो हालात श्रीलंका जैसे होने में वक्त नहीं लगता।

श्रीलंका में विद्रोह की लपटें पिछले तीन चार महीनों से उठने लगी थीं। हालात धीरे-धीरे बेकाबू होते जा रहे थे। चीन पर बढ़ती निर्भरता और कर्ज के भयानक जाल में बुरी तरह उलझ चुके इस देश के सत्ताधारियों ने आम जनता की सुध नहीं ली, उनकी रोजमर्रा की तकलीफों के बारे में नहीं सोचा और उन्हें भूखे, प्यासे और अंधेरे में रहने को मजबूर कर दिया। जाहिर है विद्रोह होना ही था। इसकी भूमिका महीनों से बन रही थी। गत दिनों इसकी पराकाष्ठा थी और आगे भी तब तक रहेगी जब तक कोई कारगर सरकार नहीं बन जाती। राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए रास्ते खोले गए हैं लेकिन इससे भी स्थितियां कितनी सुधरेंगी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो लोगों का जो गुस्सा है वो देश से भागे मौजूदा राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के खिलाफ है। उन्हें लगता है कि हमारे पैसों पर ये नेता अय्याशी कर रहे हैं और हम भूखे मरने को मजबूर हैं। इसी गुस्से का इजहार राष्ट्रपति निवास में घुसे हजारों लोगों की भीड़ ने किया... बेडरूम से लेकर, स्वीमिंग पूल तक और पूरे परिसर में इनका कब्जा यूं ही नहीं हो गया। प्रधानमंत्री आवास को यूं ही नहीं जला दिया गया। अप्रैल में भी ऐसे हिंसक प्रदर्शन हुए थे। राष्ट्रपति निवास के सामने आगजनी हुई थी। राजपक्षे ने डर कर अपना निवास छोड़ दिया था और कोलंबो फोर्ट में रहने लगे थे। कहा जा रहा है कि इस बार तो वो देश से ही भाग गए।

श्रीलंका में विद्रोह की ऐसी तस्वीरें पहले किसी ने नहीं देखी होंगी। शायद किसी देश में ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री निवास पर सीधे तौर पर कब्जा करने और आग लगाने की ऐसी कोशिश हुई हो। नेपाल में राजशाही के खात्मे के वक्त वहां के राजमहल पर कब्जा हुआ था और तत्कालीन राजा को भागना पड़ा था, लेकिन वहां भी ऐसा भयानक मंजर नहीं आया था। सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुक्मरानों पर हमले भी कई दफा हुए, हत्याएं हुईं, लेकिन जनता का ऐसा सैलाब कभी नहीं उमड़ा।

दुनिया के तमाम देश इस वक्त भीषण आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहे हैं, खासकर तीसरी दुनिया के देशों में हालात हमेशा से खराब रहे हैं। आंदोलन तो तमाम चलते ही रहे हैं, सत्ता पलटने की कोशिशें भी हुई हैं, लेकिन करीब सवा दो करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका में पिछले तीन महीनों से जो हालात बन रहे थे, शनिवार को उसकी परिणति कुछ इस तरह हुई कि दुनिया देखती रह गई। देश में बेहद गहरे होते आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका में 'गोटा गो होम' (गोतबया वापस जाओ) आंदोलन की जिस तरह तीन महीने पहले शुरुआत हुई, तब से ये लगातार पूरे देश में फैलता गया और इसका विस्तार इस कदर हुआ कि आम जनता ने सत्ताधारियों को पूरी आक्रामकता के साथ ये संदेश दे दिया कि जनता भूखी रहे, महंगाई में पिसती रहे, ऐसे में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऐशो आराम के साथ सरकार में नहीं बैठे रह सकते। जनता ने ही उन्हें सत्ता पर बैठाया है तो उस 'ऐशो आराम' की हकदार जनता भी है।

ये आंदोलन और इतने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन तो पहले से तय था, लेकिन उसका यह रूप होगा, यह नहीं सोचा गया था। हालांकि खुफिया तंत्र की जानकारियों की वजह से ही वक्त से पहले राष्ट्रपति गोटबया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग चुके थे, प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने भी खुद को बचाते हुए पद से इस्तीफा दे दिया और उन्हें इस संभावित हमले से बचाकर शाम को ही निकाल लिया गया। राष्ट्रपति राजपक्षे विदेश भाग गए हैं। लेकिन हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति को भी इस्तीफे की घोषणा करनी पड़ी।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

शानदार विरासत छोड़ गए शिंजो

शिंजो आबे सबसे लंबे समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे। गत दिनों एक राजनीतिक रैली को संबोधित करने के दौरान प्राणघातक हमले में उनका निधन हो गया। भारत भी उनके निधन से मर्माहत है। असल में भारत-जापान संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में आबे ने अहम भूमिका निभाई। उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए ही प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। आबे ने 28 अगस्त, 2020 को प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देते समय जापानी जनता से क्षमा मांगी थी कि वह अपने कार्यकाल का एक साल शेष रहते हुए पद छोड़ रहे हैं, जबकि अभी कई योजनाएं अमल में आने की प्रक्रिया में हैं। इसके बाद उन्होंने स्वयं को सार्वजनिक जीवन में सीमित कर लिया। इससे पहले जापानी राजनीति में आबे की वापसी असाधारण रही। 2007 में पहली बार प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने के बाद उन्हें दिसंबर 2012 में दुर्लभ उदाहरण के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। फिर 2014 और 2017 में उन्हें पुन: चुना गया। इससे जापान को वह स्थिरता और स्थायित्व मिला, जिसकी उसे सख्त आवश्यकता थी।

अपने शासनकाल में आबे ने कई बड़े लक्ष्य तय किए। जैसे कि दशकों पहले उत्तर कोरिया द्वारा अगवा किए गए जापानी नागरिकों की रिहाई के लिए प्योंययोंग से वार्ता, रूस के साथ सीमा विवाद को सुलझाना और युद्ध के बाद बने संविधान में संशोधन कर सेना को अधिक शक्तियां प्रदान करना। हालांकि ऐसे बड़े लक्ष्यों की पूर्ति करने में सफलता न मिलने के बावजूद उन्हें देश का कायाकल्प करने में जरूर कामयाबी मिली और वह घरेलू और विदेशी मोर्चे पर शानदार विरासत छोड़ गए। मामूली बदलाव करने वाले देश के रूप में पहचान बना चुके जापान में आबे आरंभ से ही यथास्थितिवाद से मुक्ति पाना चाहते थे। उन्होंने आबेनामिक्स की संकल्पना सामने रखी। यह अवधारणा नरम ब्याज दरों, सरकारी खर्च और ढांचागत सुधारों पर आधारित थी। इसने स्थिरता की शिकार अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान की। कम से कम आरंभ में इसका बहुत असर दिखा। कोविड महामारी से पहले आबे के दौर में ही जापानी अर्थव्यवस्था ने तेजी का सबसे लंबा दौर देखा।

शिंजो आबे ने घरेलू और बाहरी मोर्चे पर ऐसे अनेक प्रयास किए, जिन्हें करने का साहस उनके पहले किसी जापानी नेता ने नहीं दिखाया। उन्होंने विस्थापन और लैंगिक नीतियों से जुड़े मामलों में बदलाव करके जापान की सिकुड़ती श्रम शक्ति के मुद्दे का समाधान तलाशने का प्रयास किया। कामकाजी वर्ग में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए उन्होंने वूमेनिक्स जैसी पहल की। इसके अंतर्गत कुछ विशेष सरकारी अनुबंध किए गए, जिन्हें प्राप्त करने के लिए कंपनियों को अधिक महिला कर्मियों को भर्ती करना पड़ा। इसने रोजगार परिदृश्य पर महिलाओं की तस्वीर भले ही पूरी तरह न बदली हो, लेकिन इसने जापानी कारपोरेट सेक्टर में गहराई से समाए पूर्वाग्रहों पर आघात जरूर किया।

जापान की सुरक्षा नीति पर भी आबे की छाप उतनी ही महत्वपूर्ण रहेगी। उन्होंने धीरे-धीरे ही सही, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जापानी नजरिये को सामान्य बनाया। जापान की क्षेत्रीय और वैश्विक सामरिक भूमिका को लेकर उनका दृष्टिकोण स्पष्ट था। उन्होंने रक्षा व्यय बढ़ाया और सामरिक शक्ति के रूप में जापान के उभार को लेकर उनके मन में कोई संकोच या हिचक नहीं थी। उनकी सरकार ने संविधान की नए सिरे से व्याख्या करते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापानी सैन्य बलों को बाहर युद्ध करने की अनुमति का प्रविधान किया। इस अहम बदलाव ने जापान को क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्तर अधिक सक्रियता प्रदान की। अपने सहयोगियों के प्रति ट्रंप प्रशासन के चुनौतीपूर्ण रवैये के बावजूद आबे अमेरिका के साथ जापान के रिश्तों में संतुलन बनाए रखने में सफल रहे। क्षेत्रीय स्तर पर बात करें तो 2007 में भारतीय संसद को संबोधित करते हुए उन्होंने ही पहली बार हिंद-प्रशांत विजन का खाका सामने रखा था। यह एक ऐसा सामरिक दृष्टिकोण था, जिसके माध्यम से उनकी विदेश नीति ने भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी क्षेत्रीय शक्तियों संग संबंध प्रगाढ़ बनाने के साथ ही दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाया। भारतीयों के लिए आबे हमेशा खास नेता बने रहेंगे। भारत के प्रति उनका लगाव और भारत-जापान रिश्तों के लिए उनका नजरिया उनकी हिंद-प्रशांत नीति के मूल में था। पहले कार्यकाल में ही भारत का दौरा करने के बाद से उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री तीन बार भारत का दौरा करके द्विपक्षीय संबंधों को नया क्षितिज प्रदान किया।

● **कुमार विनोद**

भारतीय मूल के ऋषि सुनक बनेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री!

बोरिस जॉनसन का स्थान लेने वाले ब्रिटेन में सत्तारूढ़ 'कंजर्वेटिव पार्टी' के नए नेता और नए प्रधानमंत्री के नाम की घोषणा 5 सितंबर को की जाएगी। टोरी के नाम से जानी जाने वाली पार्टी के नेतृत्व के चुनाव के लिए जिम्मेदार निकाय ने यह जानकारी दी। नया प्रधानमंत्री निवर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का स्थान लेगा।

'1922 कमेटी ऑफ कंजर्वेटिव बैकबेंच' के सांसदों ने चुनाव के लिए टाइम टेबल और नियम तय किए। चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर शुरू और समाप्त भी होगी। प्रधानमंत्री पद के लिए अब तक 11 लोग दावेदारी पेश कर चुके हैं। ब्रिटेन के भारतीय मूल के पूर्व कैबिनेट मंत्री ऋषि सुनक और विदेश मंत्री लिज ट्रस कंजर्वेटिव पार्टी में बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में मुख्य दावेदार हैं। 1922 समिति के अध्यक्ष सर ग्राहम ब्रैडी ने कहा कि निश्चित ही 5 सितंबर को हमारे पास निष्कर्ष होगा और पार्टी का नया नेता निर्वाचित होगा और उसकी घोषणा की जाएगी। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और नए प्रधानमंत्री के तौर पर बोरिस जॉनसन की जगह लेने की दौड़ में विदेश मंत्री लिज ट्रस ने भी दावेदारी पेश कर दी। विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय (एफसीडीओ) में ट्रस के सहायक मंत्री रहे रहमान चिश्ती भी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल हो गए हैं। वह ब्रिटेन में जन्मे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद के बाद इस पद की स्पर्धा में शामिल हुए पाकिस्तानी मूल के दूसरे मंत्री हैं।

प्रताड़ना झेलने को विवश नारी

रूढ़िवादी मानसिकता ने बहुत कुछ बदल कर भी कुछ न बदलने जैसे हालात बना रखे हैं। यही वजह है कि घरेलू हिंसा का दंश भी समाज के हर वर्ग में देखने को मिलता है। सवाल है कि घर के हर सदस्य को भावनात्मक सहारा देने वाली महिलाएं क्यों अपने ही घर के भीतर हिंसक व्यवहार झेलने को विवश हैं? दुनिया का हर इंसान सम्मान और सुरक्षा की उम्मीद रखता है। पर अफसोस कि कई भारतीय महिलाओं को अपने घर में भी सम्मान का माहौल नहीं मिलता। देश की आबादी का आधा हिस्सा होने के बावजूद औरतें अपने ही घर में अपना मानवीय हक हासिल नहीं कर पाई हैं। घरेलू हिंसा जैसी अमानवीय स्थितियां अब भी उनके हिस्से आ रही हैं। शिक्षित और आत्मनिर्भर होती स्त्रियों के आंकड़े भी उन्हें मानवीय हक नहीं दिला पा रहे। इनमें सबसे ज्यादा तकलीफदेह है, छोटी-छोटी बातों पर उनके साथ होने वाली हिंसा। यह प्रताड़ना मानसिक और मनोवैज्ञानिक पीड़ा का सबब तो है ही, महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़ी तकलीफों का भी अहम कारण है।

हाल ही में जारी भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों के 707 जिलों के करीब साढ़े छह लाख घरों के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की गई रिपोर्ट इसी बात की पुष्टि करती है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की पांचवी रिपोर्ट में सामने आया है कि देश में आज भी लगभग एक तिहाई महिलाएं शारीरिक या यौन हिंसा की शिकार हैं। इस दुर्व्यवहार का दुखद पक्ष यह भी है कि शारीरिक और यौन हिंसा झेलने वाली महिलाओं की इतनी बड़ी आबादी में से सिर्फ 14 प्रतिशत महिलाएं मदद मांगने के लिए आगे आई हैं। जबकि पारिवारिक सुदृढ़ता के लिए दुनियाभर में मान पाने वाले हमारे देश में 18-49 साल की 30 प्रतिशत महिलाएं 15 साल से कम की उम्र से ही शारीरिक हिंसा का शिकार हुई हैं।

घरेलू हिंसा के सबसे ज्यादा आंकड़े विवाहत महिलाओं से जुड़े हैं, जबकि दांपत्य जीवन दो पीढ़ियों को जोड़ने वाले सेतु के समान होता है। बुजुर्गों की जिम्मेदारी से लेकर बच्चों के पालन-पोषण के दायित्व तक, पारिवारिक संसार से जुड़ा कितना कुछ दो इंसानों के साझे जीवन के साथ चलता है। ऐसे में घरेलू हिंसा की पीड़ा और प्रताड़ना झेलने वाली औरतों के लिए अपने ही घर में असुरक्षा और अपमान की स्थितियां बन जाती हैं। सहयोग और संबल देने वाले रिश्ते ही उनका जीना दुश्वार कर देते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक महिलाओं के खिलाफ शारीरिक हिंसा के 80 फीसदी से ज्यादा मामलों में अपराधी पति ही होता है। ऐसे में सवाल है कि यह कैसा साझा जीवन है, जिसमें सुरक्षा और सम्मान की जगह अपमान और प्रताड़ना का दंश भरा हो। इससे बढ़कर तकलीफ देह क्या होगा कि हमारे यहां सार्वजनिक जीवन में ही नहीं, व्यक्तिगत मामलों में भी स्त्रियां पीड़ादायी परिस्थितियों में जी रही हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की इस रिपोर्ट के अनुसार 32 प्रतिशत महिलाओं ने अपने जीवन में घरेलू हिंसा झेली है। 14 फीसदी महिलाएं भावनात्मक हिंसा का शिकार बनी हैं। 6 प्रतिशत महिलाएं यौन हिंसा का शिकार भी बनी हैं। पत्नी पर हाथ उठाना कई पुरुष अपना अधिकार समझते हैं। कई बार तो इस हद तक मारपीट की जाती है कि महिला की जान चली जाती है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य मंत्रालय का यह पांचवा सर्वेक्षण 2019 से 2021 के बीच किया गया है। यानी वैश्विक विपदा के दौर में भी औरतों के साथ दुर्व्यवहार जारी रहा। यहां तक कि जीवन के सबसे ज्यादा अनिश्चितता और पारिवारिक साथ की सबसे ज्यादा जरूरत वाले कोरोनाकाल में भी महिला आयोग को घरेलू हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी को लेकर समाज और सरकार को चेताना पड़ा। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन्स एसोसिएशन समेत 8 महिला अधिकार संगठनों ने भी कोरोना संक्रमण की घर तक सिमटी जिंदगी के दौर में महिलाओं के सामने आ रही ऐसी मुश्किलों पर गहरी चिंता जताई थी।

तकरीबन हर अध्ययन और व्यावहारिक रूप से दिखने वाली हर परिस्थिति, घरेलू हिंसा से जुड़े भयावह आंकड़े और कड़वी हकीकत को सामने लाते रहे हैं। कभी दहेज के नाम पर, तो कभी बिटिया को जन्म देने के उलाहने रूप में। मारपीट कर उनकी मान-मर्यादा पर आघात करना हमारी पारिवारिक व्यवस्था में आम बात है। अफसोस कि बरसों के साथ में भी यह दुर्व्यवहार जड़ें जमाए हुए है। यह सर्वेक्षण बताता है कि बढ़ती उम्र में भी घरेलू हिंसा के मामले देखने में आ रहे हैं। लंबा वैवाहिक जीवन बिता चुके दंपत्तियों में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले दोगुने हो गए हैं।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

बेहद चिंतनीय स्थिति

आंकड़े बताते हैं कि 18-19 साल के विवाहितों में ऐसे मामले 16.4 प्रतिशत हैं, तो 40-49 की उम्र वालों में यह आंकड़ा 32.1 पाया गया। यह बेहद चिंतनीय है कि घरेलू हिंसा के बढ़ते आंकड़ों के बावजूद मदद लेने के लिए आगे आने वाली महिलाओं की संख्या बहुत कम है। जबकि बीते कुछ बरसों में महिला शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता के आंकड़े तेजी से बढ़े हैं। स्त्री अधिकारों को लेकर सजगता लाने वाले अभियानों को गति मिली है। महिलाओं के सशक्तीकरण संबंधी जन-जागरूकता अभियानों की पहुंच बढ़ी है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि अपनों से मिले अपमानजनक और पीड़ादायी बर्ताव को झेलते रहने की वजह सामाजिक-पारिवारिक दबाव और रूढ़ सोच ही है। सर्वेक्षण में भी खुलासा हुआ है कि ऐसे दुखद हालात में भी सहायता लेने वाली महिलाओं की संख्या कम है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की तीसरी रिपोर्ट से अब तक बहुत बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। 2005-06 में यह दर 24 प्रतिशत थी, जो 2015-2017 में 14 फीसदी रह गई। 2019-21 के हालिया सर्वेक्षण में इस आंकड़े में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सहायता लेने वाली महिलाओं का आंकड़ा मात्र 14 फीसदी रहा, जबकि घरेलू हिंसा की शिकार औरतों के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है।

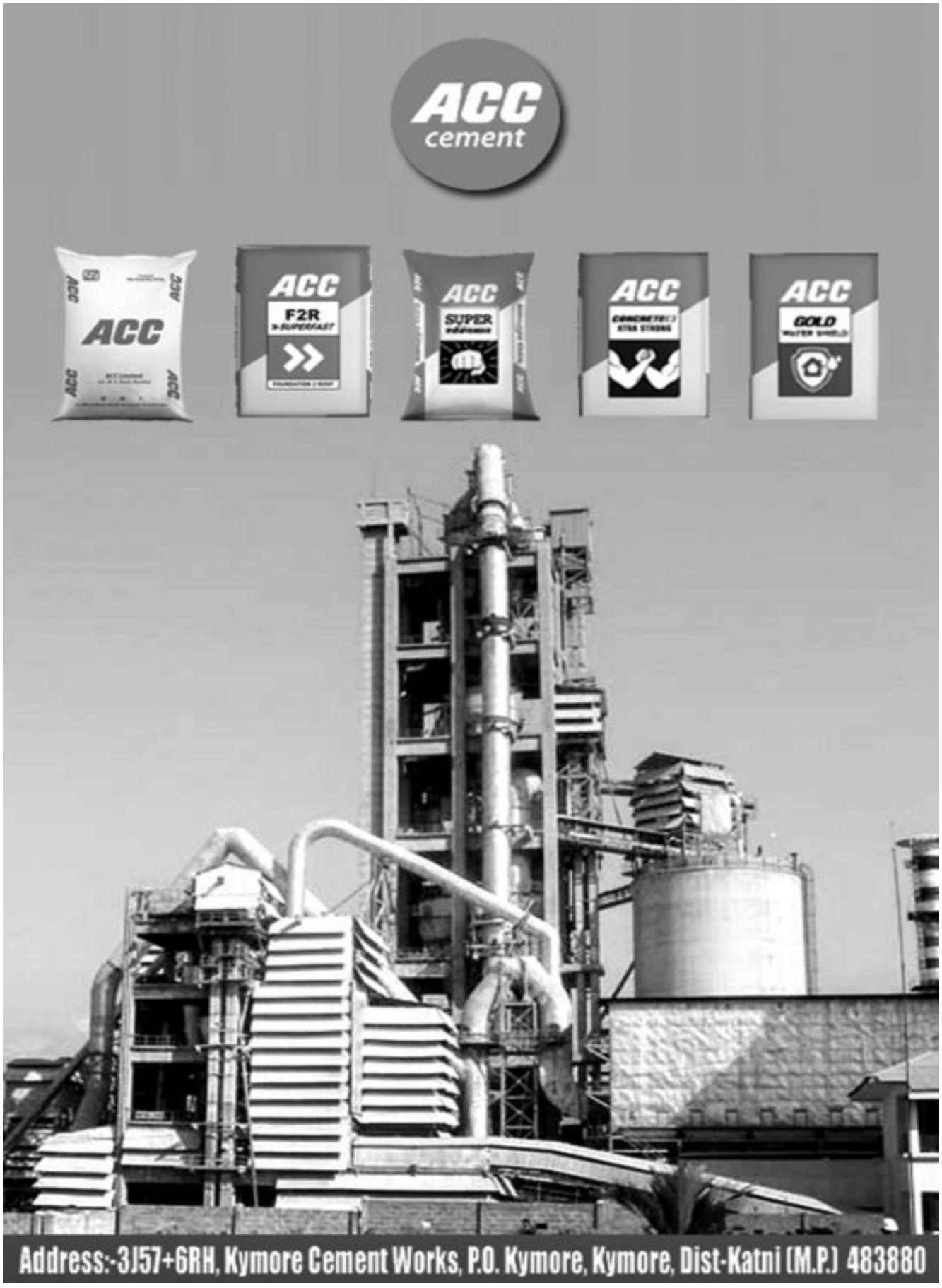

ACC
cement
ACC
ACC
F2R
ACC
SUPER
ACC
ACC
GOLD
Address:-3J57+6RH, Kymore Cement Works, P.O. Kymore, Kymore, Dist-Katni (M.P.) 483880

जीवन जीने का वैज्ञानिक तरीका है आश्रम व्यवस्था

जीवन का सबसे बड़ा द्वंद होता है मन और शरीर के बीच। जन्म के बाद से ही शरीर हर क्षण बदलता जाता है। शरीर शिशु से बालक, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध होता है। उसकी क्षमताएं युवा होने तक बढ़ती हैं, कुछ समय स्थिर रहती हैं फिर घटना शुरू होती हैं और अंत में मृत्यु के साथ ही सब कुछ प्रकृति के पंच तत्त्वों में समा जाता है। शरीर, प्रकृति का भाग है और उस पर नियंत्रण नहीं हो सकता। वह तो प्रकृति के नियमों के अनुसार क्षय होता जाएगा। इसके विपरीत मन पर समय का प्रभाव नहीं पड़ता। जीवन का हर चरण अपनी सार्थकता सिद्ध कर लेता है। इसलिए सनातन धर्म में जीवन को चार आश्रमों में बांटकर प्रत्येक आश्रम के लिए जीवनचर्या निर्धारित की गई है। प्रत्येक आश्रम अगले आश्रम की तैयारी का पड़ाव है। इस प्रकार यहां आश्रम का अर्थ है - जीवन की विशेष अवस्था या सोपान। यह जीवनशैली का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विभाजन है। मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर उसे 25-25 वर्ष के चार सोपानों में बांटा गया है। प्रथम 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थ आश्रम, 50 से 75 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम और 75 वर्ष के बाद संन्यास आश्रम।

ब्रह्मचर्य- यह उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता है तथा बलिष्ठ शरीर और विद्वान मस्तिष्क के निर्माण का सोपान है। इस समय विद्यार्थियों के जीवन में नीति, संस्कृति, सदाचार और अध्यात्म की नींव डाली जाती है। इस अवस्था में उसे गृहस्थाश्रम के अनुरूप कार्यक्षेत्र के कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है। ब्रह्मचारी, मन व इंद्रियों के संयमपूर्वक यम-नियमों का पालन करता है। मनुस्मृति में ब्रह्मचर्य आश्रम के कर्तव्यों को दो भागों में बांटा गया है- किए जाने वाले और न किए जाने वाले। नित्य किए जाने वाले कार्यों में स्नान, शारीरिक शुद्धता, देव, ऋषि और पितरों को तर्पण, देवताओं की पूजा, अग्निहोत्र आवश्यक हैं। निषेधात्मक कार्यों में विलास की वस्तुं, मादक पदार्थ, स्त्रियों का संग, काम, क्रोध और लोभ का आचरण, जुआ, गाली-गलौज और निंदा आदि शामिल हैं (मनुस्मृति 2.176-179)। वैदिक काल में इस समय क्षत्रियों को राजकाज, युद्ध और अस्त्र-शस्त्र चलाने की शिक्षा तो ब्राह्मणों को दर्शन, चिंतन-मनन और कर्मकाण्ड की शिक्षा दी जाती थी। इसके अलावा लौकिक कलाएं जैसे पशुपालन, कृषि आदि का अध्ययन भी कराया जाता था।

गृहस्थ- समावर्तन संस्कार के बाद ब्रह्मचारी विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। मनुस्मृति में कहा गया है कि चारों आश्रमों में गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है क्योंकि शेष तीन उसी पर निर्भर होते हैं। (मनुस्मृति 6.89)। महाभारत में भी इसे अन्य आश्रमों के लिए माता के समान बताया गया है (महा. अनु. 141/52-53) इसमें व्यक्ति धर्म की सीमाओं के अंतर्गत अर्थ और काम की प्राप्ति और उपभोग करता है। इस समय व्यक्ति में परस्पर प्रेम, आदर और उत्सर्ग की भावना का विकास होता है। मनुस्मृति की प्रसिद्ध उक्ति है- यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। एक अन्य ग्रंथ का श्लोक है- 'पति ध्यान रखे कि पत्नी प्रसन्न है, पत्नि ध्यान रखे कि पति प्रसन्न है।' तैत्तरीय उपनिषद् कहता है- 'गृहस्थ के पास कोई भी आश्रय मांगने आये तो उसे मना नहीं करना चाहिए। उसका सत्कार करना, भोजन देना गृहस्थ का कर्तव्य है।' इस आश्रम में संसार को विकसित करने का अवसर होता है।

घरेलू कामकाज में अनजाने में हुई हिंसा के निस्तार हेतु प्रतिदिन पंचमहायज्ञ करने का विधान है (मनुस्मृति 3.70)। यह हैं- ब्रह्मयज्ञ (शास्त्रों का पठन-पाठन), पितृयज्ञ (पिण्डदान, श्राद्ध-तर्पण आदि), देवयज्ञ (इष्टदेव की उपासना, पूजा और हवन), भूतयज्ञ (कृमि, कीट-पतंग, पशु और पक्षी आदि प्राणियों को भोजन देना) तथा मनुष्ययज्ञ (अतिथियों का सत्कार तथा भोजन कराना)। गृहस्थ को सत्य और न्यायपूर्वक धनोपार्जन करके, अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहिए, बच्चों को अच्छे नागरिक के संस्कार देना चाहिए और आत्मकल्याण के लिए देवताओं, पितरों और सभी प्राणियों की निष्कामभाव से सेवा करना चाहिए। यह सांसारिक भोगों का अनुभव कर उनसे ऊपर उठने का सोपान है।

वानप्रस्थ- यह सोपान 50 से 75 वर्ष तक का है। पीढ़ियों के विचारों और रहन-सहन में अंतर के कारण युवाओं के साथ रहने में वृद्धों को समस्या होती है। अत: यह सक्रिय जीवन से मुक्ति का सोपान है, संसार को धीरे-धीरे छोड़ने की प्रक्रिया है। गृहस्थ आश्रम में अर्थ और काम के अनुभव और उनकी निस्सारता को जानकर मोक्ष की ओर प्रस्थान का प्रारंभिक बिंदु है। इस समय सांसारिक कार्यों से उपराम लिया जाता है। इस आश्रम में घर छोड़कर, जंगल या एकांत में त्याग और वैराग्य का जीवन बिताते हुए नई पीढ़ी को मार्गदर्शन दिया जाता है। वानप्रस्थी को उचित है कि वह प्रतिदिन वेद आदि शास्त्रों का स्वाध्याय करे, इंद्रियों का दमन करे, सब में मैत्रीभाव रखे, मन को वश में रखे, सदा दान दे, पर प्रतिग्रह न ले तथा सब प्राणियों पर दया रखे (मनुस्मृति 6.8)।

संन्यास- 75 वर्ष की आयु के बाद यह आश्रम माना जाता है। इस आश्रम में अग्निहोत्र आदि सम्पूर्ण कर्मों का, सांसारिक रिश्ते-नातों का तथा शिखा-सूत्र का त्याग करके, प्राणिमात्र को अभय देकर संन्यास ग्रहण किया जाता है। इस समय वह घर-संसार छोड़ देता है। अब सारा संसार ही उसका होता है। व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के लिए पूर्ण समर्पित हो जाता है। इसका उद्देश्य है जीवन का अंतिम समय पूर्णत: त्याग, तपस्या और ध्यान में व्यतीत करना, आत्मानुभव करना और मृत्यु के बाद के जीवन में प्रवेश करने के लिए स्वैच्छा से तैयार रहना। जो महान् आत्मां पूर्व जन्मों के संस्कारों के कारण उच्च चेतना के साथ जन्म लेती हैं, जैसे शंकराचार्य, विवेकानन्द आदि, वे सांसारिक प्रलोभनों से असंपृक्त होते हैं व वे ही सीधे संन्यास के अधिकारी होते हैं। सामान्य लोगों की स्थिति भिन्न है। यदि आंतरिक पवित्रता विकसित नहीं हुई है तो ब्रह्मचर्य मानसिक रूप से बीमार कर देता है।

● **ओमप्रकाश श्रीवास्तव**

एक दो तीन चार

मेरे दफ्तर के एक सहयोगी पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मिल गए। उनके अब तक ग्यारह संस्करण धरती पर प्रकट हो चुके थे। बारहवें की तैयारी भी उन्होंने पूरी कर ली थी। वे अपनी बेगम और पूरी पलटन के साथ कहीं बाहर जा रहे थे। गाड़ी में चढ़ने से पहले उन्होंने तसल्ली के लिए गिनती शुरू की।

एक, दो, तीन, चार... दस! अरे, ग्यारहवां कहां रह गया। खोजबीन शुरू हुई, मगर सब व्यर्थ। मैंने भी प्लेटफार्म पर इधर-उधर ढूंढा, पर ग्यारहवें का कहीं अता-पता नहीं चला। अंत में उन्होंने यात्रा स्थगित कर दी और घर लौटने लगे। पुलिस में रिपोर्ट वगैरह लिखवाने में मदद के लिए उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया। दरवाजा खोलकर जब वे अंदर आए, तब देखा कि छोटे मियां तो घर में ही छूट गए थे।

मामला तो सुलझ गया परंतु मैं सोचने लगा कि पत्नियों को बच्चा पैदा करने वाली मशीन समझने लोगों के घरों में पहले बच्चे ने मां का दूध जी भर कर पिया नहीं कि दूसरा तैयार हो जाता है। फिर तीसरा और चौथा बच्चा होने तक तो मां के दूध का स्टाक खत्म हो जाता है। बाद वाले बच्चे मां के सूखे सीने से दूध नहीं बल्कि खून चूसते हैं। ऐसे में इन बच्चों के यौवन की इमारत कितनी मजबूत होगी यह सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

मैंने उनसे कहा- चलिए भाईजान, बच्चा तो मिल गया, अब इजाजत दीजिए। उन्होंने शुक्रिया अदा किया। मैं ज्योंहि उनके घर से बाहर निकला, सामने दीवार पर इश्तहार देखकर मुस्कुरा उठा। लिखा हुआ था-

छोटा परिवार-सुखी परिवार

- विनोद प्रसाद

दुखती रग

सुबह-सुबह न जाने रोहित किस बात से झुंझलाया हुआ था। शालिनी का भी मन अच्छा नहीं था। 'इस घर में कोई भी चीज जगह पर नहीं मिलती' रोहित बड़बड़ाया 'मेरी एक फाईल नहीं मिल रही है शालिनी तुम ने देखी है?' 'वहीं रखी होगी अपनी कोई सामान जगह पर नहीं रखते और मुझ पर चिल्लाते हैं' शालिनी ने झुंझलाकर कहा। 'सारा दिन क्या करती रहती हो घर पर थोड़ा ध्यान दिया करो' रोहित गुस्से में बोला। शालिनी को भी थोड़ा गुस्सा आ गया '22 साल से घर ही तो देख रही हूं, आप ने कभी एक रूमाल भी खुद से धोया है कभी किचन में खाना भी बनाया है सभी कुछ टाईम पर मिल जाता है इसलिए खुद को हाथ हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है।'

'तुम कभी मौका ही नहीं देती हो! कभी मायके जाती ही नहीं हो कि मैं सारे काम खुद से करूं!' रोहित का इतना कहना था कि शालिनी की आंखों में आंसू आ गए। शालिनी की मां नहीं थी! शादी से पहले उसकी मां का देहांत हो गया था। शालिनी के पिता को उससे कोई सरोकार न था। भाई-भाभियों की कौन पूछे। जब पिता ही पराए हो गए तो भाईयों से क्या गिला! इन 22 सालों में वो कभी भी अपने मायके नहीं गई, यहां तक कि उसके बच्चों ने कभी ननिहाल नहीं देखा! इसलिए जब कभी भी मां या मायके का जिक्र आता है शालिनी की आंखें नम हो जाती हैं। रोहित को अच्छी तरह शालिनी के दर्द का एहसास है मगर आज गुस्से में वो शालिनी की दुखती रग छेड़ गया।

- विभा कुमारी 'नीरजा'

श्रम सीकर प्यारा है...

श्रम करने वालों के आगे,
गहन तिमिर हारा है।

श्रमिकों के कारण ही तो देखो,
हरदम उजियारा है।।

खेत और खलिहानों में जो,
राष्ट्रप्रगति के वाहक हैं

अन्न उगाते, स्वेद बहाते,
जो सचमुच फलदायक हैं

श्रम के आगे सभी पराजित,
श्रम का जयकारा है।

श्रमिकों के कारण ही तो देखो,
हरदम उजियारा है।।

सड़कों, पांतों, जलयानों को,
जिन ने नित्य संवारा

यंत्रों के आधार बने जो,
हर बाधा को मारा

संघर्षों की आंधी खेले,
साहस जिन पर वारा है।

श्रमिकों के कारण ही तो देखो,
हरदम उजियारा है।।

ऊंचे भवनों की नींवें जो,
उत्पादन जिनसे है

हर गाड़ी, मोबाइल में जो,
अभिवादन जिनसे है

स्वेद बहा, लाता खुशहाली,
श्रमसीकर प्यारा है।

श्रमिकों के कारण ही तो देखो,
हरदम उजियारा है।।

- प्रो. (डॉ.) शरद नारायण खरे

खेलो इंडिया यूथ गेम

मप्र रचेगा इतिहास

खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पांचवा एडिशन मप्र में होगा। आधिकारिक रूप से कार्यक्रम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश सरकार और खेल एवं युवा कल्याण विभाग इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। विभाग का लक्ष्य है कि मप्र में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के आयोजन को ऐतिहासिक बनाया जाए। साथ ही इस आयोजन में मप्र के खिलाड़ियों का प्रदर्शन टॉप पर रहे, इसकी भी कोशिश की जा रही है।

गौरतलब है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स सबसे पहले दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसमें मप्र 13वें स्थान पर था। उसके बाद दूसरा आयोजन पुणे में हुआ था, वहां भी मप्र 13वें स्थान पर था। गुवाहाटी में आयोजित तीसरे आयोजन में प्रदेश का स्थान 12वां था। वहीं हरियाणा में आयोजित चौथे आयोजन में मप्र 8वें स्थान पर रहा। इसलिए खेल विभाग की कोशिश है कि मप्र में आयोजित होने वाले पांचवे गेम में प्रदेश का स्थान नंबर-1 पर रहे। इसके लिए हर स्तर पर तैयारी चल रही है।

जबसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स शुरू हुए हैं, मप्र की स्थिति साल दर साल बेहतर होती जा रही है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश में होने वाले गेम में मप्र बेहतर प्रदर्शन करेगा। गौरतलब है कि साल 2022-23 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए भोपाल में तैयारियां महीनों पहले से चल रही हैं। इसके लिए खेलो इंडिया योजना के प्रथम चरण में ग्राम नाथू बरखेड़ा में 20.42 हेक्टेयर भूमि पर अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना को भी स्वीकृति मंत्रिपरिषद ने दी है। पूरे आयोजन के लिए कुल 215 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया गया है।

खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि भोपाल अब एक खेल हब के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। खेलो इंडिया की मेजबानी न सिर्फ हमारे लिए हुनर दिखाने का मौका है बल्कि एक चुनौती भी है। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में ग्राम नाथू बरखेड़ा भोपाल में निर्मित होने वाले अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण एवं उपकरण पर लगभग 176.59 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यह कार्य तीन चरणों में किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के आयोजन शामिल हैं। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में लगभग 10 हजार क्षमता वाली फुटबॉल स्टेडियम, चार हजार क्षमता के दो हॉकी स्टेडियम, पार्किंग, इंटर्नल एवं सर्विस मार्ग, लैंडस्केपिंग, हॉर्टिकल्चर, सोलर पैनल, बाउंड्रीवॉल, गेट, गॉर्डरूम, सीवेज सिस्टम, स्ट्रीट लाइट आदि से लैस होगी।

मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने बताया कि दूसरे चरण में ग्राम नाथू बरखेड़ा भोपाल में इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और तीसरे चरण में क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। भोपाल में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 के लिए 23.38 करोड़ रुपए और अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण के बाद इसके संचालन और संधारण पर 15.56 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे।

गौरतलब है कि टोक्यो ओलंपिक के दौरान मप्र के कई खिलाड़ियों ने इस बार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए संसाधन विकसित करने पर जोर दे रही है। देश के खेल मानचित्र पर मप्र का नाम रौशन करने वाले खिलाड़ियों ने एक बार फिर गौरव बढ़ाया है। मप्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में ओवर चैम्पियनशिप ट्रॉफी जीतकर प्रदेश का गौरव प्रदान किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने खिलाड़ियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है।

हरियाणा के पंचकूला में खेले गए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मप्र के खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर ओवरऑल ट्रॉफी अपने नाम कर ली। इस वर्ष खेलो इंडिया गेम्स में देशज खेलों के साथ पहली बार मलखंभ को भी जोड़ा गया। मप्र की टीम 5 स्वर्ण, 5 रजत और दो कांस्य पदक सहित कुल 12 पदक जीत कर ओवरऑल चैम्पियन बनी।

मप्र में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए भोपाल के अलावा ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर और जबलपुर में भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में बड़े आयोजन करने की पर्याप्त व्यवस्था है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 10 हजार खिलाड़ी शामिल हुए थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि मप्र में होने वाले गेम में 11 हजार से अधिक खिलाड़ी शामिल होंगे। जल्द ही आयोजन की रूपरेखा तैयार करने के लिए बैठक आयोजित कर तैयारियों को गति दी जाएगी।

● आशीष नेमा

वर्ल्ड चैंपियन बनने की राह पर अमन विष्ट

मुक्केबाज अमन विष्ट अब वर्ल्ड चैंपियन बनने की राह पर हैं। चेन्नई में हुई यूथ नेशनल चैंपियनशिप में उनके पंच से बड़े-बड़े बाक्सर थर्रा उठे। मप्र अकादमी के अमन ने मप्र के लिए स्वर्ण पदक जीता। इसी के साथ उन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप में

अपना स्थान सुरक्षित कर लिया। इस प्रदर्शन के बल पर उन्हें स्पेन में होने वाली चैंपियनशिप के लिए इंडियन टीम में चुन लिया गया है। वर्ल्ड चैंपियनशिप नवंबर में आयोजित होगी। चेन्नई में 5वीं यूथ नेशनल चैंपियनशिप में मप्र अकादमी के खिलाड़ियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। टीम ने यहां एक गोल्ड, दो सिल्वर व तीन ब्रांज मेडल सहित कुल 6 पदक जीते। मप्र के लिए अमन विष्ट ने गोल्ड मेडल जीता। गोल्ड जीतने के साथ ही वे स्पेन वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए इंडियन टीम में स्थान पक्का करने में भी सफल हो गए हैं। मप्र बॉक्सिंग अकादमी के अमन ने 92 किलोभार वर्ग में शिरकत की। इसमें उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। अमन के अलावा अन्य खिलाड़ियों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। यहां 57 किग्रा भार वर्ग आनंद यादव ने सिल्वर मेडल जीता। उनके अलावा आदर्श कटारे ने भी 60 किग्रा भार वर्ग में सिल्वर मेडल जीता। अकादमी के आयुष यादव ने 75 किग्रा भार वर्ग में ब्रांज मेडल जीता।

500 से ज्यादा मुकाबले लड़े पर एक भी मैच नहीं हारे दारा सिंह

हाल ही में रुस्तम ए हिंद दारासिंह की 10वीं पुण्यतिथि मनाई गई। दारासिंह ने 500 से ज्यादा रेसलिंग मैच खेले और अपने जीवन में एक भी मैच नहीं हारा। उन्होंने 1952 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। दारा सिंह राज्यसभा में चुने जाने वाले पहले स्पोर्ट्समैन रहे हैं।

दारासिंह ने 10 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीती है। साथ ही उन्हें 1996 में हाल ऑफ फेम और 2018 में डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेम की ख्याति भी मिली है। 1954 में उन्हें रुस्तम ए हिंद और 1966 में रुस्तम ए पंजाब की ख्याति से भी नवाजा जा चुका है। रामानंद सागर के सीरियल रामायण और फिल्म बजरंगबली में दारासिंह ने हनुमान का रोल कर सभी का दिल जीत लिया था। द ग्रेट दारा सिंह के जीवन के कुछ दिलचस्प पहलु हैं जिन्होंने उन्हें इतना चर्चित बनाया। दारा सिंह का जन्म 19 जुलाई 1928 को एक जाट फैमिली में हुआ था। उनके पिता सूरत सिंह रंधावा और मां बलवंत कौर पंजाब में रहते थे। दारा सिंह का जब जन्म हुआ था उस समय भारत में ब्रिटिशर्स की हुकूमत थी। इन्हीं सब के बीच दारा पले बढ़े। दारासिंह के करियर की शुरुआत सिंगापुर से हुई। वो 19 साल की उम्र में ही सिंगापुर चले गए थे। वो वहां ड्रम मैन्युफैक्चरिंग मिल में काम करने लगे थे। यहीं से उन्होंने ग्रेट वर्ल्ड स्टेडियम के कोच हरनाम सिंह को गुरु मानकर रेसलिंग की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दी थी। कद-काठी में दारा सिंह काफी अच्छे हुआ करते थे। ऐसे में उन्हें उनके गुरु ने पहलवानी करने के लिए बढ़ावा दिया। दारा ने भी गुरु की बात मानी और पहलवानी की ट्रेनिंग लेने लगे।

कुछ साल चली ट्रेनिंग के बाद रेसलर दारा सिंह ने प्रोफेशनल रेसलिंग शुरू कर दी। सन् 1959 में वो सबसे पहले कॉमनवेल्थ चैंपियन बने। इसके बाद उन्होंने बिल वर्ना, फिरपो जबिस्जको, जॉन दा सिल्वा, रिकिडोजन, डैनी लिंच और स्की हाय ली जैसे धाकड़ पहलवानों को धूल चटाकर दुनिया भर में भारतीय पहलवानी का डंका बजाया। दारासिंह ने 500 से ज्यादा रेसलिंग मैच खेले और अपने जीवन में एक भी मैच नहीं हारा।

जब साई पल्लवी को लव लेटर के लिए पड़ी थी घर वालों से जबरदस्त मार

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस साई पल्लवी ने हाल ही में अपने टीनएज के दिनों का एक मजेदार किस्सा सुनाया। साई ने बताया कि जब वो स्कूल में थीं, तब उन्होंने स्कूल के एक लड़के को लव लेटर लिखा था। दरअसल साई फिल्म विराट पर्वम में लीड रोल में हैं। इस फिल्म में उनके किरदार का नाम वेन्नेला है और वो राणा दग्गुबती को लेटर देने के लिए जान जोखिम में डालती है।

साई से जब पूछा गया कि फिल्म में जो लेटर उन्होंने लिखे वो असली थे या सिर्फ एक्टिंग थी। इसके जवाब में साई ने कहा, फिल्म में तो मैंने डायरेक्टर के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से लेटर लिखे थे। हालांकि रियल लाइफ में, मैंने लेटर सिर्फ एक बार लिखा है। जब मैं छोटी थी तब मैंने एक लड़के को लेटर लिखा था। शायद उस वक्त मैं 7वीं क्लास में थीं। उसके बाद मैं पकड़ी गई और मेरे पेरेंट्स ने मेरी जबरदस्त पिटाई की थी। साई के बाद जब यही सवाल उनके को-स्टार राणा से किया गया तो उन्होंने कहा, एक लेटर तो उन्होंने अपने दिवंगत दादाजी दग्गुबाती रामानायडू को लिखा था। मैंने यह लेटर बचपन में लिखा था। इसके बाद मैंने किसी को लेटर नहीं लिखा।

बॉलीवुड इंडस्ट्री में आने के बाद लोगों ने कुब्रा सैत को किया था गुमराह

बॉलीवुड में काम करना और वहां की लाइफ इंजॉय करना हर किसी का सपना होता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कुब्रा सैत भी यही सपना लेकर आईं थी। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने इंडस्ट्री में अपने शुरुआती दिनों का याद किया और बताया कि लोगों ने उनके अंदर बॉलीवुड को लेकर निगेटिव बातें भर दी थीं। इंटरव्यू में बात करते हुए कुब्रा ने बताया, जब मैं इंडस्ट्री में नई थी तो लोग कहते थे कि बॉलीवुड काम करने के हिसाब से बेकार जगह है। यह पूरी इंडस्ट्री राक्षसों से भरी हुई है। कुछ लोगों ने तो मुझे अपनी बातों से इतना इनफ्लुएंस कर बैग पैक करवा कर घर वापस जाने को तैयरी करवा दी थी। कुब्रा आगे बताती हैं कि यह जगह आपको अच्छी कहानियां पहुंचाने का और दूसरों का जीवन

जीने का मौका देती है। कुब्रा ने अपनी बुक ओपन बुक-नॉट क्वाइट ए मेमॉयर के एक चैप्टर आई वास नॉट रेडी टू बी अ मदर में अपनी लाइफ के किस्से का खुलासा किया हैं। कुब्रा सैत ने बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत सलमान खान की फिल्म रेडी से की थी। फिल्म में कुब्रा का रोल काफी छोटा था। कुब्रा को पहचान नेटफ्लिक्स की सीरीज सेक्रेड गेम्स से मिली।

आदमी का सरल होना!

कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि 'क्या आदमी कभी सरल भी हो सकता है?' अपने अध्ययन काल में एक कहावत पढ़ी थी- 'कुत्ते की पूंछ बारह साल तक घूरे में गाड़ कर रखा गया, किंतु सीधी नहीं हुई।' चूंकि यह कहावत किसी कुत्ते, बिल्ली या चूहे ने नहीं बनाई, इसलिए इसे अन्योक्तिपरक रूप देने का श्रेय आदमी को ही देना चाहूंगा; क्योंकि आदमी अन्योक्तियां बुझाने का कुशल मर्मज्ञ है। वह क्यों अपनी ही प्रशंसा करके मियां मिट्ठू बनना पसंद करेगा? यह आदमी ही कुत्ते की वह हठीली, रपटीली, सर्पीली, बबाली और सवाली पूंछ है; जिसमें सीधी सरल होने का 'दुर्गुण' कभी नहीं आया। हजारों, लाखों क्या करोड़ों वर्षों से वह टेढ़ी की टेढ़ी ही है और भविष्य में भी टेढ़ी ही रहेगी।

आदिम युग का आदमी जितना सरल और सीधा था, उससे इस प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। अब यह तो वही बात हो गई न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इतने पहले के आदमी को कहां से खोजकर लाया जाए? जब ऐसा नहीं हो सकता तो हमें ही यह विचार करना होगा कि क्या आदमी भी कभी सरल हो सकता है?

जिसे भी देखते हैं, वह जो नहीं है, वही बनने के फेर में चकरघिन्नी बना हुआ जीवन बिता देता है। आदमी 'वह' नहीं रहना चाहता, जो वह वास्तव में है। वह इस प्रकार का मॉडल बनकर बाहर आना चाहता है कि चरण सिंह सरताज सिंह बनकर दिखाना चाहता है। गरीब सिंह ने अपना नाम धन सिंह रख लिया है। लक्ष्मी नाम धारी नारी भीख मांग रही है। इस 'महान' कार्य के लिए आजीवन खिट-खिट में खोया रहता है। कभी कपड़े, कभी आभूषण, शृंगार, भाषा, आचरण, चरित्र आदि के नकली आवरण पहनता, उतारता, बदलता, धोता, सुखाता रहता है। कोई उसकी असलियत न जान ले, बस इसी प्रयास में वह नंगा होता है, तो बंद हमाम में। वह अपनी पत्नी के सामने भी निरावरण नहीं होना चाहता। यही स्थिति नारियों की भी है, बल्कि कुछ ज्यादा भी हो तो शोध करने पर दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा! सरल होना तो उसने सीखा ही नहीं। इसी को उसने एक चिकना-चुपड़ा नाम दे रखा है- सभ्यता और संस्कार।

किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिनेता, नेता, धर्माधिकारी, रंगीले वेश धारी, कोई भी पुरुष या नारी; सभी में पाई गई ये पवित्र बीमारी। घर पर लड़के वालों को लड़की दिखाते समय पड़ोस से मांगा गया सोफा सेट, टी सेट, लेमन सेट, डिनर सेट आदि उसके अति विशिष्ट पन दिखाने के बहु रूप ही हैं। इस मामले में प्रकृति ने भी मनुष्य का सहयोग ही किया है। उसके लिए हजारों प्रकार के रंग निर्मित कर उसे सौंप दिए हैं कि लो मैंने तो तुम्हें जैसा बनाया था, बनाया ही था, अब तुम जितने टेढ़े बन सको, बन लो। क्योंकि अपना असली रूप दिखाने में तुम्हें शर्म आती है। जैसे जलेबी कभी सीधी सरल नहीं हो सकती, वैसे तुम इंसान भी कुत्ते की पूंछ के बाप हो, जो करोड़ों वर्षों में टेढ़े ही होते गए। और अभी भी क्रम जारी है। सरलता तुम्हारे लिए नंगापन है। इसलिए असलियत को बाहर नहीं आने देना चाहते। सरलता देखनी हो तो दिगम्बर मुनियों से पूछो। विशिष्टता और अति विशिष्टता प्रदर्शन का विशिष्ट ढोंग तुम्हारा विशेष गुण है।

संसार के इतिहास में यदि सरल व्यक्तियों का शोध किया जाए तो बिरले ही मिल सकेंगे। यदि किसी देश और धर्म के आलोक में ऐसे महामानवों की खोज की जाए तो उन्हें अंगुलियों पर भी आसानी से गिना जा सकता है; अन्यथा सारा संसार वक्रता का पर्याय बना हुआ अपने जलेबी पन का प्रतीक बना हुआ है। सर्प अपने बिल में भले सीधा घुसे किंतु आदमी अपने घर में भी सरल नहीं रह गया। देखने में उसके मुंह में भले एक ही जीभ हो, परंतु कार्य कुशलता में अनेक जीभों का स्वामी है। उसके पास मन भी एक नहीं, अनेक मन हैं। जो निरंतर चलायमान और परिवर्तनशील हैं। मनुष्य में सरलता को ढूंढ़ पाना तो इस प्रकार है, जिस प्रकार चील के घोंसले में मांस नहीं ढूंढ़ पाना।

आज के मानव की स्थिति पर यदि विचार किया जाए तो जो जितना असरल, वक्र, चक्राकार और बनावटी है, वह उतना ही 'महान' है। अब महानता के मानदंड सरलता, बच्चों जैसा भोलापन अथवा ज्ञान नहीं है, उसका प्रबल ढोंगी होना ही उसे देश, समाज और व्यक्ति की दृष्टि में महान बनाता है और वह इससे अपने घमंड में फूला नहीं समाता। वक्रता मानव की महानता का पर्याय बनती जा रही है। आज का मानव अपना काला इतिहास स्वयं लिख रहा है। सरलता जैसे पानी भरने विदा हो चुकी है। कलों का प्रतियोगी मानव कलों से भी दस कदम आगे चलने में योजनाबद्ध रूप से संलग्न है। द्वंद्व, फंद, धोखा, काइयांपन, पर उत्पीड़न, प्रदर्शन, (फोटो, वीडियो, टीवी, अखबार आदि माध्यम) आज के सरलता से कोसों दूर मानव के पर्याय हैं। किस विनाश की ओर अग्रसर हो रहा है वह, अनिश्चित भविष्य के गर्भ में है।

● **डॉ. भगवत स्वरूप 'शुभम'**

HEIDELBERGCEMENT

149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव

माईसेम सीमेन्ट की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता, मज़बूती और टिकाऊपन के पीछे उसके विश्व प्रख्यात उत्पादनकर्ता जर्मन कंपनी हाइडलबर्ग सीमेन्ट का 149 वर्षों का अतुलनीय अनुभव है जो 50 देशों में लगातार सुनिश्चित करता आया है कि उसके द्वारा उत्पादित सीमेन्ट का हर कण गुणवत्ता के मापदंड पर खरा उतरे ताकि उनका नारा "सर्वोत्तम निर्माण के लिए" उसके ग्राहकों का विश्वास पात्र बना रहे।

क्योंकि जब सीमेन्ट की गुणवत्ता का सवाल हो,
तो सीमेन्ट का हर कण मायने रखता है..

माईसेम सीमेन्ट | सर्वोत्तम निर्माण के लिए

सस्ता सीमेन्ट या बढ़िया सीमेन्ट - फैसला आपका

For all licenses and BIS standards please refer to www.bis.gov.in
HeidelbergCement India Limited CIN: L26942HR1958FLC042301 Phone +91-124-4503700 e-mail - assistance@mycem.in

SCIENCE HOUSE MEDICAL PVT. LTD.

D-10™ Hemoglobin Testing System

For HbA_{1c}, HbA_2 and HbF

Flexible
to solve more testing needs

Comprehensive
B-thalassemia and diabetes testing

Easy
for simple operation

Dependability is about more than keeping your laboratory running smoothly; It's about the quality diabetes care you support. That's why we developed the D-10™ System with reliability and efficiency in mind.

A simple, fully-automated solution, the D-10™ System Combines diabetes and B-thalassemia testing, enabling rapid HbA_{1c} or $HbA_2/F/A_{1c}$ testing using pripary tube sampling-so you can accomplish more in fewer steps, With the D-10™ System, It's easier to deliver a full picture of diabetes treatment progress-and that can be the difference for the people who count on you most.

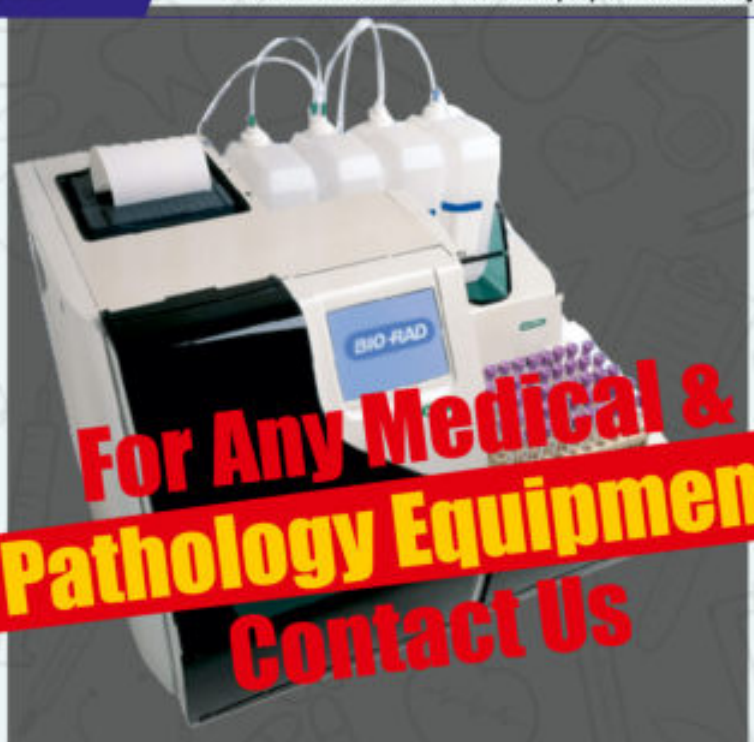

For Any Medical & Pathology Equipments Contact Us

C-65, Gautam Nagar, Near Chetak Bridge, Bhopal-462023
GST.No. : 23AAPCS9224G1Z5 Email : shbple@rediffmail.com
Phone : +91-0755-4241102, 4257687, Fax : +91-0755-4257687